राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 235

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

यह बजट भले ही अंतरिम हो और पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में आएगा लेकिन अंतरिम होते हुए भी बजट पूरी तरह से समावेशी और नवोन्मेषी है। इसमें युवाओं की आकांक्षाओं की उड़ान को ऊंचाई देने का प्रविधान है, तो गरीबों, महिलाओं और किसानों का भी ध्यान रखा गया है। **–नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

स्वर्णिम भारत का संकल्प

- वित्त मंत्री ने पेश किया मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट
- लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एजेंडा
- किसानों की आय बढ़ाने जैसे उपायों से राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास

₹47.66 लाख करोड़ का अंतरिम बजट

जयप्रकाश रंजन ● नई दिल्ली

- गरीब, महिलाएं, युवा, अन्नदाता को प्रमुख जातियां बताकर कहा- इनके कल्याण से ही देश बढ़ेगा
- यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने का एलान कर विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब

अगला आम चुनाव दस्तक दे रहा है। इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में लोकलुभावन वादों से पूरी तरह परहेज किया। मतदाताओं को प्रभावित करने वाली कोई बड़ी घोषणा नहीं की। उनका पूरा जोर मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल की आर्थिक उपलब्धियों को गिनाने के साथ वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा करने के भावी एजेंडे को पेश करने पर रहा। उन्होंने ढांचागत व्यवस्था में ज्यादा पैसे खर्च कर देश की आर्थिक विकास दर की रफ्तार तेज करने के आजमाए नुस्खे को और आगे बढ़ाया है। तिलहन, दलहन, दुग्ध, मछली पालन को प्रोत्साहित कर किसानों की आय बढ़ाने के उपाय कर राजनीतिक संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। बेरोजगारी, महंगाई पर सवाल उठा रहे विपक्ष को पूर्व यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने का एलान कर जवाब भी दिया।

लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट को पेश करते हुए वित्तमंत्री ने 58 मिनट के बजट भाषण में पिछले पांच बजटों को ही आगे बढ़ाने पर फोकस रखा। सरकार की तरफ से हाल के वर्षों में दिए गए सभी नारों का कहीं न कहीं इस्तेमाल किया। जातीय गणना के मुद्दे को हवा दे रहे विपक्ष के सामने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता को चार प्रमुख जातियों के तौर पर चिह्नित किया और साफ किया कि, इनके कल्याण से ही देश आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने अगली पीढ़ी के सुधार कार्यक्रम के भी संकेत दे दिए। इसका मुख्य सिद्धांत रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म होगा। वित्त मंत्री ने दो बार याद दिलाया कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोडमैप बना रही है। जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में रोडमैप पेश किया जाएगा। यह भी कहा, वर्ष 2014 तक देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। मोदी सरकार की नीतियां विकसित भारत का सपना साकार कर रही हैं। अगले पांच वर्ष अभूतपूर्व विकास के और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपनों के साकार करने का स्वर्णिम क्षण होगा।

राज्यों को बिना ब्याज मिलेंगे 75 हजार करोड़: राज्यों को 50 वर्षों के दौरान 75 हजार करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव कर वित्त मंत्री ने राज्यों से भेदभाव के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है। उक्त आवंटन का लाभ वही राज्य पाएंगे जो केंद्र की तरफ से दिए गए सुधार लागू करेंगे। बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया है, जो गत आम बजट के आवंटन से 11.1 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास दर सात प्रतिशत के करीब बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। नए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ही सस्ती दर पर या शून्य ब्याज पर कर्ज देने के लिए एक लाख करोड़ के फंड बनाने का एलान किया है, यह अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार की चुनौतियों को भी साधेगा।

बजट की अन्य प्रमुख बातें

- एक निश्चित अवधि में आम करदाताओं से पुराने बकाये की मांग को रद कर दिया गया है। एक करोड़ आयकरदाताओं को राहत मिलेगी
- राजकोषीय घाटे को अगले वर्ष घटा कर 5.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे वर्ष 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाना संभव दिखाई दे रहा है
- कुल राजस्व प्राप्तियां 30.80 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है

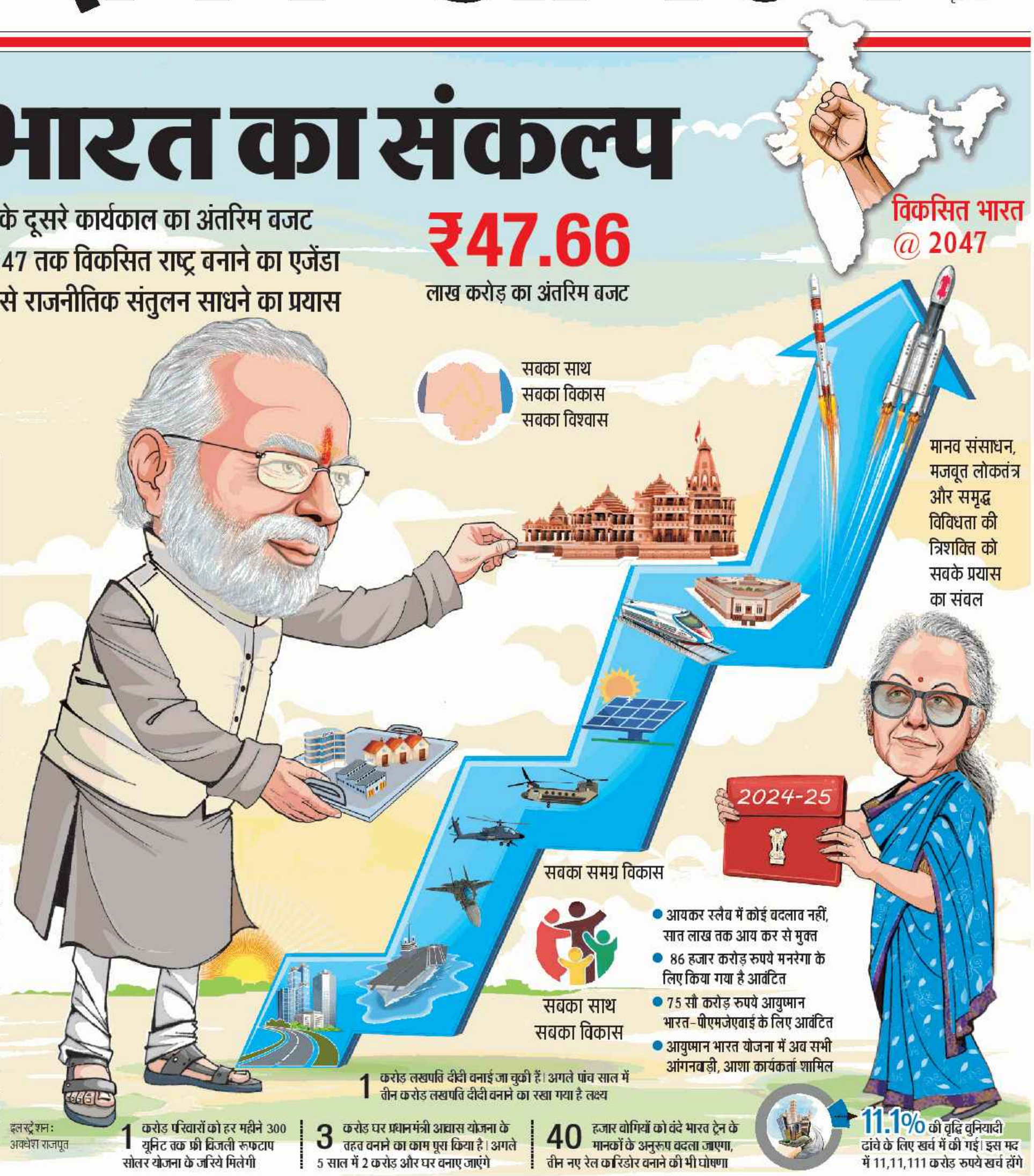

- आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सात लाख तक आय कर से मुक्त
- 86 हजार करोड़ रुपये मनरेगा के लिए किया गया है आवंटित
- 75 सौ करोड़ रुपये आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के लिए आवंटित
- आयुष्मान भारत योजना में अब सभी आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता शामिल

1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। अगले पांच साल में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का रखा गया है लक्ष्य

इलस्ट्रेशन: अवधेश राजपूत

1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली रूफटाप सोलर योजना के जरिये मिलेगी

3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने का काम पूरा किया है। अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे

40 हजार बोगियों को वंदे भारत ट्रेन के मानकों के अनुरूप बदला जाएगा, तीन नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा

11.1% की वृद्धि बुनियादी ढांचे के लिए खर्च में की गई। इस मद में 11,11,111 करोड़ रुपये खर्च होंगे

देश के भविष्य के निर्माण का बजट : मोदी

- कहा, विकसित भारत के नींव को मजबूत करने की गारंटी
- युवा, गरीब, महिला और किसान को बनाएगा सशक्त

हमने गरीबों के लिए तीन करोड़ से अधिक घर बनाए हैं। बजट में दो करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से दो करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर तीन करोड़ लखपति दीदी कर दिया गया है। आयुष्मान योजनाओं में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को भी शामिल कर लिया गया है। **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024-25 के अंतरिम बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया है। उनके अनुसार इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। उन्होंने कहा, यह विकसित भारत के चारों स्तंभों युवा, गरीब, महिला व किसान को सशक्त बनाएगा। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बजट को युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताते हुए उन्होंने इसके दो प्रविधानों का विशेष उल्लेख किया, जो रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक लाख करोड़ रुपये के फंड बनाने और स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार से संबंधित है। इनसे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए भी पूंजीगत खर्चे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये की व्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी ने बजट का बेहतरीन प्रविधान (स्वीट स्पाट) बताया है। उनके अनुसार इससे जहां एक ओर भारत में 21वीं सदी के आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण होगा, वहीं युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। सामान्य ट्रेनों में वंदे भारत की गुणवत्ता वाली 40 हजार बोगियां लगने से आरामदायक यात्रा का अवसर मिलेगा। पिछले 10 साल के दौरान अपनी सरकार की कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पहले एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं। उन्होंने गरीबों को घर, आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का जिक्र किया।

मध्यम वर्ग को मजबूत करने का भी इंतजाम

बजट सिर्फ युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों के सशक्तीकरण तक सीमित नहीं है। इसमें मध्यमवर्ग को मजबूत करने का इंतजाम भी किया गया है। पीएम के अनुसार, एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना से इन परिवारों को सिर्फ मुफ्त बिजली ही नहीं मिलेगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर वे 15-20 हजार रुपये सालाना की आमदनी भी कर सकेंगे। आयकर छूट योजना से मध्यम वर्ग के लगभग एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह से नैनो डीएपी व पीएम मत्स्य संपदा योजना के विस्तार, आत्मनिर्भर खाद्य तेल अभियान किसानों की आय बढ़ने के साथ ही खर्च भी कम करने का काम करेगा।

विशेष टिप्पणी: यह है सरकार के आत्मविश्वास की गूंज

आशुतोष झा ● नई दिल्ली

- जनता के भरोसे व 10 साल के ट्रैक रिकार्ड 'जो कहा सो पूरा किया' पर विश्वास जताने वाला बजट
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी वादों के बजाय सरकार के सोच और कामकाज पर खुद को केंद्रित रखा

विकास की राजनीति का यह एक नया उदाहरण है। जब सामने लगातार तीसरी पारी की लड़ाई का मैदान सज रहा हो और यह अपेक्षा हो कि लोकलुभावन घोषणाओं का तड़का लगेगा, तब नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से सामाजिक न्याय व समानता के अवसर पैदा करते हुए भविष्य के विकसित भारत का संकल्प दोहराना यह स्पष्ट करता है कि केंद्र में वापसी का विश्वास लबालब है। पीएम मोदी लोकलुभावन घोषणाओं के जरिये नहीं बल्कि अपने 10 साल के ट्रैक रिकार्ड 'जो कहा सो पूरा किया' के नारे के साथ ही जनता से समर्थन चाहते हैं। यह बजट वोट के लिए है ही नहीं, यह है कि अगले 15-20 वर्षों के भारत के लिए।

यह सच है कि विपक्षी गठबंधन का मनोबल ध्वस्त है और उनके पास सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन यह एक परंपरा रही है कि ऐन चुनाव के वक्त सरकार कुछ घोषणाएं करने से नहीं चूकती है। खुद मोदी सरकार ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं की थीं जिससे कि मतदाताओं को साधा जा सके। वह उसके कार्यकाल के पहले पांच साल थे और सरकार अपने सोच को जमीन पर पूरी तरह नहीं उतार पाई थी। 10 साल के स्थायी काल और तीव्र क्रियान्वयन के बाद केंद्र सरकार खुद को ऐसी स्थिति में देखती है जहां ट्रैक रिकार्ड बोलता है। इसीलिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणाओं के बजाय सरकार के सोच और 10 वर्षों के कामकाज पर खुद को केंद्रित रखा। साथ ही बहुत बारीकी से विपक्ष के उन बयानों का जवाब भी दे दिया जिसका आरोप लगाया जाता है। राहुल गांधी आजकल न्याय यात्रा पर निकले हैं और विपक्ष सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहा है। बजट भाषण में स्पष्ट कहा गया- सामाजिक न्याय का मतलब हमारी सरकार के लिए सभी लाभान्वितों तक कल्याणकारी योजनाएं पूरी तरह पहुंचाना है। कार्यरूप में यही धर्मनिरपेक्षता भी है जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और भाई-भतीजावाद पर लगाम लगती है। एक रिपोर्ट के अनुसार गत 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबी की मार से बाहर निकले हैं। ग्रामीण स्तर पर वह सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं जो पहले छोटे शहरों तक में उपलब्ध नहीं थीं। बीमारी हर साल पुनः गरीबी के चपेट में आने का बड़ा कारण रही है पर आयुष्मान योजना ने उस दशा में परिवर्तन ला दिया। सड़क, रेल और हवाई यातायात का परिदृश्य बदल रहा है। लोगों की औसत आय में वृद्धि हुई है। देश बदल रहा है और आने वाले समय में दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। देश की जनसंख्या और जनांकिकी बदल रही है। सरकार ने उस पर विचार के लिए उच्चाधिकारी समिति बनाने की बात कर यह संदेश दे दिया है कि उनका सोच पांच नहीं बल्कि अगले 15-20 वर्षों के लिए है।

डाटा शक्ति

2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए कुछ मानक होते हैं, जिनको पूरा करने के बाद ही कोई देश विकसित गिना जाता है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है।

जैकेट इनसाइड>>

इच्छा शक्ति

वित्त मंत्री ने सदन में लगभग मूरत की तरह बैठे विपक्ष की शांति के बीच लोकसभा में अपने अंतरिम बजट भाषण को पूरी गति से सरपट दौड़ाया। केवल मेजें थपथपाने तक सक्रिय रहे सत्तापक्ष को शांत चित विपक्ष ने सियासी गरमागरमी का कोई मौका नहीं दिया।

1

राष्ट्र शक्ति

बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की गई है। पिछले चार वर्षों में सरकार ने जिस तरह इस क्षेत्र में अपना खर्च बढ़ाया है, उससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है और नौकरियों के ढेरों अवसर उत्पन्न हुए हैं।

2

नारी शक्ति

बजट चुनावी नहीं है और लक्ष्य भी लोकसभा चुनाव नहीं दिखता, लेकिन मोदी सरकार के निर्णय इस संभावना को जरूर मजबूत करते नजर आते हैं कि मातृशक्ति उन्हें 'रिटर्न गिफ्ट' में चुनावी बल देने में संकोच नहीं करेगी।

3

जन शक्ति

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में दो करोड़ पक्के आवास और शहरों में नई आवासीय योजना पर आगे बढ़ने का एलान कर सरकार ने आम चुनाव के पहले बड़ी आबादी को आकर्षित किया है।

4

अर्थ शक्ति

लोगों की उम्मीद के विपरीत सरकार ने इनकम टैक्स से लेकर अप्रत्यक्ष कर किसी भी टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स देनदारी संबंधी नोटिस से प्रभावित लोगों को जरूर राहत दे दी।

5

संपादकीय

संतुलित एवं व्यावहारिक अंतरिम बजट: चुनावी लोकलुभावनवाद से मुक्त यह अंतरिम बजट महंगाई के दबाव को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला है। **धर्मकीर्ति जोशी** का आलेख।

विकसित भारत के संकल्प का प्रदर्शन: अंतरिम बजट यह तस्वीर पेश करता है कि सरकार किस तरह देश के भविष्य को संवार रही है। **विवेक देवराय** व **आदित्य सिन्हा** का आलेख।

6

****

डाटा शक्ति

आंकड़े सच बोलते हैं। इनमें छिपी होती है किसी भी देश या अर्थव्यवस्था के विकास की पूरी तस्वीर। जरूरत है इन्हें देखने की, परखने की और समझने की। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और दिखाते भी नहीं हैं। अंतरिम बजट 2024-25 के इन्हीं आंकड़ों की जुबानी आइये आपको बताते हैं विकसित भारत के संकल्प की कहानी।

दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 फरवरी, 2024

1,44,634 किलोमीटर लंबाई हो गई वित्त वर्ष 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो वित्त वर्ष 2015 में 97,991 किलोमीटर थी

महिला श्रम बल भागीदारी दर में इजाफा

विकसित भारत : सपनों की उड़ान में चुनौतियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। आम तौर पर बड़ी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) और ऊंची प्रति व्यक्ति आय वाले देश विकसित माने जाते हैं। भारत मौजूदा समय में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं प्रति व्यक्ति आय 2601 डालर है। 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें लंबा सफर तय करना है।

भारत की प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी

₹1,72,000 हो गई थी भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2022-23 तक

₹86,647 सालाना प्रति व्यक्ति आय थी भारत की वित्त वर्ष 2014-15 में

45,03,097 लाख करोड़ 2023-24

अमीर देशों में प्रति व्यक्ति आय

रुपये का हिसाब-किताब

सरकार की कमाई

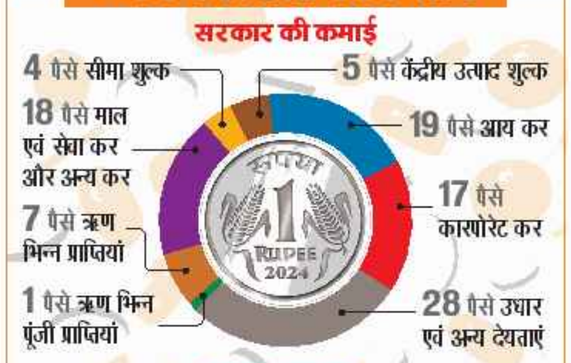

सरकार का खर्च

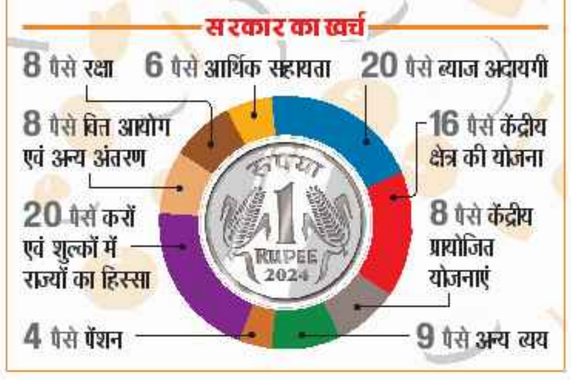

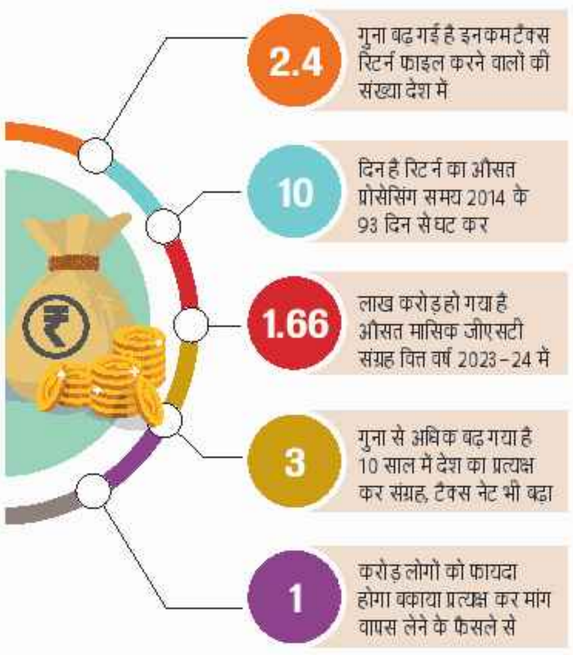

बजट एक नजर में

विषय	2022-23 वास्तविक	2023-24 अनुमान	2023-24 सं. अनुमान	2024-25 बजट अनुमान
1. राजस्व प्राप्तियां	23,83,206	26,32,281	26,99,713	30,01,275
2. कर राजस्व	20,97,786	23,30,631	23,23,918	26,01,574
3. कर भिन्न राजस्व	2,85,421	3,01,650	3,75,795	3,99,701
4. पूंजी प्राप्तियां	18,09,951	18,70,816	17,90,773	17,64,494
5. ऋणों की वसूली	26,161	23,000	26,000	29,000
6. अन्य प्राप्तियां	46,035	61,000	30,000	50,000
7. उधार और अन्य देयताएं	17,37,755	17,86,816	17,34,773	16,85,494
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	41,93,157	45,03,097	44,90,486	47,65,768
9. कुल व्यय (10+13)	41,93,157	45,03,097	44,90,486	47,65,768
10. राजस्व खाते पर	34,53,132	35,02,136	35,40,239	36,54,657
11. ब्याज भुगतान	9,28,517	10,79,971	10,55,427	11,90,440
12. पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	3,06,264	3,69,988	3,21,190	3,85,582
13. पूंजी खाते पर	7,40,025	10,00,961	9,50,246	11,11,111
14. राजस्व घाटा (10-1)	10,69,926	8,69,855	8,40,527	6,53,383
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	7,63,662	4,99,867	5,19,337	2,67,801
16. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	17,37,755	17,86,816	17,34,773	16,85,494
17. प्राथमिक घाटा (16-11)	8,09,238	7,06,845	6,79,346	4,95,054

(सभी राशि करोड़ रुपये में है)

जीएसटी से कारोबार करना हुआ आसान

94% इंडस्ट्री के लोग जीएसटी को सकारात्मक सुधार के तौर पर देखते हैं

80% लोगों का मानना है कि जीएसटी से सप्लाई चेन का प्रभावी इस्तेमाल किया जा सका है। यानी इससे सप्लाई चेन की क्षमता बढ़ी है।

(अग्रणी फर्म के सर्वे के आधार पर)

धान और गेहूं की बढ़ती खरीदारी

(लाख मीट्रिक टन में)

₹3 लाख करोड़ की खरीदारी की गई ई-मंडियों के जरिये अब तक

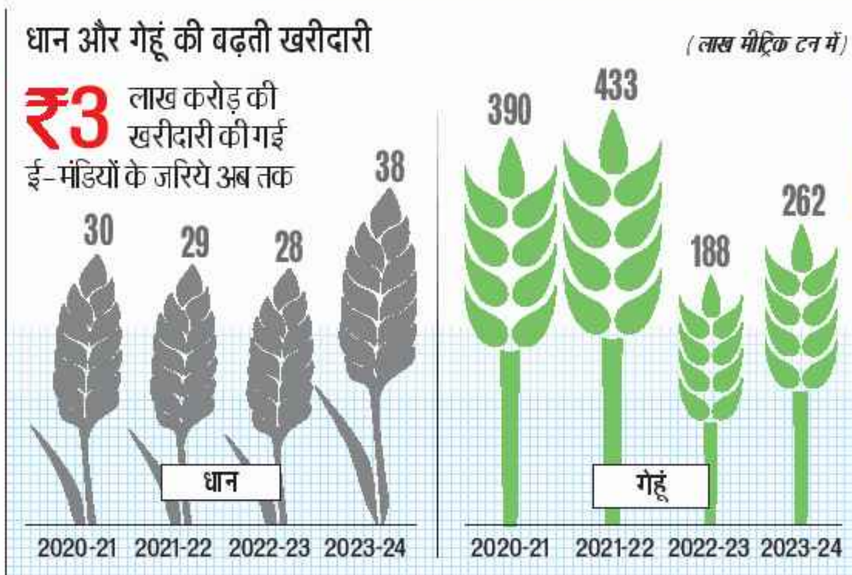

बढ़ता हुआ औसत मासिक जीएसटी संग्रह

बढ़ता गया पूंजीगत खर्च

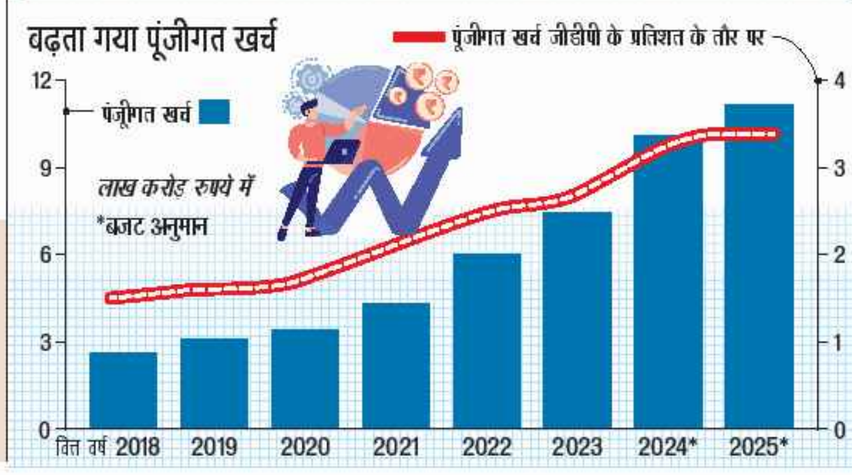

अंतरिम बजट पेश होने के बाद गुरुवार को सेंसेक्स 106 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। अबतक कुल आठ वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किया है। बजट जारी किए जाने के दिन बीएसई के सेंसेक्स की यह प्रतिक्रिया रही :

4 बार पिछले 6 वर्ष में बजट के दिन बीएसई सेंसेक्स ने दिया है पाजिटिव रिटर्न

212 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था सेंसेक्स 2019 के अंतरिम बजट के दिन तक

वर्ष	वित्त मंत्री	सेंसेक्स में बदलाव**
2014	अरुण जेटली	↓ 0.3 (-72)
2015		↑ 0.5 (142)
2016		↑ 0.6 (152)
2017		↑ 1.7 (486)
2018		↓ 0.16 (-58)
2019*	पीयूष गोयल	↑ 0.59 (212)
2019	निर्मला सीतारमण	↓ -0.99 (-395)
2020		↓ -2.43 (-988)
2021		↑ 5 (2315)
2022		↑ 1.46 (848)
2023		↑ 0.27 (158)
2024*		↓ -0.15 (-106)

* अंतरिम बजट **प्रतिशत

20% बढ़त दर्ज कर चुका है है बीएसई सेंसेक्स 1 जनवरी 2023 से इस साल 1 फरवरी 2024 तक

आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास

देश के 112 आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास तेजी से हो रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम रोजगार सृजन के साथ तेज विकास में राज्यों की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत विकास में पीछे रह गए जिलों पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है।

प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत

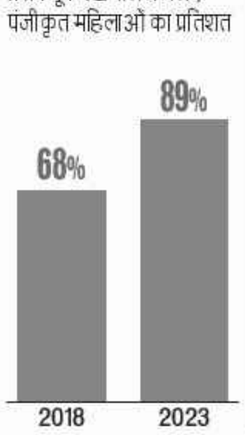

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नामांकन की संख्या

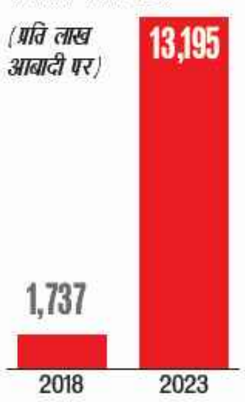

एफडीआइ का प्रवाह दोगुना

नीली क्रांति का आवंटन बढ़ा

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण

*संशोधित अनुमान ^बजट अनुमान

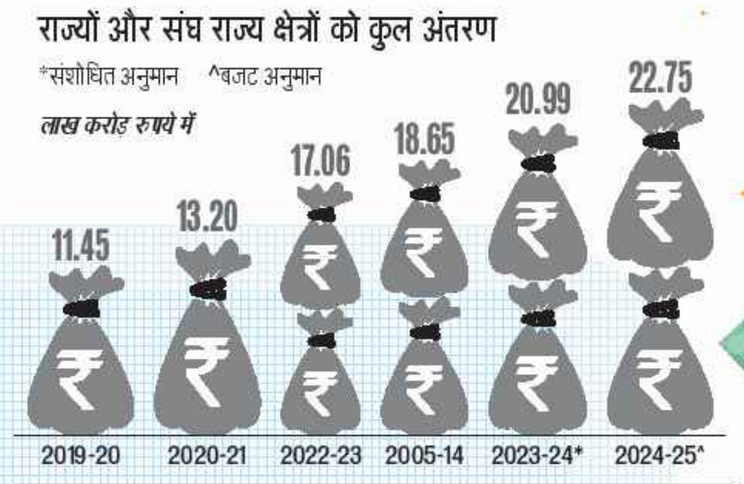

प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन

मनरेगा		आयुष्मान भारत		प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम	
60,000	86,000	7,200	7,500	4,645	6,200
2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25

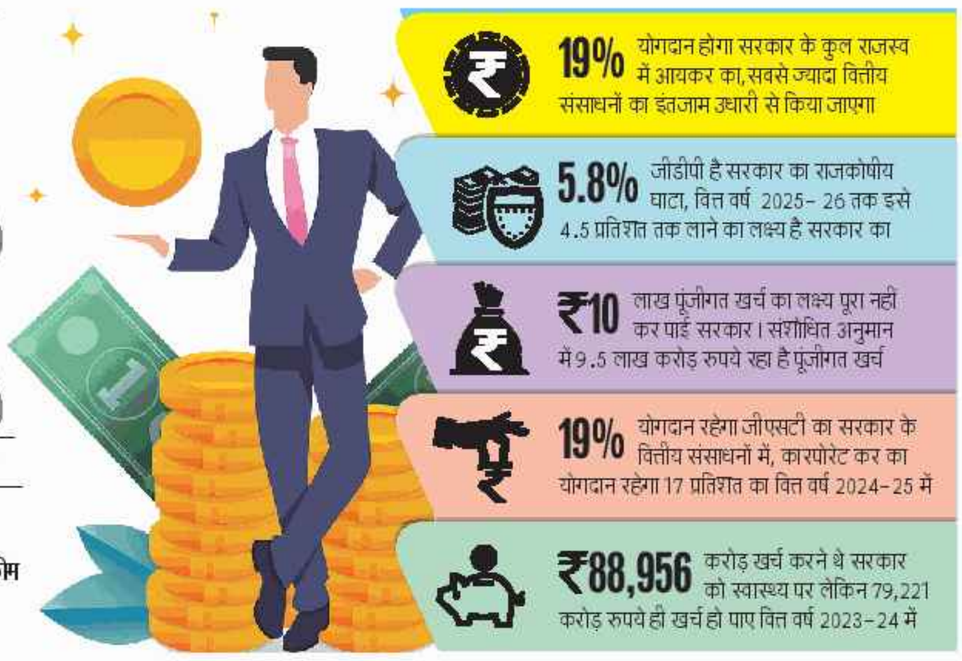

मंत्रालयों को कितना आवंटन

(सभी आंकड़े लाख करोड़ रुपये में)

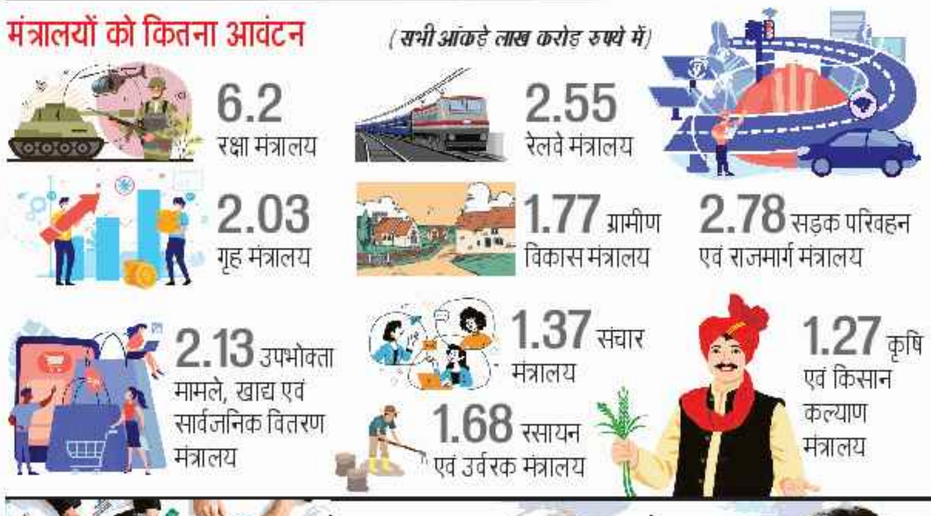

बढ़ता हुआ डिजिटल लेन-देन

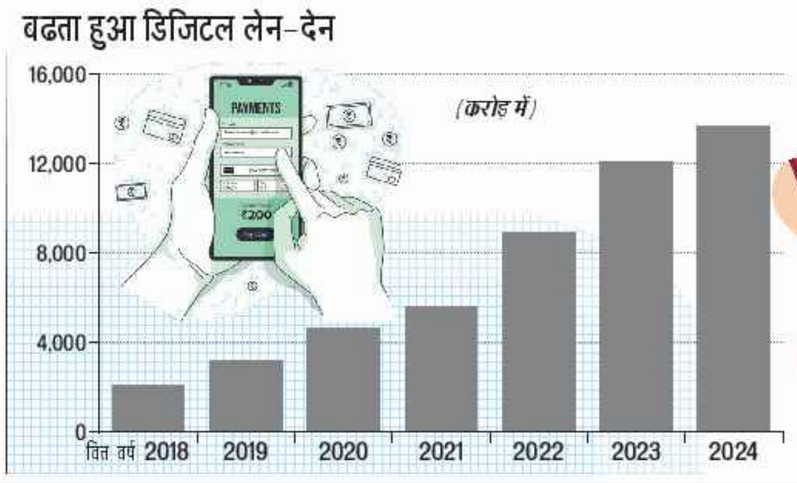

घटती बेरोजगारी दर

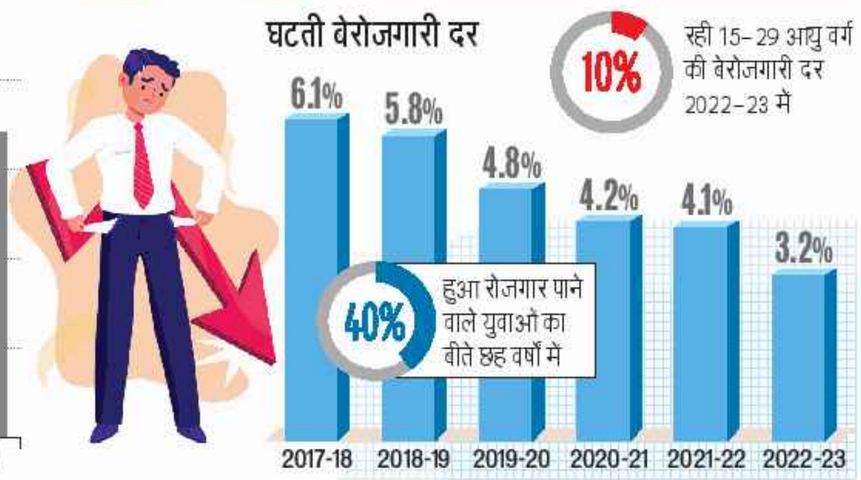

बजट के बाजीगर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वृहस्पतिवार को अपना छठां बजट पेश किया। नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट था। आइये जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट टीम में शामिल अधिकारियों के बारे में जिन्होंने बजट दस्तावेज तैयार करने में मदद की।

निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री

भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले वे पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य सीतारमण लगातार छह बजट पेश करने वाली सिर्फ दूसरी वित्त मंत्री होंगी। मोरारजी देसाई यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले वित्त मंत्री थे।

टीवी सोमनाथन
वित्त सचिव

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन 1987 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। तमिलनाडु कैडर के अधिकारी सोमनाथन इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में थे। वर्ष 2020 में वे वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव बने थे। अर्थशास्त्र पर उनके 80 पेपर और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा टीवी सोमनाथन दो किताबें भी लिख चुके हैं।

अजय सेठ
सचिव, डीईए

अजय सेठ आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव हैं। वे कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वर्ष 2021 में वित्त मंत्रालय आए थे और बजट डिवीजन की अगुवाई की। उन्होंने जी 20 ब्लाक के फाइनेंस ट्रैक के प्रमुख के तौर पर भी सेवाएं दी थीं। सितंबर 2023 में भारत ने जी 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।

तुहिन कांत पांडे
सचिव, दीपम

तुहिन कांत पांडे निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव है। वे 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के आइएएस अधिकारी हैं। तुहिन कांत पांडे ने एअर इंडिया के निजीकरण और जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के आइपीओ में अहम भूमिका निभाई थी। वित्त मंत्रालय आने से पहले वे उड़ीसा में प्रमुख सचिव थे।

संजय मल्होत्रा
राजस्व सचिव

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वे आइएएस की परीक्षा में अपने बैच के टापर रहे हैं। इससे पहले मल्होत्रा वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। बजट बनाने की प्रक्रिया में संजय मल्होत्रा की जिम्मेदारी कर राजस्व बढ़ाने की थी। बजट भाषण तैयार करने में भी अहम भूमिका।

विवेक जोशी
सलाहकार

विवेक जोशी बजट पर वित्त मंत्री के शीर्ष सलाहकारों के समूह में सबसे नए हैं। जोशी नवंबर 2022 में वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव के तौर पर वित्त मंत्रालय में आए थे। वे हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। इससे पहले विवेक जोशी भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर रहे हैं।

वी अनंत नागेश्वरन
मुख्य आर्थिक सलाहकार

मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन को अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों में सीतारमण के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक माना जाता है। नागेश्वरन के पास आर्थिक सर्वेक्षण की जिम्मेदारी भी है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले जारी किया जाता है। अंतरिम बजट के चलते इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं हुआ।

****

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 235

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है सेना

>> 9

ज्ञानवापी तलगृह में हरि-हर की 30 साल बाद आरंभ हुई पूजा-आरती

जिला अदालत के आदेश का प्रशासन ने कराया पालन, ब्रह्ममुहूर्त से नियमित अनुष्ठान आरंभ

पांच पहर होगी भोग-आरती, विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के पुजारियों ने संभाली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी

जिला अदालत के फैसले के अनुपालन में ज्ञानवापी तलगृह (व्यासजी का तहखाना) में गुरुवार को ब्रह्ममुहूर्त में व्यास पीठिका के निकट स्थापित देव विग्रहों की नियमित राग-भोग, पूजा-आरती आरंभ हो गई। भोर में मंगला आरती के साथ ही विश्वनाथ मंदिर की तरह पांच पहर आरती-अनुष्ठान किए गए। सुबह होते ही तलगृह में विराजमान प्राचीन शिवलिंग के साथ ही श्रीहरि, हनुमत प्रभु व मां गंगा के वाहन मकर विग्रह के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। तीन दशक बाद अपने आराध्यों का राग-भोग देख हर एक की आंखें छलछलाईं तो हर हर महादेव के उद्घोष का स्वर तीव्र हो उठा।

1993 में तलगृह में होने वाली नियमित पूजा पर रोक लगा दी गई तो तत्कालीन पुजारी पं. सोमनाथ व्यास ने न्यायालय की शरण ली। उनके नाती शैलेंद्र पाठक की याचिका पर बुधवार को जिला न्यायाधीश डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने ज्ञानवापी के तलगृह में स्थापित देव विग्रहों के नियमित राग-भोग, पूजा-आरती के लिए निर्णय सुनाया था। प्रशासन रात में ही सक्रिय हो उठा। साफ-सफाई कराने के साथ साज-सज्जा व विद्युत प्रकाश का भी देर रात लगभग 1.30 बजे तक प्रबंध कर लिया गया। एएसआइ सर्वे के दौरान कोषागार में जमा कराए गए आठ विग्रह लाए गए। अयोध्या में बालकराम की प्राण-प्रतिष्ठा कराने वाले वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के भाई विश्वेश्वर शास्त्री के निर्देशन में गंगा जल से शुद्धीकरण और नए वस्त्रादि के साथ फूल-माला से शृंगार कर ब्रह्ममुहूर्त में व्यास परिवार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक ने देव विग्रहों की विधि विधान से मंगला आरती की और भोग समर्पित किया।

अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके साथ ही श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर की तरह पांच पहर राग-भोग, पूजा-आरती का क्रम आरंभ हो गया।

- विराजमान हनुमत प्रभु और मां गंगा के वाहन मकर का भी विधि-विधान से किया गया पूजन

<< वाराणसी में गुरुवार को ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना करते पुजारी। प्रेट्र

झांकी दर्शन को उमड़ा रेला, रुंधे कंठ से हर हर महादेव बोला

तलगृह खुलने के बाद पूजा व आरती के साथ विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। देव विग्रहों का झांकी दर्शन कर लोग विभोर हुए और रुंधे कंठ से हर हर महादेव का उद्घोष किया। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर पुरी, अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानन्द सरस्वती, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी और अन्य की उपस्थिति में षोडशोपचार पूजन और आरती की गई। शृंगार गौरी मुकदमे में वादी महिलाएं सपरिवार दर्शन करने पहुंचीं और भावुक हो उठीं।

तीन हजार जवानों ने सड़क से गलियों तक संभाली सुरक्षा

वाराणसी में गुरुवार को शहर से गलियों तक में पीएसी, आरएएफ और पुलिस के करीब तीन हजार जवान भ्रमणशील रहे। मुस्लिमों की घनी आबादी वाले इलाके बुधवार रात से ही फोर्स के हवाले थे। फैसले के विरोध में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने जुमा के दिन (शुक्रवार को) बंदी की घोषणा की है। साथ ही लोगों से शांति व संयम बरतने की अपील की है।

बाबा विश्वनाथ की तरह ही राग-भोग का विधान

वादी पं. शैलेंद्र पाठक ने तलगृह स्थित व्यास पीठ में स्थापित देव-विग्रहों के पूजा-अर्चन, राग-भोग की व्यवस्था का अधिकार पूर्णरूप से श्रीकाशी विश्वनाथ न्यास परिषद को ही सौंप दिया। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रो. नागेंद्र पांडेय ने कहा कि पं. शैलेंद्र पाठक की विशाल सहृदयता का वह अभिनंदन करते हैं। बताया कि तलगृह में विराजमान देव विग्रहों की नित्य पूजा, आरती, राग-भोग का संपूर्ण विधान वही होगा, जो बाबा विश्वनाथ दरबार में है। तलगृह में देव विग्रहों के पूजन-अर्चन, राग-भोग का विधान तय करने का दायित्व न्यायालय ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को ही सौंपा है। विश्वनाथ मंदिर के अर्चक ही यहां भी पूजन-अर्चन करेंगे। न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि अपनी-अपनी पाली में बाबा दरबार में पूजन-अर्चन, आरती, राग-भोग का दायित्व निर्वहन करने वाले पुजारी-अर्चक ही तलगृह में भी विधान संपन्न कराएंगे।

पानी की टंकी में मिले शिवलिंग का आधार तलगृह में होने का दावा पेज>>11

सर्द माहौल में शांत विपक्ष, सक्रिय सत्तापक्ष ने किया एक-दूसरे को हैरान

संजय मिश्र, नई दिल्ली

अंतरिम बजट 2024-25

- न टोकाटाकी हुई, न शोर-शराबा, वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में सरपट दौड़ाई अंतरिम बजट भाषण एक्सप्रेस
- लक्षद्वीप, अयोध्या के उल्लेख पर सत्तापक्ष ने दिखाया जोश, करदाताओं के लिए वित्त मंत्री की पोटली से नहीं निकली राहत

नई दिल्ली में गुरुवार को वित्त मंत्रालय के बाहर लाल रंग के कवर में 'बही-खाते' के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

ठंड के मौसम में राजधानी दिल्ली में बारिश की बौछार का असर हो या फिर विपक्ष के लिए लगातार बनते जा रहे मुश्किल सियासी हालात... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रत्याशित रूप से सदन में लगभग मूरत की तरह बैठे विपक्ष की शांति के बीच लोकसभा में अपने अंतरिम बजट भाषण को पूरी गति से सरपट दौड़ाया। केवल मेजें थपथपाने तक सक्रिय रहे सत्तापक्ष को शांत चित विपक्ष ने सियासी गरमागरमी का कोई मौका नहीं दिया तो वित्त मंत्री ने केवल 58 मिनट में अपने अंतरिम बजट भाषण एक्सप्रेस को मंजिल तक पहुंचा दिया। बजट चाहे अंतरिम ही हो, मगर आम चुनाव से ठीक पहले इस मौके पर सदन में विपक्ष का कोई सांसद जुबान भी नहीं खोलेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। चुनावी मौसम में वित्त मंत्री की पोटली से किसी भी वर्ग के लिए एक भी लुभावनी घोषणा नहीं होगी, ऐसी अपेक्षा नहीं थी। इस लिहाज से उम्मीदों और अपेक्षाओं की कसौटी पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे को हैरान किया कि वित्त मंत्री के भाषण के दौरान एक बार भी टोका-टाकी तो दूर विपक्ष ने अपने होंठ तक नहीं हिलाए।

आम चुनाव की सियासी बिसात चाहे बाहर कितनी तेजी से बिछाई जा रही हो, मगर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी लेखानुदान बजट भाषण शुरू किया तो लोकसभा का माहौल बेहद शांत था। विपक्षी बेंच अपनी पूरी क्षमता में नहीं थी तो सत्तापक्ष की भी काफी सीटें खाली थीं। हालांकि, बजट भाषण के आधे घंटे बाद दोनों तरफ की संख्या में कुछ और इजाफा हुआ। वैसे सदन के इस शांत माहौल में थोड़ी सक्रियता दो-तीन मौके पर नजर आई। इसमें पहला मौका सदन की बैठक शुरू होने से पूर्व तब आया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में प्रवेश किया। सत्ताधारी भाजपा के सांसदों ने मेजें थपथपाते और भारत माता तथा जय श्रीराम के नारे लगाते हुए पीएम का सदन में स्वागत किया।

सदन में निर्बाध भाषण पढ़ रहीं वित्त मंत्री ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम की ओर से घरों पर सोलर प्लांट लगाने को लेकर की गई घोषणा की कार्ययोजना में 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त के प्रस्ताव की बात कही तब सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाने के साथ एक बार फिर जय श्रीराम के नारे लगाकर सदन की खामोशी तोड़ने की कोशिश की। हालांकि, इसके बावजूद विपक्षी सांसदों ने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। विपक्षी बेंच की अग्रिम पंक्ति में बैठी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, द्रमुक नेता टीआर बालू और तृणमूल नेता सुदीप बंधोपाध्याय वित्त मंत्री के भाषण को निरपेक्ष भाव से सुनते-देखते रहे।

बीते पांच साल के साथ वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के 10 साल के दौरान हुए कई ऐसे बड़े फैसलों का जिक्र किया, जिसका राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी विस्तार से उल्लेख किया था। इस दौरान वित्त मंत्री ने सत्तापक्ष की कई मौकों पर तालियां बटोरीं। खासकर तब जब मध्यम वर्ग के घर का सपना साकार करने और मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने के सरकार के भविष्य के इरादों की चर्चा की। मालदीव के मंत्रियों के बयान से बढ़ी कटुता के मद्देनजर वित्त मंत्री ने जब लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की घोषणा की तो स्वाभाविक रूप से भाजपा सांसदों ने जोर से मेजें थपथपाईं। वित्त मंत्री ने जब टैक्स भरने वाले करदाताओं की प्रशंसा की तो सदन में दोनों तरफ कुछ उत्सुकता जगी कि चुनाव से पहले इस वर्ग के लिए शायद कुछ राहत की पोटली खुलने वाली है। मगर अगली पंक्तियों में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर ढांचों में किसी तरह का बदलाव नहीं करने की घोषणा कर कुछ पलों के लिए जगी इस उत्सुकता को तत्काल शांत कर दिया।

राजस्थान में हिजाब पहनकर आने पर स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश

जागरण संवाददाता, जयपुर

- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा-छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं मिलेगी तो उसके साथ शिक्षक पर भी होगी कार्रवाई
- पिछले दिनों हिजाब पर आपत्ति के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने थाने का किया था घेराव

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिजाब को लेकर फिर बयान दिया। कहा कि हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से तय ड्रेस में ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं मिलेगी तो उसके साथ शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम हिजाब के विरोधी नहीं हैं, लेकिन स्कूलों के नियम का तो पालन करना ही होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मतांतरण नहीं होने देंगे।

दरअसल, हिजाब को लेकर कुछ दिनों से प्रदेश में माहौल गर्माया हुआ है। दो दिन पहले भी दिलावर ने कहा था कि जो भी स्कूली ड्रेस को लेकर उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने हिजाब पर रोक को लेकर अधिकारियों से चर्चा में उन राज्यों से जानकारी जुटाने को कहा जहां हिजाब पर रोक है। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी स्कूलों के साथ मदरसों में भी हिजाब पर प्रतिबंध की पैरवी की थी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों जयपुर के गंगापोल सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम में भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने स्कूल में भारत माता की जय के नारे भी लगवाए थे। बाद में मुस्लिम छात्राओं व उनके अभिभावकों ने सुभाष चौक थाने का घेराव किया था।

मदन दिलावर। फाइल

दिलावर बोले- अकबर महान नहीं, बलात्कारी था

दिलावर ने पाठ्यक्रम में अकबर को महान बताने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस अकबर ने मीना बाजार लगाकर मां और बहनों को उठाने का काम किया, आखिर वह कैसे महान हो सकता है। अकबर महान नहीं, बलात्कारी था। उन्होंने कहा कि स्कूलों की कुछ किताबों में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को आतंकी बताने की भी जानकारी मिली है। इस बारे में पड़ताल करवाई जा रही है। देशभक्तों को आतंकी बताकर पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चों पर इसका विपरीत असर होगा। इस तरह का कोई अंश हुआ तो उसमें बदलाव किया जाएगा।

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में आठ दिनों तक दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनी। सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पार्डीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, वह एएमयू का भविष्य तय करने वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान माना जाएगा कि नहीं। इस मामले में एएमयू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांच जनवरी 2006 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। (पेज-9)

विमर्श

झलक रहा है सरकार का आत्मविश्वास : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट आगामी आम चुनाव में जीत के प्रति मोदी सरकार के आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई पड़ रहा है। **मनोहर मनोज** का दृष्टिकोण।

एक बार फिर अस्थिरता की ओर प्रदेश : झारखंड का गठन हुए महज 24 वर्ष हुए हैं, परंतु अब तक वहां 11 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। एक बार फिर से अस्थिरता की ओर जा रहा है यह प्रदेश, जिसे विश्लेषित कर रही है **प्रदीप सिंह** की डायरी। • पेज-7

झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे चम्पाई सोरेन, आज लेंगे शपथ

राज्य ब्यूरो, रांची

- राज्यपाल ने गुरुवार देर रात दिया शपथ ग्रहण करने का आमंत्रण
- चम्पाई को 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत

झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गुरुवार को रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट के बाद बाहर निकलते झामुमो नेता चम्पाई सोरेन। प्रेट्र

हेमंत सोरेन की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी संकट के बादल देर रात छंट गए जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने विधायक दल के नेता चम्पाई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण दे दिया। चम्पाई नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुक्रवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें 10 दिन के अंदर बहुमत साबित करना होगा।

झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन की ओर से चम्पाई को नया नेता चुन लिया गया फिर भी राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। चम्पाई के शपथ ग्रहण पर असमंजस के बीच महागठबंधन के विधायकों को एकजुट रखने के लिए भी मशक्कत की जाती रही। विधायकों को तोड़ने की गुंजाइश खत्म करने के लिए महागठबंधन के 38 विधायकों को गुरुवार को दो विशेष विमान से हैदराबाद भेजने की तैयारी थी मगर मौसम इसमें बाधक बना। दो घंटे से अधिक समय तक विमान में बैठकर मौसम साफ होने का इंतजार करने के बाद विधायक एयरपोर्ट से लौट गए।

फिलहाल विधायकों को रांची स्थित सर्किट हाउस में ठहराया गया है। विधायक दिन में ही हैदराबाद जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण दिल्ली से रांची विमान आने में भी देर हुई। इसी बीच देर शाम राज्यपाल ने चम्पाई को शपथ ग्रहण के लिए समय दे दिया।

चम्पाई ने किया स्थिर सरकार का दावा

बुधवार रात को हेमंत के इस्तीफे के तत्काल बाद ही चम्पाई ने महागठबंधन के 47 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण कराने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए। गुरुवार को देर रात तक राजभवन की चुप्पी बरकरार रही। दोपहर को चम्पाई ने दोबारा राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि दो दिनों से सरकार के गठन को लेकर निर्णय नहीं लिए जाने से असमंजस की स्थिति है। इसके बाद शाम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर उन्होंने दोबारा 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। कहा कि कुछ और विधायकों के रांची पहुंचने से उनके पास 45-46 विधायक हो जाएंगे। दावा किया कि बहुमत उनके साथ है तथा वे राज्य में स्थिर सरकार देने में सक्षम हैं। इसी बीच रात लगभग 11.30 बजे राज्यपाल ने चम्पाई को बुलाकर शपथ दिलाने की घोषणा कर दी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है।

ईडी ने कहा, बेनामी संपत्ति हड़पना चाहते थे हेमंत सोरेन पेज>>11

ईडी की याचिका पर एजेएल और हुड्डा को हाई कोर्ट का नोटिस

चंडीगढ़ : प्लाट आवंटन मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को ईडी की याचिका पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। ईडी ने इन सभी के खिलाफ आरोप तय करने पर लगी रोक को चुनौती दी है। 19 अप्रैल, 2022 को विशेष अदालत ने आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी। (पेज-9)

धामी को आज सौंपा जाएगा समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट

देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। इसे शनिवार तीन फरवरी को कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट को पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ड्राफ्ट में कानूनों को सख्त करने पर जोर दिया गया है। (पेज-9)

अमेरिका ने वीजा शुल्क में की भारी बढ़ोतरी

वाशिंगटन : अमेरिकी ने गैर-आप्रवासी वीजा की विभिन्न श्रेणियों में भारी शुल्क वृद्धि की घोषणा की है। इसमें भारतीयों में लोकप्रिय एच-1बी, ईबी-5 और एल-1 वीजा शामिल हैं। फीस बढ़ोतरी आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क के लिए अब 460 डालर की जगह 780 डालर देना होगा। जबकि एच-1बी पंजीकरण शुल्क 10 डालर से बढ़ाकर 215 डालर होगा, लेकिन यह अगले वर्ष से लागू होगा। (पेज-12)

श्रीराम

अनुमान से कई गुना अधिक दर्शनार्थी पहुंच रहे रामनगरी

प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, भीड़ कम होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं आसपास के जिलों के लोग

रघुवरशरण, अयोध्या

अनुमान ध्वस्त हो रहे हैं और रामनगरी आस्था के शिखर का आलिंगन कर चहक रही है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण और रामलला के विग्रह की प्रतिष्ठा के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तीन से पांच गुना तक बढ़ जाएगी, किंतु गत दस दिनों का अनुभव बताता है कि यह संख्या उससे काफी अधिक है।

रामलला की प्रतिष्ठापना के बाद से रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या 25 लाख के पार जा पहुंची है। प्रतिदिन औसतन ढाई लाख से अधिक लोग दर्शन कर रहे हैं, जबकि रामलला की प्रतिष्ठापना से पहले यह संख्या 20- 25 हजार थी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी-अपनी विधा और क्षेत्र के शीर्ष पर विराजे साढ़े छह हजार अतिथि ही शामिल हुए थे और उन्हें ही रामलला के दर्शन का अवसर मिला, किंतु अगले दिन यानी 23 जनवरी से आस्था का ज्वार उमड़ा। उस दिन के दर्शनार्थियों की संख्या पांच लाख तक जा पहुंची। समझा गया कि एक-दो दिन के बाद दर्शनार्थियों की संख्या सामान्य होगी, किंतु दस दिन हो गए और दर्शनार्थियों का ज्वार नित्य उमड़ रहा है। गुरुवार को भी रामलला आस्था के ज्वार से अभिषिक्त हो रहे थे।

बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार के दिन अपेक्षाकृत कम श्रद्धालुओं के आने की प्रवृत्ति देखी जाती है और यदि इन दिनों श्रद्धालुओं की संख्या दो लाख तक पहुंच रही है, तो मंगलवार, शनिवार एवं रविवार को यह तीन लाख पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं। 24 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 17 अप्रैल को रामनवमी जैसे पर्वों पर तो दर्शनार्थियों की संख्या पांच लाख से 10 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। यह अनुमान रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माथे पर चिंता की लकीर भी पैदा करने वाला है। रामलला के प्रधान अर्चक आचार्य सत्येंद्रदास कहते हैं, हम 23 जनवरी को पांच लाख श्रद्धालु आने के अनुभव से गुजर चुके हैं, किंतु इससे डेढ़ या दो गुना और अधिक श्रद्धालु आने का अनुमान विचलित करने वाला है।

निकट भविष्य में और वृद्धि की संभावना : श्रद्धालुओं के आगमन की प्रवृत्ति को देखते हुए निकट भविष्य में उनकी संख्या में और वृद्धि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्रद्धालुओं का प्रवाह लघु भारत का परिचायक है, किंतु इसमें दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं का आधिक्य है जो उत्तर-दक्षिण की भौगोलिक-सांस्कृतिक एकता को भी परिपुष्ट करता है।

रामजन्मभूमि पथ पर आगे बढ़ते श्रद्धालु। जागरण

अयोध्या के लिए आठ शहरों से शुरू हुई सीधी हवाई सेवा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : रामलला की नगरी अयोध्या गुरुवार को आठ प्रमुख शहरों के हवाई मार्ग से जुड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पाइसजेट एयरलाइंस की आठ नई हवाई सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इसी के साथ अयोध्या से दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई व बेंगलुरु हवाई मार्ग से जुड़ गए हैं। बेंगलुरु को छोड़कर शेष सभी हवाई सेवाएं गुरुवार से शुरू हो गईं। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा कि विगत एक माह के दौरान अयोध्या नगरी की कनेक्टिविटी देश के महत्वपूर्ण शहरों के साथ होना पर्यटन की संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

बंगाल में एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार को लेकर हाई कोर्ट को लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- न्यायाधीश ने सीआइडी से नौ फरवरी तक जांच की प्राथमिक रिपोर्ट मांगी
- पत्र में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं की संलिप्तता का भी दावा

बंगाल सरकार के एक अधिकारी ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट को पत्र लिखा है, जिसके आधार पर इसकी सीआइडी जांच का आदेश दिया गया है। न्यायाधीश बिश्वजीत बसु ने नौ फरवरी तक सीआइडी से जांच की प्राथमिक रिपोर्ट मांगी है। अधिकारी ने भ्रष्टाचार में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं की संलिप्तता का भी दावा किया है। उन्होंने राशन वितरण घोटाले में नई जानकारियां दी हैं।

मालूम हो कि इस मामले में बंगाल के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिकारी ने राशन वितरण घोटाला में हावड़ा के एक नेता की संलिप्तता का दावा किया है। उन्होंने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के तहत हुई शिक्षकों की नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार की बात कही है। हाई कोर्ट को बताया कि 313 शिक्षकों को रुपये के एवज में गैरकानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ सरकार के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि इस पत्र में कही गई बातों की सत्यता की जांच किए जाने की जरूरत है। कई बार व्यक्तिगत रोष में भी इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं।

****

2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में चल रही मोदी सरकार ने समग्र विकास के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना लाने वाली केंद्र सरकार इस योजना का विस्तार कर रही है।

2.78 लाख करोड़ की अनुमानित राशि निर्धारित की गई है सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए बजट में, सड़क निर्माण पर सरकार का फोकस

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति
(प्रति दिन किमी के हिसाब से)

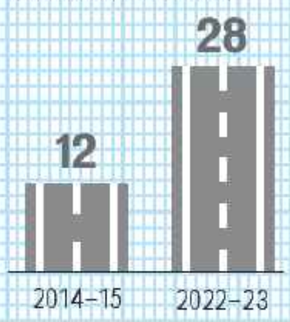

बढ़ा रक्षा बजट तीनों सेनाओं को चुनौतियों के लिए करेगा तैयार

संजय मिश्र • नई दिल्ली

27 हजार करोड़ बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ किया गया रक्षा मंत्रालय का आवंटन

1.72 लाख करोड़ पूंजीगत अधिग्रहण के लिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर

सीमाओं पर गहराती चुनौतियों के साथ भू-राजनीतिक परिदृश्य के बदलते हालात के मद्देनजर रक्षा बजट खर्च में पिछले साल की तुलना में करीब 27 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य के तहत रक्षा बजट को पिछले साल के 5.94 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। यह आवंटन कुल बजट का 13.04 प्रतिशत है।

वित्त मंत्री ने डीप-टेक तकनीक को मजबूती देकर रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनने की गति तेज करने के लिए एक नई योजना लाने की भी घोषणा की है। अंतरिम बजट से साफ है कि वित्त वर्ष 24-25 के लिए रक्षा बजटीय आवंटन 2022-23 के आवंटन से लगभग एक लाख करोड़ (18.35 प्रतिशत) और 23-24 से 4.72 प्रतिशत अधिक है। इसमें से 27.67 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा पूंजी में जाता है। 14.82 प्रतिशत जीविका और परिचालन तैयारियों पर राजस्व व्यय के लिए, 30.68 प्रतिशत वेतन और भत्ते के लिए, 22.72 प्रतिशत रक्षा पेंशन के लिए रखा जाता है। रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देने के लिए रक्षा पूंजीगत व्यय में वृद्धि का क्रम जारी है। नए वित्त वर्ष के लिए रक्षा पूंजीगत व्यय पर 1.72 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33 प्रतिशत अधिक है। यह आवंटन तीनों सेनाओं की दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआइपीपी) के अनुरूप है। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ बड़े अधिग्रहणों को मूर्त रूप देकर तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण गैप को भरना है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, बढ़े हुए बजटीय आवंटन से विमानों की अतिरिक्त खरीद, मौजूदा मिग-29 के लिए उन्नत इंजनों के अधिग्रहण, परिवहन विमान सी-295 और मिसाइल प्रणालियों के अधिग्रहण के साथ-साथ मौजूदा सुखोई-30 बेड़े का आधुनिकीकरण होगा। 'मेक इन इंडिया' की पहल को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादन में अत्याधुनिक तकनीक सुनिश्चित करने के लिए एलसीए एमके-आइ आइओसी/एफओसी कन्फिगरेशन को अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी।

रक्षा बजट में बढ़ रही पेंशन की हिस्सेदारी

रक्षा बजट में पेंशन की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। पेंशन के लिए आवंटन 1,41,205 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्त वर्ष से 2.17 प्रतिशत अधिक है। भारत-चीन सीमा पर लगातार खतरे की आशंका के मद्देनजर सीमा सड़क संगठन के पूंजीगत बजट आवंटन में बढ़ोतरी करते हुए 6,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विशेषकर 13,700 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में न्योमा एयर फील्ड का विकास, अंडमान और निकोबार द्वीप में भारत की सबसे दक्षिणी पंचायत के लिए स्थायी पुल कनेक्टिविटी, हिमाचल प्रदेश में 4.1 किमी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकू ला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग पर रकम खर्च होगी।

2024-25 में कुछ बड़े अधिग्रहणों को मूर्त रूप देकर तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण गैप को भरना है

1,41,205 करोड़ रुपये रक्षा पेंशन के लिए आवंटित, जो पिछले वित्त वर्ष से 2.17 प्रतिशत अधिक है

13,700 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में न्योमा एयर फील्ड का होगा विकास, कई अन्य अहम परियोजना भी शामिल

6500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं भारत-चीन सीमा पर लगातार खतरे को देखते हुए सीमा सड़क संगठन को, कई परियोजनाएं जारी

2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भरोसा : राजनाथ

नई दिल्ली, एएनआइ : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट को उत्साहजनक बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि देश 2047 तक विकसित बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह उत्साहजनक बजट है। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

बजट बोल

वित्त मंत्री ने जो रोडमैप बनाया है वह पिछले 10 वर्षों में बनाए गए कार्यों को इस बजट में बुनियादी ढांचे, रेलवे, नवीकरणीय, आवास, विनिर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ाया गया है। बजट में कई सकारात्मक प्रविधान हैं। – **मुकेश माथुर**, राष्ट्रीय प्रमुख वेल्थ, एयूएम कैपिटल

प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की घोषणा एक सकारात्मक कदम है। लंबी अवधि के ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर वाले ऋण और डीप टेक संबंधी घोषणा निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। – **एसपी कोचर**, महानिदेशक, सीओएआइ

पीएम-किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से लेकर किसान-केंद्रित नीतियों के विस्तार और नवाचारों को बढ़ावा देने तक, बजट कृषि क्षेत्र में समावेशी, टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

– **बलराम सिंह यादव**, प्रबंध निदेशक, गोदरेज एग्रोवेट

अंतरिम बजट 2047 तक भारत को पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और एक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के उद्देश्य पर केंद्रित है। बजट यह सुनिश्चित करेगा कि भारत 2025 तक पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन जाए। – **अजय सिंह**, प्रेसिडेंट, एसोचैम

बुनियादी ढांचे को 11.11 लाख करोड़ का 'शगुन'

बजट में पूंजीगत व्यय में 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ इन्फ्रा विकास पर सरकार का फोकस

मनीष तिवारी • नई दिल्ली

9.5 लाख करोड़ की राशि खर्च हो जाने का अनुमान है पूंजीगत व्यय में इस साल मार्च तक

10 सालों में विमानन क्षेत्र का हुआ कायापलट, हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी बढ़कर 149 हुई

17 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं

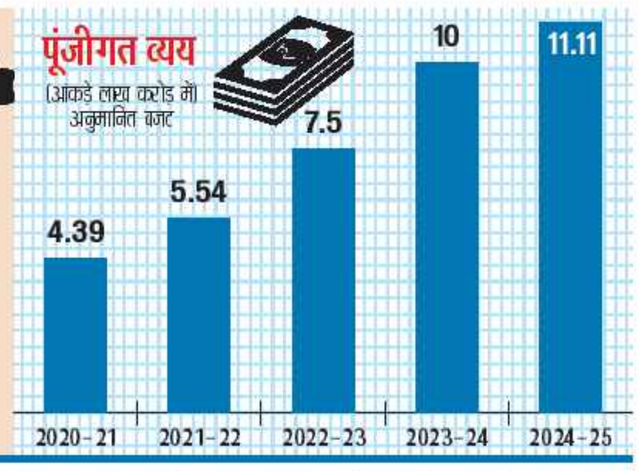

इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के लिए खर्च में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि के 'शगुन' के साथ इसे 11,11,111 (ग्यारह लाख, ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) करोड़ रुपये तक ले जाकर केंद्र सरकार ने 'शुभ' भारत में प्रगति और रोजगार के नए अवसरों के सृजन की जमीन भी मजबूत कर दी है। पिछले वर्ष के मुकाबले यह बढ़ोतरी काफी कम है, लेकिन अंतरिम बजट की सीमाओं और बदली स्थितियों के लिहाज से यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। इन्फ्रा विकास पर कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।

पिछले वर्ष सरकार ने पूंजीगत व्यय में 37.5 प्रतिशत की रिकार्ड बढ़ोतरी कर इसे 10 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचा दिया था। इस वर्ष मार्च तक इसमें 9.5 लाख करोड़ की राशि खर्च हो जाने का अनुमान है। इसके पहले वाले वर्ष में भी लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। वे परिस्थितियां भी अलग थीं, जब कोविड के कारण निजी क्षेत्र की खराब स्थिति के कारण सरकार ने ज्यादातर बोझ अपने कंधे पर उठा लिया था, लेकिन अब निजी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा भी कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने जिस तरह इस क्षेत्र में अपना खर्च बढ़ाया है, उससे आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हुई है और नौकरियों के ढेरों अवसर उत्पन्न हुए हैं।

सड़क निर्माण की तेज रफ्तार के बीच वित्त मंत्री ने यह भी एलान किया कि मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार और नए हवाई अड्डों के विकास का सिलसिला आगे भी तेजी से जारी रहेगा। पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र का कायापलट हुआ है, हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी बढ़कर 149 हो गई है। उड़ान योजना के तहत दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा जा रहा है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां एक हजार से अधिक नए वायुयानों के लिए आर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं।

एनएचएआइ का आवंटन 1.68 लाख करोड़ : मोदी सरकार के ब्रांड के रूप में उभरे सड़क निर्माण पर भी सरकार का फोकस बना हुआ है। इसी कड़ी के तहत सड़क परिवहन मंत्रालय के बजट के लिए अनुमानित राशि 2.78 लाख करोड़ निर्धारित की गई है।

यह पिछले वर्ष किए गए आवंटन 2.70 लाख करोड़ के आसपास ही है। माना जा रहा है कि यह सड़क निर्माण की मौजूदा रफ्तार को कायम रखने के लिए किया गया है। जुलाई में पूर्ण बजट पेश किए जाने के दौरान इसमें व्यापक बढ़ोतरी की जा सकती है। एनएचएआइ के लिए आगामी वित्त वर्ष में 1.68 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह भी पिछले वर्ष के संशोधित आवंटन (1.67 लाख करोड़) से कुछ ही अधिक है। इसी तरह हाईवे को छोड़कर अन्य सड़कों के निर्माण के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। यह भी पिछले वर्ष के संशोधित आवंटन के करीब है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इन्फ्रा विकास का मजबूत ढांचा बनाया है, जिसमें 1.50 लाख किलोमीटर का हाईवे और चार हजार किलोमीटर का एक्सप्रेस वे शामिल है।

मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाने का जारी रहेगा प्रयास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश में मेडिकल शिक्षा में सुधारों और उसे सुलभ बनाने के लिए 2014 से शुरू हुआ सिलसिला मोदी सरकार के अंतिम अंतरिम बजट में भी जारी रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न विभागों के मातहत चल रहे अस्पतालों की अवसंरचना का उपयोग करते हुए नए मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो अस्पतालों के पास उपलब्ध आधारभूत ढांचे का अध्ययन कर मेडिकल कालेज खोलने की संभावना पर अपनी रिपोर्ट देगा।

निर्मला सीतारमण के अनुसार, डाक्टर बनना कई युवाओं की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मेडिकल शिक्षा में सीटों की कमी के कारण उनके सपने पूरे नहीं हो पाते। सीटों की कमी के कारण देश में बड़ी संख्या में युवाओं को दूसरे देशों में मेडिकल शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। मोदी सरकार लगातार नए मेडिकल कालेज खोलने और एमबीबीएस व पीजी की सीटें बढ़ाने पर जोर देती रही है। 2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कालेज थे। वहीं पिछले 10 वर्षों में 319 नए मेडिकल कालेज खोले गए हैं। इस तरह से 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ मेडिकल कालेजों की संख्या 706 हो गई है।

नए मेडिकल कालेजों के खुलने से देश में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में दोगुनी से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। 2014 में एमबीबीएस की कुल सीटें 51,348 थी, जो अब 112 प्रतिशत बढ़कर 1,08,940 हो गई हैं। इसी तरह से पीजी की सीटें पिछले 10 वर्षों में 31,185 से बढ़कर 70,674 हो गई हैं, जो 127 प्रतिशत अधिक हैं।

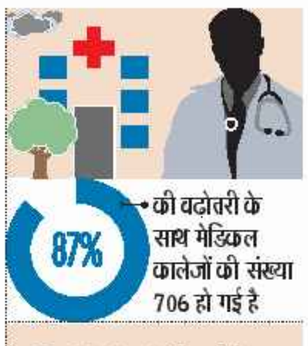

की बढ़ोतरी के साथ मेडिकल कालेजों की संख्या 706 हो गई है

2014 में एमबीबीएस की कुल सीटें 51,348 थी, जो अब 112 प्रतिशत बढ़कर 1,08,940 हो गई हैं

सूर्योदय योजना से 18 हजार करोड़ की होगी बचत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटने के बाद 22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सूर्योदय योजना का एलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना को आगे बढ़ाने की बात कही है। सरकार ने इस मद में 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक परिवार हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा। इससे देश के एक करोड़ परिवार वर्ष में 18 हजार करोड़ रुपये की बचत कर सकेंगे और साथ ही अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति बिजली वितरण कंपनियों को कर सकेंगे। इससे उन्हें अतिरिक्त आय भी हो सकती है। वित्त मंत्री ने देश के ऊर्जा सेक्टर को लेकर सरकार की यह सोच सामने रखी है कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को आगे भी तेजी से प्रोत्साहित किया जाएगा।

अंतरिम बजट में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने वाले हैं। सौर ऊर्जा को कई तरह से पहले ही प्रोत्साहित करने का काम चल रहा है, अब पवन ऊर्जा लगाने वाली कंपनियों को भी अतिरिक्त फंड देने की व्यवस्था की गई है। अपतटीय पवन ऊर्जा में 1,000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए कंपनियों को फंड दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक देश में कोल गैसीफिकेशन से 100 मीट्रिक टन क्षमता गैस निकालने का इरादा जताया है। जबकि देशभर में बायोगैस मिश्रित पीएनजी व सीएनजी उपलब्ध कराने का काम भी सरकार करने वाली है। पीएनजी से रसोई गैस की आपूर्ति होती है, जबकि सीएनजी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है। इनमें बायोगैस मिलाने से न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी बल्कि बड़े पैमाने पर बायोगैस बनाने वाली कंपनियों का उद्भव भी संभव है। सीतारमण ने यह भी बताया कि बायोगैस बनाने को जरूरी उपकरण खरीदने को सरकार मदद देगी।

जहां तक हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलने की बात है तो इस बारे में वित्त मंत्री ने स्पष्टता से कुछ नहीं बताया। बिजली मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह मोटे तौर पर एक सौर पैनल लगाने से एक महीने में उत्पादित होने वाली बिजली के आधार पर है। हर परिवार रोजाना 10 यूनिट बिजली पैदा करता है तो यह महीने में 300 यूनिट होता है। सौर पैनल से एक परिवार औसतन रोजाना 17-18 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है। सौर बिजली की औसत कीमत 2.7 रुपये प्रति यूनिट लगाई है। इसके आधार पर सालाना एक परिवार को 18 हजार तक की बचत का दावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया है।

2030 तक देश में कोल गैसीफिकेशन से 10 करोड़ टन गैस निकालने का लक्ष्य

35 लाख नई नौकरियां निकलेंगी 2030 तक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में

26 गुना बढ़ी है 10 वर्षों में सौर ऊर्जा की क्षमता

ई-बसों को मिलेगी प्राथमिकता, चार्जिंग की मिलेगी सुविधा

हरित ईंधन को बढ़ावा देने के संदर्भ में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं पर जोर देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ई-वाहनों के निर्माण व चार्जिंग सुविधाओं में सहायता देगी और इनके इकोसिस्टम को सुदृढ़ करेगी। सामाजिक परिवहन में ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी अपने अभिभाषण में नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में सरकार की उपलब्धियों का पूरा ब्योरा दिया था कि कैसे पिछले 10 वर्षों में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 26 गुना बढ़ी है। सौर व दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर पैदा होने की संभावना है। इसका जिक्र वित्त मंत्री ने भी किया कि कैसे छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने व उनकी देखरेख के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों की जरूरत होगी। रोजगार के अवसर बनेंगे। सनद रहे कि मार्च, 2023 में जारी एक अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2030 तक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 35 लाख नई नौकरियां निकलेंगी।

राज्यों को सहारा, विकसित भारत का संकल्प

जितेंद्र शर्मा • नई दिल्ली

देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में चल रही मोदी सरकार ने समग्र विकास के दृष्टिकोण पर फिर जोर दिया है। कोरोना महामारी जैसे संकटकाल में राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना लाने वाली केंद्र सरकार लगातार इस योजना का विस्तार कर रही है और अब इसे एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपये का प्रविधान कर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि मोदी सरकार राज्यों को सहारा देते हुए विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ना चाहती है और इसके लिए राज्यों को भी सुधारों के प्रति सक्रियता और प्रतिबद्धता दिखानी होगी।

केंद्र की मोदी सरकार का मानना है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। बजट में इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। दरअसल, अपने पूंजीगत व्यय के आकार को लगातार बढ़ा रही केंद्र सरकार की सोच है कि रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के उसके सिद्धांत पर सभी राज्य भी चलते हुए आवश्यक सुधारों को अपनाते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भी बढ़ाया गया। योजना के तहत क्रमशः 11,830.29 करोड़ रुपये, 14,185.78 करोड़ रुपये और 18,195.35 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। मानकों और पात्रताओं की तमाम शर्तों के चलते राज्य योजना का उतना लाभ नहीं ले सके, जितने बजट की व्यवस्था केंद्र सरकार ने कर रखी थी। लिहाजा, राज्यों के अनुरोध पर ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए योजना में कुछ बदलाव करते हुए उसका विस्तार किया गया। आठ क्षेत्रों में सुधारों के लिए प्रोत्साहन के रूप में 30 हजार करोड़ रुपये सहित कुल 1.30 लाख करोड़ रुपये की धनराशि बजट में आवंटित की गई थी।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, एक लाख करोड़ रुपय जो भाग-एक के तहत खुली मद में आवंटित किया गया था, उसका लाभ भी राज्य पूरी तरह नहीं उठा सके। दिसंबर, 2023 तक का आंकड़ा कहता है कि राज्य इस धनराशि के लिए तय मानक, शर्तों और सुधारों के प्रति तुलनात्मक रूप से उदासीन ही रहे, जिसके कारण केंद्र सरकार की ओर से सिर्फ 60,104 करोड़ रुपया ही जारी किया जा सका। इसके बावजूद सरकार ने इस योजना में 75 हजार करोड़ रुपये का आवंटन इस वर्ष के लिए करते हुए अपनी नीयत स्पष्ट कर दी है कि वह राज्यों को साथ लेकर समग्र विकास की ओर बढ़ना चाहती है।

50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना इस वर्ष भी रहेगी जारी

75,000 करोड़ का प्रविधान पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए

बजट में आकांक्षी जिलों और पूर्वी क्षेत्र पर भी नजर

मोदी सरकार के समावेशी विकास की परिभाषा राज्यों से आगे बढ़ते हुए आकांक्षी जिलों और विकासखंडों तक भी पहुंचती है। सरकार ने कहा गया है कि वह पर्याप्त आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने सहित आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के त्वरित विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए तत्पर है। दोहराया गया है कि सरकार इस बात पर पूरा ध्यान देगी कि पूर्वी क्षेत्र और वहां रहने वाले लोग भारत के विकास के सशक्त संवाहक बनें।

विशेषज्ञ टिप्पणी

बुनियादी ढांचे के विकास पर दूरगामी नजरिया

बुनियादी ढांचा, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, सरकार की सोच के केंद्र में है। यही इस बार भी नजर आया जब वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार तेज करने के लिए अपना पूरा संकल्प प्रदर्शित किया।

– **डा. जयजीत भट्टाचार्य**, प्रेसिडेंट, सेंटर फार डिजिटल इकोनमी पालिसी

यह सिर्फ अंतरिम बजट के रूप में लेखानुदान मांगें नहीं हैं, बल्कि विकास और जनकल्याण के केंद्र सरकार के दूरगामी नजरिये की एक और बानगी है। खास बात यह है कि सरकार ने अपनी यह सोच चुनावी साल में दिखाई है, जब कोई भी यह सहज अपेक्षा कर सकता है कि सरकार लोक-लुभावन रास्ते में चलना पसंद करेगी। बुनियादी ढांचा, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, सरकार की सोच के केंद्र में है। यही इस बार भी नजर आया जब वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार तेज करने के लिए अपना पूरा संकल्प प्रदर्शित किया।

रेलवे के लिए ज्यादा आवंटन, कहीं अधिक हवाई अड्डों का बाद ताकि एयरलाइंस की विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और मालभाड़े के लिए डेडिकेटेड कारिडोरों की संख्या बढ़ाने की घोषणा सरकार के इरादों को साफ तौर पर दर्शाती है। यह सड़क निर्माण की एक्सप्रेस रफ्तार से अलग है। इसका मतलब है कि सरकार बुनियादी ढांचे के चतुर्दिक विकास के अपने एजेंडे पर तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उसे इसका अहसास है कि विकसित भारत विकास के इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर गढ़ा जाएगा। सरकार ने सी पोर्ट और रिवर पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी अपनी प्राथमिकता बताया है। इसी तरह डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बनी हुई है। अंतरिम बजट के अपने भाषण में वित्त मंत्री ने इसका ब्योरा दिया कि डिजिटल इन्फ्रा के विकास से किस तरह जनता के पैसों में धांधली पर रोक लगी है और इस धन का अधिक से अधिक इस्तेमाल जनकल्याण के कार्यों में सुनिश्चित हुआ है। वित्त मंत्री ने यदि यह घोषणा भी की कि अगले पांच साल अभूतपूर्व प्रगति के होंगे तो इसका सीधा मतलब है कि उन्हें अब तक किए गए कामों और सरकार की दिशा पर पूरा भरोसा है।

सबके लिए घर के लिए नई योजना की घोषणा को भी जनकल्याण के साथ-साथ इन्फ्रा विकास के अहम कदम के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव होने हैं, जो एक विकसित और सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह इकोनमी के भले के लिए मांग बढ़ाने का सिलसिला जारी रखना चाहती है और यह काम सामाजिक क्षेत्रों, फिजिकल और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में खर्च बढ़ाकर ही किया जा सकता है।

लक्षद्वीप बनेगा पर्यटन हब, बढ़ेगा आध्यात्मिक तीर्थाटन

अरविंद पांडेय • नई दिल्ली

32 वर्ग किलोमीटर है समुद्र से घिरे लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल, होगा बहुमुखी विकास

60 लाख के करीब विदेशी पर्यटक 2023 में देश में आए में एक रिपोर्ट के मुताबिक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के बाद दुनियाभर में चर्चा में आया लक्षद्वीप अब देश के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। बजट में गुरुवार को सरकार ने इसके विकास के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने का एलान किया गया है। इसमें पूरे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों से जुड़ी सुख-सुविधाओं का विकास शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि देश के सबसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। समुद्र से घिरे लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। जहां छोटे-छोटे कई द्वीप समूह हैं, जो पर्यटकों को खूब भाते हैं।

पर्यटन विकास का रोजगार के साथ सीधे जुड़ाव को देखते हुए सरकार ने सभी प्रमुख पर्यटन केंद्रों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से भी लैस करने का फैसला लिया है। इनमें आध्यात्मिक तीर्थाटन भी शामिल है। काशी विश्वनाथ के बाद अयोध्या अब देश के एक बड़े आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में सामने आया है। जहां श्रीराम मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन तीन से चार लाख लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने सभी राज्यों के प्रमुख पर्यटन केंद्रों की न सिर्फ वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग करने का फैसला लिया है, बल्कि उनकी सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता की रेटिंग भी की जाएगी। इतना ही नहीं, राज्यों को अपने प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर सुविधाओं को जुटाने के लिए ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण भी दिया जाएगा।

वैसे भी जी-20 की देशभर के प्रमुख स्थानों पर हुई बैठकों के बाद वहां घरेलू के साथ विदेशी पर्यटकों का भी रुझान बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसका जिक्र भी किया और कहा कि जी-20 के आयोजन के दौरान भारत ने अपनी विविधता और खूबसूरती को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, उससे वहां घरेलू पर्यटकों के साथ ही विदेशी पर्यटकों की भी आवाजाही बढ़ी है। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में लगभग एक करोड़ विदेशी पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में देश में करीब 60 लाख विदेशी पर्यटक आए। लक्षद्वीप से जुड़े सरकार के एलान को मालदीव के साथ हुए ताजा विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है क्योंकि इसके बाद देश से मालदीव जाने वाले लोगों ने लक्षद्वीप के बारे में खोज तेज की है।

****

3,146 करोड़ रुपये अंतरिम बजट में किया गया मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन) का बजट, जबकि पिछले वर्ष इस योजना के तहत 2,326 करोड़ रुपये का बजट था

10,000 करोड़ रुपये पिछले वर्ष प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में खर्च हुए थे, जिसे बढ़ाकर 12,467 करोड़ रुपये किया गया है

पीएम-श्री के बजट आवंटन में बढ़ोतरी

(आंकड़े करोड़ में)

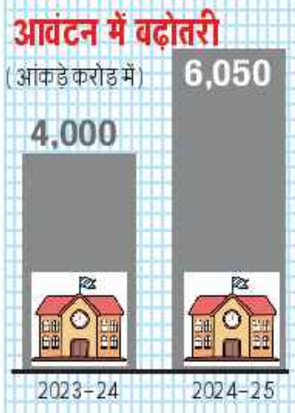

सशक्त नारी से भारत बन रहा समृद्ध, सरकार की 10 में से सात योजनाओं के केंद्र में महिलाएं

बाला दीक्षित • नई दिल्ली

मोदी सरकार का पिछले दस वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए, तो दस में से सात योजनाओं के केंद्र बिंदु में महिलाएं हैं। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सशक्त नारी के जरिये समृद्ध भारत की राह गढ़ने की सोच है। इसी सोच को सरकार ने अपनी कार्यशैली में भी उतारा है। गुरुवार को वित्तमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के लिए दस वर्षों में किए कामों की उपलब्धियां गिनाईं। जिसमें मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के शाप से मुक्त करने के लिए कानून लाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण देने को प्रमुखता से उजागर किया गया।

28% नामांकन महिलाओं का 10 वर्षों के दौरान उच्चतर शिक्षा में बढ़ा है

43% नामांकन साइंस, टेक्नोलाजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स में है

30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण से महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर किया और मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाई

सरकार मानती है कि अगर देश को समृद्ध और सशक्त करना है, तो उसके लिए महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसके लिए उनके जीवन को सुगम बनाने के साथ ही उन्हें शिक्षित करना और सुरक्षा के साथ ही उनके सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इन्हें ध्यान में रखकर ही सरकार ने पिछले दस वर्ष की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं। वित्तमंत्री ने बताया कि उद्यमिता, सुगम्य जीवन और महिलाओं के लिए सम्मान के माध्यम से उनके सशक्तीकरण को गति मिली है। महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण योजना शुरू कर 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। इन वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत बढ़ा है। साइंस, टेक्नोलाजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट (स्टेम) पाठ्यक्रमों में 43 प्रतिशत नामांकन बालिकाओं और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इन सभी उपायों का असर महिलाओं की बढ़ती भागेदारी के रूप में कार्यबल (वर्क फोर्स) में दिखाई दे रहा है। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के भय से मुक्त करने के लिए इसे गैर कानूनी ठहराने वाला कानून लागू किया गया। राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने और उनकी भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रविधान है। महिलाओं को स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य है। देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति में नारी की बराबर की भागीदारी होगी।

महिलाओं और किशोरियों के पोषण का बजट 2,467 करोड़ रुपये बढ़ाया

महिलाओं के स्वास्थ्य और किशोरियों के पोषण पर भी सरकार का काफी ध्यान है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पोषण पीएम) योजना में पिछले वर्ष 10,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि इस वर्ष अंतरिम बजट में इसे बढ़ाकर 12,467 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मिशन शक्ति (महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन) का बजट पिछले वर्ष 2,326 करोड़ था, जो कि इस अंतरिम बजट में बढ़ाकर 3,146 करोड़ रुपये किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए कदम

महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू उन्हें घर का मालिकाना हक मिलना भी है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में 70 प्रतिशत से अधिक घर देने से उनका सम्मान बढ़ा है। एलपीजी कनेक्शन का भी सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिलता है, उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलती है और जीवन आसान होता है। इसका बजट भी बढ़ाया।

बजट बोल

अंतरिम बजट युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाओं का है। इसमें विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी को महत्व दिया है। सबसे खुशी की बात यह है कि एक करोड़ महिलाएं 'लखपति' बन गई हैं। अगला लक्ष्य दो करोड़ और लखपति दीदियों का है।

– **मीनाक्षी लेखी**, विदेश राज्य मंत्री

किशोरियों को सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाने की घोषणा की सराहना करता हूं। मेडिकल कालेजों की स्थापना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित करना स्वास्थ्य के प्रति समग्र प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

– **अदार पूनावाला**, सीईओ, सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया

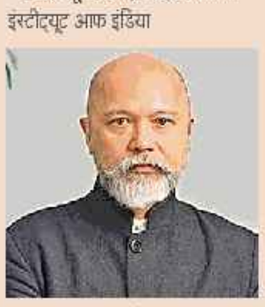

आयुष्मान भारत के तहत आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और सहायकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार महत्वपूर्ण है। टीकाकरण के प्रबंधन को यू-विन प्लेटफार्म का विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगा।

– **डा. रोडिरिको एच ओफ्रिन**, भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि

अंतरिम बजट स्वास्थ्य देखभाल के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाता है। मेडिकल कालेजों के विस्तार से स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी दूर होगी और चिकित्सा शिक्षा में मजबूती आएगी। टीकाकरण से सर्विकल कैंसर से निपटने में मदद मिलेगी।

– **डा. आशुतोष रघुवंशी**, एमडी, फोर्टिस हेल्थकेयर

तीन करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी

महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने को पीएम ने बढ़ाया लक्ष्य, नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम भी जोड़ा

जितेंद्र शर्मा • नई दिल्ली

बजट चुनावी नहीं है और प्रत्यक्ष लक्ष्य भी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं दिखता, लेकिन मोदी सरकार के निर्णय इस संभावना को जरूर मजबूत करते नजर आते हैं कि मातृशक्ति उन्हें 'रिटर्न गिफ्ट' में चुनावी बल देने में संकोच नहीं करेगी। तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने सहित आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर को शामिल करने जैसी घोषणाएं, सीधे तौर पर उन 49 प्रतिशत महिला मतदाताओं को सकारात्मक संदेश देती हैं, जो 2024 के आम चुनाव में 'भाग्य विधाता' साबित हो सकती हैं।

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले गहरे होते जातियों के जंजाल को भेदते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को अपनी प्राथमिकता वाली चार जातियां बताकर बड़ा दांव चल दिया है। सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम और प्रयास इनके इर्दगिर्द सटते भी दिखाई दे रहे हैं। इनमें ही सबसे प्रमुख वर्गों में महिलाएं शामिल हैं, जिनके प्रति अंतरिम बजट में भी सरकार ने भरपूर चिंता जाहिर की है। दरअसल, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से स्वयंसहायता समूहों का विस्तार करते हुए उनसे महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के सतत प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने यानी स्वयंसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये पहुंचाने की दिशा में काम शुरू किया। जब यह संख्या एक करोड़ के करीब पहुंचने वाली थी, इसी बीच 15 अगस्त, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा कर दी कि दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। इसी कार्यक्रम से नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम भी जोड़ा गया। यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि सरकार ने अंतरिम बजट में इस लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाते हुए घोषणा कर दी कि तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।

सरकार ने दावा किया है कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल चुकी है। वे दूसरों के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्हें सम्मान देकर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं, मातृ एवं शिशु देखरेख की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तालमेल के लिए इन्हें एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण-2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। इस निर्णयों से सरकार ने महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरण के साथ ही उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार के इन निर्णयों को उस चुनावी पैटर्न से भी जोड़कर देखा जा सकता है। भाजपा भी इस वर्ग को लेकर अधिक चिंतित और आशान्वित है, क्योंकि एसबीआइ की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में कुल मतदाताओं में 49 प्रतिशत भागीदारी महिला मतदाताओं की होगी।

49% महिलाओं की भागीदारी कुल मतदाताओं में है, इसलिए सरकार महिलाओं को लेकर चिंतित व आशान्वित है

15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने दो करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए घोषणा की थी

3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा, इस योजना का लाभ अभी तक दो करोड़ महिलाओं को मिल रहा था

एसएचजी ला रहे हैं बदलाव

सरकार ने दावा किया है कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं

प्राथमिकताओं में महिलाएं

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले गहरे होते जातियों के जंजाल को भेदते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को अपनी प्राथमिकता वाली चार जातियां बताकर बड़ा दांव चल दिया है

सर्विकल कैंसर से सुरक्षा के लिए बालिकाओं का होगा टीकाकरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पिछली बार बजट में सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष अभियान चलाने के बाद सरकार ने इस बार अंतरिम बजट में महिलाओं में सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए अहम फैसला किया है। इसके लिए नौ से 14 साल की बालिकाओं के टीकाकरण का अभियान चलेगा। भारत में हर साल सर्विकल कैंसर के 1.25 लाख मामले सामने आते हैं और इससे सालाना 75 हजार की मृत्यु हो जाती है।

देश में नौ से 14 साल की बालिकाओं की संख्या लगभग आठ करोड़ है और सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी को सर्विकल कैंसर का टीका लगाने का अभियान चलाएगी। इस उम्र की अधिकांश बच्चियों के स्कूल में होने के कारण टीकाकरण अभियान स्कूलों में चलाया जाएगा, लेकिन साथ ही सामान्य राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष में भी इसे शामिल किया जा सकता है। महिलाओं में सर्विकल कैंसर के मामले काफी पाए जाते हैं। इसके लिए एचपीवी (ह्यूमन पपिल्लोमा वायरस) वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है, लेकिन कीमत अधिक होने के कारण इसका उपयोग सीमित है। उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण की स्थिति में इसकी कीमत भी कम होगी। वैसे सरकार अभियान के तहत मुफ्त टीका उपलब्ध कराएगी।

कोरोना टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफार्म की तरह से सामान्य टीकाकरण अभियान के प्रबंधन के लिए यू-विन प्लेटफार्म भी तैयार किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यू-विन प्लेटफार्म और मिशन इंद्रधनुष की सहायता से बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एसआइआइ) के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि हमें प्रण करना चाहिए कि एचपीवी से बचा जा सके और वैक्सीन सबको आसानी से उपलब्ध हो।

9 से 14 साल की उम्र की लगभग आठ करोड़ बालिकाओं को लगेगा टीका

'जीडीपी' माडल से विकास की नई उड़ान

राजीव कुमार, नई दिल्ली: कोरोना काल और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत पिछले तीन वर्षों से जी-20 समूह में सबसे अधिक विकास करने वाला देश बना हुआ है। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार इस उपलब्धि के लिए जीडीपी माडल और आर्थिक प्रबंधन को जिम्मेदार बता रही है।

जीडीपी माडल में गवर्नेंस (प्रशासनिक सुधार), डेवलपमेंट (विकास) और परफार्मेंस (प्रदर्शन) शामिल है। सरकार ने सही नीति बनाई और फैसले लिए। कोरोना काल के दौरान आत्मनिर्भर भारत मिशन स्कीम लांच की। निश्शुल्क राशन देने का फैसला किया। मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम चलाई। समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए महंगाई रोकने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन जैसी नीतियां बनाकर लागू किया। नतीजा, देश विकास करने लगा। जीवन आसान हुआ और लोगों की आय बढ़ने लगी। इससे देश अच्छा प्रदर्शन करने लगा और हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए।

भू-राजनीतिक चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे अधिक विकास करने वाला देश

आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी भारत की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है

जीडीपी का ही नतीजा है कि लोग पहले की तुलना में आराम से रह रहे हैं और अधिक कमा रहे हैं। दस वर्षों में कमाई औसतन 50 प्रतिशत बढ़ी है। महंगाई कम है और बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। जीडीपी माडल ने देश की अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर ला दिया है।

– **निर्मला सीतारमण**, वित्त मंत्री

10 वर्षों में इन सात सेक्टरों पर किया गया फोकस

- सभी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर (फिजिकल और डिजिटल दोनों) पर जोर रहा और रोजगार बढ़ा और आगामी वित्त वर्ष के लिए भी पूंजीगत खर्च में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
- देश के सभी क्षेत्रों को आर्थिक विकास में भागीदार बनाया गया और नार्थ ईस्ट को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया।
- डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो 21वीं सदी में आर्थिक विकास की गाड़ी है। डिजिटल भुगतान में हम सबसे आगे हो गए।
- एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी को लागू किया गया।
- वित्तीय सेक्टर को मजबूत बनाया गया, जिससे बचत, ऋण सभी में बढ़ोतरी हुई।
- विदेशी निवेश प्रोत्साहन के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथारिटीज बनाई गई।
- सरकार ने महंगाई को काबू में रखा।

विकसित भारत के लक्ष्य के आड़े नहीं आएगी बढ़ती जनसंख्या

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

- जनसंख्या और जनसांख्यिकी बदलावों पर नजर रखने के समिति के गठन का एलान
- विकसित भारत की यात्रा में इससे पैदा होने वाली चुनौतियों को लेकर देगी अपनी सिफारिशें

तेजी से बढ़ती जनसंख्या आने वाले दिनों में विकसित भारत के लक्ष्य की राह का रोड़ा न बन जाए इसको लेकर सरकार अभी से सतर्क है। यही वजह है कि सरकार ने बजट में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का एलान किया है, जो न सिर्फ तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उससे पैदा होने वाली चुनौतियों पर नजर रखेगी। साथ ही इससे पैदा होने वाले जनसांख्यिकी बदलावों को भी परखेगी। इस कमेटी का गठन कब तक हो जाएगा, यह अभी साफ नहीं है।

सरकार के इस कदम को भविष्य की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में विकसित भारत को लेकर जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है, वह वर्तमान जनसंख्या रफ्तार और क्षेत्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। ऐसे में यदि बीच में इसमें किसी तरह का बड़ा बदलाव हुआ तो देश को 2047 तक विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उनमें और समय लग सकता है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार की ओर से गठित यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति समय-समय पर जनसंख्या में बढ़ोतरी और जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर विकसित भारत के लक्ष्य में जुटी एजेंसियों को सतर्क करती रहेगी।

गौरतलब है कि देश की आबादी मौजूदा समय में 140 करोड़ से ज्यादा है। जो आबादी के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि चीन की मौजूदा समय में आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है। तेज बढ़ती आबादी के चलते जब तक कोई संसाधन जुटाए जाते है, तब तक एक बड़ी आबादी खड़ी हो जाती है। इसके चलते सदैव संसाधनों की कमी बनी रहती है। माना जा रहा है कि तेजी से बढ़ती आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान करके उन क्षेत्र में समिति की सिफारिश पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभियान भी चलाया जा सकता है।

2024 में भी जनगणना, एनपीआर शुरू होने की संभावना नहीं

- अंतरिम बजट में केवल 1277 करोड़ रुपये आवंटित
- आम चुनाव के कारण जनगणना टलने की संभावना

नई दिल्ली, प्रेट्र : जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) इस साल भी शुरू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने इसके लिए केवल 1277 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके लिए 2021-22 से 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, उसकी तुलना में यह काफी कम हैं। 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में 8,754.23 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2021 आयोजित करने और 3,941.35 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

जनगणना और एनपीआर को अपडेट करने की कवायद एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक देशभर में की जानी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दी गई थी। जनगणना का काम अब भी रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। अधिकारियों ने कहा कि चूंकि इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए जनगणना 2024 में होने की संभावना नहीं है। अंतरिम बजट के अनुसार, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 1277.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आने की संभावना है। अब जब भी जनगणना होगी, वह डिजिटली की जाएगी। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। एनपीआर को उन नागरिकों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, जो सरकारी गणनाकर्ताओं के बजाय स्वयं जनगणना फार्म भरना चाहते हैं। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्व गणना पोर्टल डिजाइन किया है, जिसे अभी लांच नहीं किया गया है। स्व गणना के दौरान आधार या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अनुसार इस बार की जनगणना में 31 सवाल पूछे जाएंगे।

भविष्य का भारत

सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन को दी गति

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल और आइटी हार्डवेयर पीएलआइ योजना सहित विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग कार्यक्रमों के लिए 15,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्रों के लिए 4,203 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का प्रस्ताव है, जिससे गुजरात में माइक्रोन द्वारा स्थापित संयंत्र, फाक्सकान और एचसीएल के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तावित संयंत्र जैसे परियोजनाओं को लाभ होगा। प्रस्तावित आवंटन में कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सेंसर संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाएं शामिल हैं।

भारत में सेमीकंडक्टर फैब या इलेक्ट्रानिक चिप प्लांट स्थापित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये, मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के लिए 900 करोड़ रुपये, डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,903 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने मोबाइल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना के आवंटन को 2023-24 के 4,489 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 6,125 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार ने आइटी हार्डवेयर पीएलआइ के लिए केवल 75 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया है। इस क्षेत्र में पांच सालों में लगभग 17,000 करोड़ रुपये के कुल प्रोत्साहन का वादा किया गया है। सरकार ने सी-डाट का बजट आवंटन 2023-24 के 590 करोड़ रुपये से घटाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है। बजट दस्तावेज़ के अनुसार, दूरसंचार हार्डवेयर पीएलआइ के लिए किसी तरह का आवंटन नहीं किया गया है।

15,500 करोड़ रुपये सेमीकंडक्टर मिशन, मोबाइल व आइटी हार्डवेयर योजना सहित इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए आवंटित

स्टार्टअप में निवेश के लिए कर प्रोत्साहन की अवधि बढ़ी

सरकार ने सावरेन वेल्थ या पेंशन फंड द्वारा स्टार्टअप में किए गए निवेश के लिए कर प्रोत्साहन की अवधि को मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा अब तक 1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी की पार्टनर गौरी पुरी ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक सरकार ने नीतिगत संयम बरता है और किसी भी कर प्रस्ताव का एलान नहीं किया गया है। डेलाइट इंडिया की पार्टनर दीपा शेषाद्रि ने कहा कि तकनीक के विकास में एक परिभाषित कानूनी ढांचा आवश्यक है।

विकसित भारत का रोडमैप तैयार करने वाला है बजट : शाह

- बजट भाषण मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करता है
- विकसित भारत की भव्य इमारत खड़ी की जा रही है

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अंतरिम बजट 2024-25 विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए रोडमैप तैयार करने वाला है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण भारत को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की यात्रा में पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को रेखांकित करता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर 'विकसित भारत बजट' हैशटैग के पोस्ट किया, बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन कार्यों की बुनियाद पर विकसित भारत की भव्य इमारत खड़ी की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बजट भाषण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार। बाद में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का 'विकसित भारत बजट' देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए अवसर लेकर आया है।

संसद भवन परिसर में गुरुवार को भाजपा सदस्य राम कृपाल यादव एवं रमेश पोखरियाल निशंक के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

विपक्ष ने अंतरिम बजट को बताया चुनावी कवायद

नई दिल्ली, एएनआइ: बजट के बाद कई विपक्षी नेताओं ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर अपना खर्च चला रही है। यह लेखानुदान है, जिसका एकमात्र लक्ष्य सरकार को पहली तिमाही के लिए वित्तीय स्थिति में बनाए रखना है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वित्त मंत्री ने कई चीजों के बारे में बात की जो अस्पष्ट भाषा में हैं, जैसे आत्मविश्वास और उम्मीद इत्यादि। लेकिन जब ठोस आंकड़ों की बात आती है, तो बहुत कम आंकड़े उपलब्ध होते हैं। शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह बजट खोखला है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि जब डिलीवरी की बात आती है तो बजट शून्य हो जाता है। आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने बजट को निराशाजनक बताया।

****

नैसकाम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 31,000 से अधिक तकनीकी स्टार्ट अप के लिए संचयी फंडिंग वर्ष 2019 से 2023 तक 70 बिलियन डालर से अधिक हो गई है।

900 मिलियन हो सकती है देश में मोबाइल वालेट उपयोगकर्ताओं की संख्या

63 लाख से अधिक लेनदेन हुए हैं ई-कामर्स प्लेटफार्म पर

10 वर्षों में आइआइटी की बढ़ी संख्या

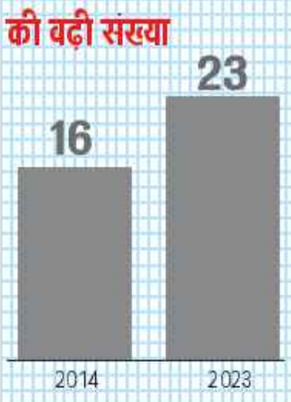

भारत में गतिमान है डिजिटल अर्थव्यवस्था

डिजिटल क्रांति और समावेशी विकास में प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है। सरकार 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था को 1,000 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचाना चाहती है। गूगल, टेमासेक व बैन एंड कंपनी और बैंक आफ अमेरिका की रिपोर्ट भी इस पर मुहर लगाती है। अनुमान है कि यह लक्ष्य 2030 तक प्राप्त होगा। रिपोर्ट 'भारतीय अर्थव्यवस्था-एक समीक्षा' में कहा गया है कि पिछले नौ वर्ष में हुए सुधारों में तकनीक व डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग से यह संभव हुआ है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने में स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), कंप्यूटर के बुनियादी ढांचे का निर्माण और ई-कामर्स को प्रोत्साहन प्रमुख कारक रहेंगे। 2016 में लान्च होने के बाद से यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2023 तक 800 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

ऐसे डिजिटल हो रहा देश

वर्ष 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था 1,000 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचाने की उम्मीद

वर्ष 2016 में लान्च होने के बाद से यूपीआ के जरिये भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई

पिछले वर्ष 950 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप स्थापित हुए

स्टार्टअप इंडिया में 2.1 लाख ऋण दिए गए, 84 प्रतिशत महिला उद्यमियों को

बीते छह वर्ष में यूपीई से भुगतान की संख्या और राशि का आंकड़ा

नोट: इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार

एआइ की महत्वपूर्ण भूमिका

1000 अरब की डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में एआइ की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। भारत एआइ कार्यक्रम की कल्पना इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर सामाजिक प्रभाव के समावेशन, नवाचार और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा देश

भारत सेमीकंडक्टर मिशन को डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रानिक व सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए 76,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ सेमीकान इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी देकर गति दी गई है।

1.14 लाख स्टार्टअप, 12 लाख से अधिक नौकरियां

वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की हालिया समीक्षा में कहा है कि देश में 1.14 लाख से अधिक स्टार्टअप ने अब तक 12 लाख से अधिक नौकरियां पैदा की हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा तकनीकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बना है।

ई-कामर्स बाजार 31 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद

भारत में ई-कामर्स डिजिटल भुगतान में वृद्धि का प्रमुख चालक है। भारत में ई-कामर्स बाजार 31 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है। ई-कामर्स बाजार की वृद्धि से भारत में आनलाइन खरीदारों की संख्या बढ़ी है, जिसके वर्ष 2025 तक 220 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

बजट बोल

अंतरिम बजट ने प्रशंसनीय रूप से सरकारों द्वारा अक्सर अपनाए जाने वाले किसी भी लोकलुभावन उपायों को खारिज कर दिया। लेकिन भारत निश्चित रूप से अपने बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय बजट पर अधिक काम कर सकता है, जिसमें नाममात्र 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के स्तर को 60 अरब डालर तक बढ़ाने के लिए कुछ साहसिक उपायों की आवश्यकता है।

गोपीचंद हिंदुजा, चेयरमैन, हिंदुजा समूह

यह एक उत्कृष्ट बजट है जो भारत की प्रभावशाली विकास गाथा को और भी अधिक गति देगा। राजकोषीय समेकन के साथ सरकारी पूंजीगत व्यय का उच्च स्तर निजी निवेश को बढ़ाने का सही तरीका है। तीन नए आर्थिक रेलवे गलियारे उद्योग के लिए लाजिस्टिक्स में गेमचेंजर साबित होंगे। वित्त मंत्री का युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना उत्साहजनक है जो भारत के परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे।

अनिल अग्रवाल, चेयरमैन, वेदांता समूह

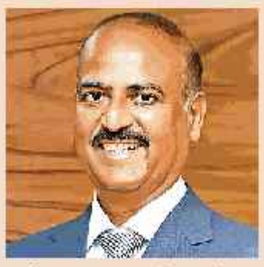

मार्च 2025 तक स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का विस्तार और करदाता सेवाओं में सुधार पर ध्यान देना कराधान को सरल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण का आवंटन एक सकारात्मक कदम है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देने वाली राजकोषीय घोषणाओं के साथ-साथ उड़ान योजना के माध्यम से हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार, परिवहन और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के संकल्प को दर्शाता है।

तपन सिंघल, एमडी व सीईओ, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस

शहरों में घर खरीदें या बनाएं, सरकार तैयार

किराए से मिलेगी आजादी, झुग्गी, चाल, अनधिकृत कालोनी वाले लोग भी आएंगे योजना के दायरे में

मनीष तिवारी ● नई दिल्ली

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में छतविहीन दो करोड़ और परिवारों को पक्के आवास और शहरों में अपने ठिकाने के लिए भंवर में फंसे मध्यम वर्ग के लिए नई आवासीय योजना पर आगे बढ़ने का एलान कर केंद्र सरकार ने आम चुनाव के पहले शहरों और गांवों की बड़ी आबादी को अपनी ओर आकर्षित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरों में किराए पर रह रहे लोगों के साथ ही झुग्गी-झोपड़ियों में गुजर-बसर करने वालों की पीठ पर यह एलान करते हुए हाथ रखा कि उन्हें अपना घर हासिल करने में पूरी मदद दी जाएगी।

इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही कर चुके हैं, जिसके लिए नियम-कायदे तय किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट भाषण के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने संकेत दिए कि यह कम ब्याज दर वाले लोन पर आधारित योजना हो सकती है। शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी पिछले माह कह चुके हैं कि जैसे ही इस योजना की नियम-शर्तें तय हो जाती हैं, इसके क्रियान्वयन में किसी तरह की देरी नहीं होगी।

सीतारमण ने अंतरिम बजट में कहा कि समावेशी विकास के अपने संकल्प की पूर्ति के लिए मोदी सरकार ने सभी आश्रयहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरा जोर लगाया है। इसी कड़ी के तहत मोदी सरकार किराए के घरों में रह रहे मध्यम आय वर्ग के लोगों, झुग्गी, चाल या अन्य अनधिकृत कालोनियों में किसी तरह गुजर-बसर कर रही आबादी को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए योजना शुरू करने जा रही है। माना जा रहा है कि शहरों में चल रही पीएम आवास योजना के घटक सीएलएसएस यानी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जैसे कार्यक्रम के जरिये इस योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसके तहत साढ़े तीन से साढ़े छह प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी के जरिये लाभार्थी को सहायता दी जाती है।

सीतारमण ने यह भी रेखांकित किया कि कोविड की चुनौती के बावजूद पीएस आवास योजना (ग्रामीण) पर क्रियान्वयन थमा नहीं। इस योजना में तीन करोड़ लोगों को घर देने का लक्ष्य पूरा ही होने वाला है। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ घर और बनाए जाएंगे। इसके सहारे पक्के घर की आकांक्षा वाले परिवारों की बढ़ी हुई संख्या को भी इस योजना में कवर किया जा सकेगा।

सबको आवास के संकल्प के साथ पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत एक अप्रैल, 2016 को की गई थी ताकि गांवों में रहने वाली निर्धन आबादी को पक्की छत मुहैया कराई जा सके। कुछ गैरभाजपा शासित राज्यों के ठंडे रुख के बावजूद इस योजना ने पूरे देश में सार्थक सामाजिक-आर्थिक असर डाला है।

इसके तहत अब तक 2.95 करोड़ घर या तो उपलब्ध कराए जा चुके हैं या फिर आवंटित होने वाले हैं। योजना में केंद्र और केंद्रशासित क्षेत्रों को एक इकाई मानते हुए सीधे पैसा स्थानांतरित किया जाता है और फिर वे जिलों, ब्लाक या निकायों में मांग के अनुरूप इसका इस्तेमाल करते हैं।

सरकारी डाटा के मुताबिक 2018-19 से 2022-23 के बीच केंद्र सरकार 1,60,853 करोड़ रुपये राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को दे चुकी है। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि गांवों में 70 प्रतिशत से अधिक घर पात्र महिलाओं को दिए गए हैं।

पीएम आवास योजना को (शहरी) 23,175 करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए इस बार 26,170 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले बार के मुकाबले करीब साढ़े चार प्रतिशत ज्यादा है। पीएम आवास योजना के तहत शहरों में अब तक लगभग 1.20 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।

एक बड़ी आबादी को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए सरकार की योजना है ● फाइल

70 प्रतिशत से अधिक घर पात्र महिलाओं को दिए गए हैं। यह इस योजना की एक प्रमुख विशेषता है।

1.6 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार दे चुकी है विभिन्न राज्यों को 2018-19 से 2022-23 के बीच

2.95 करोड़ घर या तो उपलब्ध कराए जा चुके हैं या फिर आवंटित होने वाले हैं पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में

पिछले दस वर्षों में तैयार किया गया कृषि विकास का आधार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की नीति का प्रतिफल यह है कि कृषि विकास एवं किसानों की समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11.80 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रत्येक वर्ष छह हजार रुपये मिल रहे हैं। इससे खेती के लिए न्यूनतम पूंजी की समस्याओं का समाधान हुआ है।

बजट की प्रमुख विशेषताओं में किसान कल्याण एवं उत्पादन-उत्पादकता बढ़ाना है। इसके लिए कृषि से जुड़ी लगभग प्रत्येक योजना की राशि में वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राशि 6,150 करोड़ से बढ़ाकर 7,553 करोड़ कर दी गई है। नीली क्रांति एवं डेरी विकास की राशि में निरंतर वृद्धि की जा रही है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को बड़ा सहारा दिया है। अभी चार करोड़ से ज्यादा किसान बाढ़-सूखा की आशंका से मुक्त हैं। फसलें बर्बाद होने की स्थिति में उन्हें बीमा योजना के तहत भरपाई कर दी जा रही है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से लगभग 38 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। रोजगार के करीब 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। दानेदार उर्वरकों के बदले नैनो यूरिया के साथ नैनो डीएपी का चलन भी बढ़ रहा है। इससे कृषि लागत में काफी हद तक कमी आती जा रही है।

इलेक्ट्रानिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1,361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है। इससे 1.8 करोड़ किसान जुड़े हैं, जिनका प्रति वर्ष तीन लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से भी जोड़ने में सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों एवं 60 हजार व्यक्तियों को ऋण सुविधा दी गई है। अनेक कार्यक्रमों के जरिये 'अन्नदाता' को देश-दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है। किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के अतिरिक्त अन्य लोगों का हित भी जुड़ा होता है।

पीएम किसान सम्मान निधि ने खेती के लिए आवश्यक पूंजी का किया समाधान

1,361 मंडियों को एकीकृत करने से किसानों का हो रहा तीन लाख करोड़ का कारोबार

वित्त मंत्री ने समझाए सामाजिक न्याय व पंथनिरपेक्षता के अर्थ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सामाजिक न्याय का मतलब कुछ जातियों का उत्थान और पंथनिरपेक्षता का अर्थ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के घिसे-पिटे ढर्रे के विपरीत केंद्र सरकार ने इसे विकास के संदर्भ में अलग अर्थ में प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में सामाजिक न्याय और पंथनिरपेक्षता का सरकार के लिए असली मतलब भी समझाया।

सीतारमण ने कहा कि पहले सामाजिक न्याय मुख्य तौर पर एक राजनीतिक नारा था, लेकिन मोदी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन पद्धति है। वित्त मंत्री का इशारा उन दलों, खासकर क्षेत्रीय दलों की ओर था, जो पिछले तीन-चार दशक से सामाजिक न्याय को अनुसूचित जातियों-जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के अपने वोट बैंक वाले एजेंडे तक सीमित रखे हुए हैं।

सीतारमण ने कहा कि सभी पात्र लोगों को शत-प्रतिशत लाभान्वित करने का दृष्टिकोण ही सच्चे और स्पष्ट अर्थों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति है। कार्य रूप में यही पंथनिरपेक्षता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है और भाई-भतीजावाद पर लगाम लगती है।

वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा गिनाई गईं चार जातियों- गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और उनके कल्याण को मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय और पंथनिरपेक्षता के प्रति सरकार की इस सोच ने ही यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ सीधे सभी पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। संसाधनों का वितरण निष्पक्ष रूप से किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत कुछ भी हो, उसकी अवसरों तक पहुंच हो रही है।

> हमारी सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। इसमें सभी जातियों और सभी स्तरों के लोग शामिल हैं। हमारे लिए सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा नहीं है।
> - **निर्मला सीतारमण**, वित्त मंत्री

समग्र खेती की जमीन पर उगेंगी किसानों की आय की फसलें

अरविंद शर्मा ● नई दिल्ली

कृषि की कार्यशैली में सुधार एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अंतरिम बजट में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ विभिन्न फसलों की कटाई के बाद की क्षति को कम करने पर समग्रता में जोर दिया गया है। गेहूं-चावल की तरह तिलहन एवं दलहन में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की तैयारी है। इसके लिए कार्यनीति बनाने की घोषणा की गई है।

किसानों को 'अन्नदाता' बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सबसे अधिक जोर कृषि क्षेत्र में मूल्य-वर्द्धन एवं किसानों की आय बढ़ाने पर है। सरकार का मानना है कि किसान कल्याण की योजनाओं एवं कृषि में व्यापक सुधारों के चलते पिछले 10 वर्षों में किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है, किंतु तेज वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खेती की परंपरागत शैली को बदलना पड़ेगा। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण क्षमता में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला, विपणन एवं ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को भविष्य में बढ़ावा देने की तैयारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, उचित रखरखाव के अभाव में देश में खेतों से घर पहुंचने तक लगभग 15 से 20 प्रतिशत फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए भंडारण क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि पर काम किया जा रहा है। अभी देश में उत्पादन का सिर्फ 47 प्रतिशत अन्न भंडारण की ही व्यवस्था है। किसानों की समावेशी आय में वृद्धि के लिए सरकार कृषक-केंद्रित नीतियों के साथ ही एमएसपी में लगातार वृद्धि, फसल बीमा के माध्यम से नुकसान को न्यूनतम करना एवं स्टार्टअप के जरिये प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों को बढ़ावा देगी।

पशुपालन अवसंरचना पर खर्च होंगे तीन हजार करोड़: बजट के तुरंत बाद कैबिनेट ने किसानों की आय में वृद्धि के प्रति गंभीरता दिखाते हुए पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (आइडीएफ) को अगले दो वर्षों तक विस्तार दे दिया। इस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 29,610.25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके तहत डेरी प्रसंस्करण, विभिन्न उत्पाद, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन फार्म, पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन एवं पशु चिकित्सा व वैक्सीन-दवा उत्पादन के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र की ओर से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नाबार्ड एवं एनडीडीबी के जरिये दो वर्ष के लिए बिना ब्याज 90 प्रतिशत तक ऋण एवं आठ वर्षों तक तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा मिलेगी। निजी कंपनियां, एफपीओ एवं एमएसएमई इसका लाभ उठा सकती हैं।

केंद्र सरकार डेरी संयंत्रों के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए डेरी सहकारी समितियों को 750 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी कोष से लिए गए ऋण की 25 प्रतिशत तक ऋण गारंटी भी प्रदान करेगी। इस योजना से डेयरी, मांस और चारा क्षेत्र की प्रसंस्करण क्षमता दो से चार प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

मछली पालन में 55 लाख रोजगार सृजन: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को विस्तार देते हुए केंद्र सरकार ने नीली क्रांति अर्थात मछली पालन के प्रति भी संकल्प दिखाया है। इस योजना के माध्यम से 55 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। साथ ही सी-फूड निर्यात एक लाख करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में कहा गया है कि पांच इंटीग्रेटेड एक्वापार्क बनाए जाएंगे। जलकृषि की उत्पादकता अभी तीन लाख टन प्रति हेक्टेयर है। इसे बढ़ाकर पांच लाख टन करने की तैयारी है। मत्स्य पालन के लिए अलग मंत्रालय बनाने के बाद से इनलैंड फिशरी और जलीय कृषि का उत्पादन दोगुना हो गया है।

पशुपालन, मछली पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण की समग्र कृषि से बढ़ेगी किसानों की आय

फसलों की कटाई के बाद की क्षति को कम करने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर

गेहूं-चावल की तरह तिलहन-दलहन में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बनेगी कार्यनीति

गेहूं की फसल में खाद डालते किसान ● फाइल फोटो

आत्मनिर्भर तिलहन अभियान

सरकार का लक्ष्य दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की है। बजट में तिलहन की विभिन्न फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी के उत्पादन-उत्पादकता बढ़ाने की कार्यनीति तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहन, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य-वर्धन और फसल बीमा को शामिल किया जाएगा। भारत में दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर भी देश दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है। केंद्र का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में दलहन में आत्मनिर्भर बनने का है।

विशेषज्ञ टिप्पणी

देश की कृषि में आधारभूत परिवर्तन जरूरी

पूर्वी भारत का सर्वांगीण विकास करके देश को संपन्न राष्ट्र बनाने के वादों को यह बजट पुरजोर तरीके से पूरा करने वाला है। 'सबका प्रयास' के समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में कृषि में आधारभूत परिवर्तन की जरूरतों को भी पूरा करने में यह सक्षम हो सकता है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विश्व सहकार आर्थिक मंच का गठन भी पिछले ही वर्ष हुआ है। भारतीयों के जरिये इस नवाचारी वैश्विक मंच पर सहकारिता के मूल्यों को प्रतिस्थापित करेगा। साथ ही सहकारिता क्षेत्र के हितधारकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने 54 मुख्य पहल के क्रियान्वयन के तहत विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिये कृषि उत्पादों का निर्यात आसान हो सकेगा, जिससे किसानों को उनकी उपज के अधिक दाम मिल सकेंगे। प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड व जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड पहले से ही किसानों के लाभ में वृद्धि कर रही है। किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण इन समितियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के आधार पर सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करने की बात कही गई है। तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान पोर्टल जैसे किसान-केंद्रित पहल का उद्देश्य दाल किसानों को सशक्त बनाना है। उन्हें नेफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा खरीद और बैंक हस्तांतरण के माध्यम से आसानी से कीमतें मिल जाएंगी। इससे दाल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात निर्भरता कम होगी।

तूर (अरहर) दाल खरीद पोर्टल भारत के सर्वांगीण विकास की नई क्रांति के व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो गेहूं-धान जैसी पारंपरिक फसलों के साथ-साथ दालों और तिलहनों को भी सम्मिलित करेगा। केंद्र की पहल से दाल खरीद, भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्रसंस्करण, विपणन एवं ब्रांडिंग सहित फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी-सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पांच एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। 'नेट-जीरो' कार्बन उत्सर्जन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से पराली की राजनीति को विराम मिलेगा।

> नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिये कृषि उत्पादों का निर्यात आसान हो सकेगा, जिससे किसानों को उपज के अधिक दाम मिल सकेंगे। किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण इन समितियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बिनोद आनंद, एक्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वर्ल्ड को-आपरेशन इकोनामी फोरम एंड एसी रिफार्म

अनुसंधान से जुड़े अपने सपने पूरे कर सकेंगे युवा

अरविंद पांडेय ● नई दिल्ली

युवाओं को अनुसंधान से जुड़े अपने सपनों को पूरा करने में अब पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। वे जितना चाहेंगे अब उतना पैसा मिलेगा, वह भी ब्याज मुक्त होगा। बजट में अनुसंधान क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के सपनों को उड़ान देने को लेकर सरकार ने बड़ा एलान किया है। इसके तहत 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का एक फंड बनाया गया है। इससे नए और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान या फिर नई पहलों के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं के सपनों को उड़ान मिलने के साथ अनुसंधान में तेजी आएगी और रोजगार भी बढ़ेंगे।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के इस एलान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जय अनुसंधान के नारे से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका जिक्र भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपने बजट भाषण में किया और कहा कि नई पहल ही विकास का आधार है। अनुसंधान को बढ़ावा देने की वैसे तो सरकार की यह कोई पहली पहल नहीं है, उससे पहले सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का एलान किया था। साथ ही 2021 के बजट में इस पर पांच वर्षों में 50 हजार करोड़ खर्च करने का भी एलान किया था। जिस पर शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर तेजी से काम शुरू किया गया है। इसका परिणाम भी हाल में जारी हुई उच्च शिक्षण संस्थानों की विश्वस्तरीय रैंकिंग में दिखा है।

अनुसंधान के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने का सरकार का एलान इसलिए भी अहम है, क्योंकि देश भले ही विकसित होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में अभी भी वह विकसित देशों की तुलना में काफी पीछे है। अमेरिका मौजूदा समय में अपनी जीडीपी का करीब 2.9 प्रतिशत अनुसंधान और नवाचार पर खर्च करता है, जबकि स्वीडन 3.2 प्रतिशत और स्विटजरलैंड करीब 3.8 प्रतिशत फीसद खर्च करता है, जबकि भारत 2014 से पहले तक सिर्फ 0.5 प्रतिशत ही खर्च करता था, जबकि अब वह करीब एक प्रतिशत खर्च कर रहा है।

इसके साथ ही इस पहल से भारतीय प्रतिभाओं के दूसरे देशों में होने वाला पलायन भी अब थमेगा। अनुसंधान व नवाचार के क्षेत्र में वित्तीय मदद नहीं मिलने से अभी तक भारतीय प्रतिभाएं दूसरे देशों में चली जाती थीं।

50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के लिए बनाया एक लाख करोड़ का फंड

10 वर्षों में 3000 नए आइटीआइ, 390 नई यूनिवर्सिटी

वित्त मंत्री ने बताया कि उदीयमान भारत के लिए पीएम-श्री स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों के समग्र विकास पर जोर दे रहे हैं। 10 वर्षों में देश में 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। 3,000 नए आइटीआइ खोले गए। इसके साथ ही इस अवधि में सात आइआइटी, 16 ट्रिपल आइटी, सात आइआइएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय खोले गए हैं।

****

केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में आरबीआइ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और अन्य वित्तीय संस्थानों से लाभांश के रूप में 1.02 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान जताया है।

20 शहरों में मेट्रो सिस्टम की आपरेशनल लंबाई इस समय 895 किलोमीटर है। 986 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है।

10 साल में तीन गुना से अधिक बढ़े एम्स

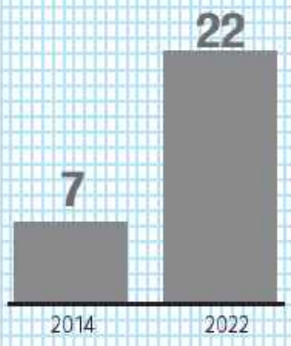

11 लाख करोड़ की लागत से बनेंगे तीन नए रेल कारिडोर

अरविंद शर्मा • नई दिल्ली

अगले वित्त वर्ष में सुरक्षित, सुगम और समय पर रेल यात्रा के लिए बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। तीन नए रेल कारिडोर का निर्माण किया जाएगा। इनमें पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा एवं तीसरा उच्च यातायात घनत्व (अमृत चतुर्भुज) गलियारा शामिल है। इन तीनों कारिडोर के निर्माण पर 11 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा अगले पांच वर्षों के दौरान 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार बोगियों को वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। अंतरिम बजट में रेलवे को अगले वित्त वर्ष के लिए कुल 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अभी देश में ट्रेनों के माध्यम से प्रति वर्ष करीब 700 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। आगे आधारभूत संरचनाओं को इस तरह बढ़ाने की तैयारी है कि प्रति वर्ष लगभग एक हजार करोड़ लोग यात्रा कर सकें। मेट्रो रेल एवं नमो भारत जैसी प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में प्रत्येक हफ्ते में कम से कम एक वंदे भारत चलाने का लक्ष्य है। भर्ती अभियान को भी व्यवस्थित करते हुए वर्ष में अलग-अलग ग्रुप की चार बार निर्धारित समय पर रिक्तियां निकाली जाएंगी। जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर में नौकरी के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीनों नए रेल कारिडोर पर अगले पांच साल में काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मल्टी-माडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत इन परियोजनाओं पर काम होगा।

2.52 लाख करोड़ रुपये रेलवे को बजट में आवंटित किए गए

हर साल जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर में होंगी रेलवे में भर्तियां

40 हजार रेल बोगियां वंदे भारत के पैटर्न पर अपग्रेड होंगी

रेलवे के लिए तैयार नया रोडमैप विकसित भारत की झांकी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए एक नया रोडमैप तैयार हुआ है, जो विकसित भारत की झांकी है। पहले 15 हजार करोड़ का बजट होता था, किंतु आज रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए दो लाख 55 हजार 393 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। पिछले वर्ष यह राशि दो लाख 40 हजार करोड़ थी। सुरक्षा और विद्युतीकरण पर बल दिया जा रहा है। सभी जोनों का विद्युतीकरण कुछ महीने में पूरा हो जाएगा।

पांच वर्षों में 40 हजार किमी रेल ट्रैक बनेगा

रेलवे गरीब एवं मध्यम वर्ग का मुख्य यातायात साधन है। इसकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। पिछले दस वर्षों में 26 हजार किमी ट्रैक बने हैं। इस वर्ष 5,500 किमी से ज्यादा ट्रैक बनाए जाएंगे। बुलेट ट्रेन का भी ट्रैक बनाया जा रहा है। जरूरत के अनुसार रेल ट्रैक की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जहां अभी दो लाइन हैं, उन्हें चार लाइन किया जाएगा। इसी तरह चार लाइन को छह लाइन किया जाएगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 40 हजार किमी रेल ट्रैक बनाया जाएगा।

यात्रा के दौरान सुरक्षा पर जोर

रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कवच (आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन) सिस्टम का विस्तार किया जाएगा। अन्य देशों की ट्रेनों में इसे 1991 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत में इसे पहली बार 2016 में अनुमोदित किया गया था। पावर सेक्टर में 269 और आप्टिकल में तीन हजार 40 कवच लग चुके हैं। रेलवे से यात्रा में प्रदूषण का उत्सर्जन 90% कम होता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तस्वीर के लिए रेल यात्रा की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है।

2030-31 तक नो वेटिंग लिस्ट

रेल मंत्री ने आश्वस्त किया है कि वर्ष 2030-31 तक रेलवे में वेटिंग की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। वेटिंग की समस्या के समाधान के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। गाड़ियों को कैंसिल होने से भी बचाना होगा। जब ट्रैक की क्षमता बढ़ेगी तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। वंदे भारत एवं अमृत भारत से सीख लेकर रेलवे को अपग्रेड किया जाएगा।

बजट बोल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रस्तुति सबसे छोटे भाषणों में से एक थी। कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं हुई। यह स्वागत योग्य है और मुझे उम्मीद है कि स्थायी दृष्टिकोण है! राजकोषीय घाटे का लक्ष्य परिकल्पना से बेहतर था।

आनंद महिंद्रा, चेयरमैन, महिंद्रा समूह

वित्त मंत्री ने निरंतर आर्थिक विकास का एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। अनुसंधान और नवप्रवर्तन, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी-संचालित डिजिटल परिवर्तन पर जोर जन-केंद्रित, समावेशी विकास के लिए अच्छा संकेत है। **-किरण मजूमदार शा**, चेयरपर्सन, बायोकान लिमिटेड

'विकसित भारत 2047' का दृष्टिकोण निर्णायक शासन और बुनियादी ढांचे को वितरित करने की मजबूत नींव पर बनाया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय का विस्तार और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का पालन इस अंतरिम बजट के मजबूत बिंदु हैं। **कुणाल बहल**, सह-संस्थापक, स्नैपडील

अंतरिम बजट में सरकार ने देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने के संकल्प को और दृढ़ किया है। लखपति दीदी स्कीम को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ तक ले जाना सराहनीय है। सरकार ने देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। **-जक्षय शाह**, चेयरपर्सन, क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया

टैक्स रेट में बदलाव नहीं, एक करोड़ करदाताओं को पुराने नोटिस से राहत

वित्त मंत्री ने कहा-टैक्सपेयर्स के पैसे का देश के विकास में बुद्धिमत्ता से उपयोग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोगों की उम्मीद के विपरीत सरकार ने इनकम टैक्स से लेकर अप्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स देनदारी संबंधी नोटिस से प्रभावित लोगों को जरूर राहत दे दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान टैक्सपेयर्स की तारीफ करते हुए कहा कि उनके दिए हुए पैसे का सरकार देश के विकास में बुद्धिमत्तापूर्वक इस्तेमाल कर रही है। पिछले 10 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इनकम टैक्स की नई और पुरानी किसी भी व्यवस्था के तहत कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में टैक्सपेयर्स से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। फार्म 26एएस के लांच होने से आइटीआर भरना आसान हो गया है और टैक्सपेयर्स के रिफंड आने का समय अब औसतन दस दिन हो गया है जो वर्ष 2013-14 के दौरान 93 दिन था।

सरकार की घोषणा के मुताबिक वित्त वर्ष 2009-10 तक अगर किसी टैक्सपेयर्स पर टैक्स विभाग के मुताबिक 25,000 रुपये का बकाया था और विभाग ने इस बकाए के लिए नोटिस भेज रखा है तो उसे सरकार अब वापस ले लेगी। वैसे ही, वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर 2014-15 के बीच टैक्स विभाग के मुताबिक किसी टैक्सपेयर पर 10,000 रुपये का बकाया है और इस संबंध में नोटिस जारी है तो उसे भी सरकार माफ कर देगी।

वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि इस फैसले से एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। बजट में सरकार ने किसी भी प्रकार के आयात शुल्क में भी कोई बदलाव नहीं किया। यह उम्मीद की जा रही थी कि कई प्रकार के कच्चे माल के आयात पर सरकार शुल्क में कमी करेगी।

औद्योगिक समूहों ने मैन्यूफैक्चरिंग लागत में कमी के लिए कई कच्चे माल के आयात शुल्क में कटौती की मांग की थी।

2009-10 तक 25,000 रुपये तक के बकाए कर पर नोटिस वापस लेगी सरकार

10 वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी

5 वर्षों में करदाताओं से जुड़ी सुविधाएं बढ़ीं और आइटीआर भरना हुआ आसान

93 दिन था 2013-14 में रिफंड मिलने का औसत समय, जो अब 10 दिन रह गया

3500 करोड़ बकाया कर माफ

नई दिल्ली, प्रेट्र : राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि सरकार कुल 3500 करोड़ रुपये के विवादित कर मांगों को वापस लेगी। इसके तहत वर्ष 2014-15 तक पांच साल की अवधि के 1.11 करोड़ विवादित कर मांगों को वापस लेने का अंतरिम बजट में प्रस्ताव है। मल्होत्रा ने बताया कि वापस लिए जाने वाले बकाया करों में आयकर, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स आदि हैं। इनमें से कुछ मामले तो 1962 तक के हैं।

जुलाई में पेश करेंगे अमृतकाल का रोडमैप

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बात का पूरा भरोसा है कि आगामी आम चुनाव में उनकी पार्टी ही विजयी होने वाली है। उनके आत्मविश्वास का स्तर यह था कि उन्होंने यह एलान कर दिया कि अगले बजट में उनकी सरकार अमृतकाल यानी वर्ष 2047 तक देश की आर्थिक उन्नति का रोडमैप पेश करेगी। अमृतकाल के लिए रणनीति का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आगे भी आर्थिक सुधारों की गति तेज बनी रहेगी और समावेशी विकास सरकार की अहम प्राथमिकता रहेगी। विकसित भारत बनाने के लिए विशाल वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वित्तीय सेक्टर में सुधार भी सरकार के एजेंडे में ऊपर रहेगा।

इस घोषणा के साथ ही वित्त मंत्री ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को एक बार फिर उसके आर्थिक कुप्रबंधन के लिए घेरा और एलान किया कि वर्ष 2014 तक (यूपीए के कार्यकाल) के कुप्रबंधन से सबक सीखने के लिए सरकार सदन पटल पर एक श्वेत पत्र पेश करेगी।

सीतारमण ने कहा- 'वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी तब चरणवार अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने व शासन-प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। लेकिन अब यह देखना सही होगा कि तब हम कहां थे और कुप्रबंधन से क्या सबक सीखा जा सकता है।'

इसके पहले वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आगे ऐसी नीतियां अपनाएंगी जो विकास की रफ्तार को बढ़ाएंगी, उत्पादकता बढ़ाएंगी और सभी के लिए अवसर बनाएंगी। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार की नीति भी सभी को पर्याप्त और किफायती कीमत पर ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराने की रहेगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एलान किया कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप पेश करेगी।

यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा | आगामी सरकार की आर्थिक नीतियों का खींचा खाका | वित्तीय सेक्टर में सुधार और समावेशी विकास को मिलेगी प्राथमिकता

अंतरिम बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने पहुंचीं। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने हाथों से मीठा खिलाकर वित्त मंत्री को संसद के लिए रवाना किया। • प्रेट्र

बजटीय घोषणाओं से ईवी और सोलर क्षेत्र के शेयरों में उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र: अंतरिम बजट की घोषणाओं से गुरुवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) और सोलर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया। वित्त मंत्री ने चार्जिंग इन्फ्रा को मदद के जरिये ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन में ई-बसों को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। साथ ही एक करोड़ घरों पर रूफटाप सोलर लगाने की घोषणा की गई है।

इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों में बीएसई में 6.21 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, यह 0.69 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,729 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। इसी तरह, जेबीएम आटो के शेयर कारोबार के दौरान 4.96 प्रतिशत तक बढ़े और अंत में यह 2.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,963.20 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। इंजन निर्माता कंपनी ग्रीव्स काटन के शेयर दिनभर के दौरान तीन प्रतिशत की तेजी के साथ 168.55 रुपये प्रति इकाई के उच्च स्तर पर पहुंचे। अंत में यह 0.95 प्रतिशत की तेजी के साथ 165.05 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। सौर ऊर्जा से जुड़ी कंपनी केपीआइ ग्रीन एनर्जी के शेयर कारोबार के दौरान 9.50 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,997.15 रुपये प्रति इकाई पर पहुंचे। यह इनका बीएसई में 52 सप्ताह का नया उच्च स्तर है। हालांकि, अंत में यह 9.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,996.65 रुपये प्रति इकाई पर बंद हुए। इसी प्रकार, वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 4.99 प्रतिशत बढ़कर एक वर्ष के नए उच्च स्तर 388.15 रुपये प्रति इकाई पर पहुंचे। विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी और अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में कारोबार के दौरान क्रमशः 4.16 प्रतिशत और 2.14 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घरों के निर्माण से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हुडको के शेयर में 6.14 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई और यह 52 सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंचे।

52 सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंचे केपीआइ ग्रीन एनर्जी के शेयर 2

दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद गिरकर बंद हुए घरेलू शेयर बाजार

चालू वित्त वर्ष में विनिवेश का लक्ष्य घटाया, अगले वर्ष 50 हजार करोड़ का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में विनिवेश से 50 हजार करोड़ रुपये मिलने का लक्ष्य रखा है। यह चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लक्ष्य 51 हजार करोड़ रुपये से मामूली कम है। साथ ही सरकार ने चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य को 51 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 30 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।

लोकसभा में पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार, सरकार को चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक संपत्तियों के मौद्रीकरण से कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। 2023-24 के बजट में सरकार ने ऐसी संपत्तियों के मौद्रीकरण से 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई थी। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश की बात करें तो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की सात कंपनियों की आंशिक हिस्सेदारी बेचने से अब तक 12,504 करोड़ रुपये मिले हैं। इनमें कोल इंडिया, एनएचपीसी, आरवीएनएल और इरेडा शामिल है। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 को छोड़कर सरकार अधिकांश वर्षों में बजट में निर्धारित विनिवेश लक्ष्यों से चूक रही है। वित्त वर्ष 2017-18 में एक लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य के सापेक्ष सरकार को विनिवेश से 1,00,056 करोड़ रुपये मिले थे। इसी तरह, वित्त वर्ष 2018-19 में 80 हजार करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य के सापेक्ष विनिवेश से 84,972 करोड़ रुपये मिले थे।

आरबीआइ, पीएसबी से 1.02 लाख करोड़ के लाभांश का अनुमान : सरकार ने अगले वित्त वर्ष में आरबीआइ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और अन्य वित्तीय संस्थानों से लाभांश के रूप में 1.02 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान जताया है। चालू वित्त वर्ष में सरकार को 48 हजार करोड़ के बजट लक्ष्य के सापेक्ष आरबीआइ-पीएसबी से 1.04 लाख करोड़ का लाभांश मिलने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष के लिए आरबीआइ ने मई 2023 में सरकार को लाभांश के रूप में 87,416 करोड़ रुपये दिए थे, जो बजट अनुमान से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार को आरबीआइ और पीएसबी से लाभांश के रूप में 39,961 करोड़ रुपये मिले थे। सरकार को चालू वित्त वर्ष में आरबीआइ, पीएसबी और अन्य कंपनियों से 1,54,407 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने की उम्मीद है। इसी तरह, अगले वित्त वर्ष 1.50 लाख करोड़ का लाभांश मिलने का अनुमान जताया गया है।

चालू वित्त वर्ष में 51 हजार करोड़ के बजट लक्ष्य के सापेक्ष 30 हजार करोड़ मिलने की उम्मीद

दो वित्त वर्ष को छोड़ विनिवेश लक्ष्य प्राप्त करने में चूकी सरकार

7 कंपनियों की आंशिक हिस्सेदारी बेचने से 12,504 करोड़ रुपये मिले

1.02 लाख करोड़ रुपये लाभांश का मिलने अनुमान

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा गेम चेंजर साबित होगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने भी भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारे (आइएमईसी) का जिक्र किया और इसे भारत के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने इस संदर्भ में पीएम नरेन्द्र मोदी के इस कथन को उद्धृत किया कि आने वाले सैकड़ों वर्षों में यह कारिडोर वैश्विक कारोबार का आधार बनेगा और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि इसकी नींव भारत में रखी गई थी।

भारत-मध्य पूर्व- यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा सितंबर, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 समूह की शीर्ष बैठक में की गई थी। पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद समेत कई वैश्विक नेताओं ने मिल कर इसकी घोषणा की थी। माना जाता है कि चीन के अंतरराष्ट्रीय कारिडोर बीआरआइ (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) का विकल्प है।

देश की भावी आर्थिक तस्वीर की बेहद सुनहरी तस्वीर खींचने के साथ ही वित्त मंत्री ने पहले कोरोना महामारी और उसके बाद भूराजनीतिक माहौल का भी जिक्र किया। उनका मकसद यह बताना था कि युद्धों व विवादों के कारण भूराजनीतिक माहौल काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। उद्योगों को अपने यहां या मित्र देशों के यहां लगाने, आपूर्ति श्रृंखला के अव्यवस्थित होने, महत्वपूर्ण खनिजों व प्रतिस्पर्धा की वजह से वैश्वीकरण की परिभाषा बदल रही है। इस कठिन समय में भारत ने जी-20 बैठक की अध्यक्षता सफलतापूर्वक की है।

कोरोना महामारी के दौरान विश्व में खाद्य, उर्वरक, ईंधन व वित्त की समस्या पैदा हुई है जबकि भारत अपनी राह बनाने में सफल रहा। भारत ने वैश्विक समस्याओं के समाधान पर सहमति बनाई।

वित्त मंत्री ने पीएम के कथन को किया उद्धृत-यह कारिडोर वैश्विक कारोबार का आधार बनेगा

जी-20 की शिखर बैठक में की गई थी यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारों की घोषणा

भारत-मध्य पूर्व- यूरोप आर्थिक गलियारा • प्रतीकात्मक मानचित्र

कर्ज में कमी, कर वृद्धि से राजकोषीय घाटा 5.1 % का लक्ष्य

राजीव कुमार • नई दिल्ली

वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण समय होने के बावजूद सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचय दिया है। बढ़ते राजस्व व घटते कर्ज से सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को आसानी से हासिल करती दिख रही है। आने वाले वर्षों में भी सरकार को ऐसे ही प्रदर्शन का भरोसा है। तभी अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे में लगातार कमी का अनुमान लगाया गया है।

चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रखा था लेकिन अब राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8 प्रतिशत करने का अनुमान लगाया है। आगामी वित्त 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस तरह वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 प्रतिशत या इससे कम रहने का अनुमान है।

सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में अपने टैक्स बढ़ाने तो कर्ज में कटौती का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में ऋण प्राप्तियां 17,61,424 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में ऋण प्राप्तियां 16,81,944 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट घोषणा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में उधारी को छोड़ सरकार की कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें 23.24 लाख करोड़ रुपये टैक्स से प्राप्त होगा। चालू वित्त वर्ष में कुल खर्च 44.90 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आगामी वित्त वर्ष में कुल प्राप्ति (उधारी को छोड़) 30.80 लाख करोड़ तो कुल खर्च 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। आगामी वित्त वर्ष में 26.02 लाख करोड़ रुपये टैक्स से प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री कहते हैं कि आर्थिक मजबूती को देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे के 4.5% के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी के साथ सरकार को चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों से पहले के मुकाबले अधिक लाभांश मिला है। हालांकि विनिवेश से सरकार को लगभग 12,000 करोड़ ही मिले।

चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से कम 5.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान

वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

साल दर साल कम हो रहा घाटा

वित्त वर्ष	राजकोषीय घाटा (% में)
2020-21	9.2
2021-22	6.8
2022-23	6.4
2023-24	5.8
2024-25	5.1 (अनुमानित)

14.3 लाख करोड़ बाजार से उधार लेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करके 14.3 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव रखा। यह पिछले साल के 15.43 लाख करोड़ रुपये के सकल उधार अनुमान से कम है, जो अब तक का सर्वाधिक था। बढ़ते कर राजस्व और राजकोषीय समेकन रोडमैप को पूरा करने के संकल्प के चलते अगले वित्त वर्ष में कम उधारी का लक्ष्य रखा गया है।

सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए शुद्ध उधार अनुमान के बारे में कहा कि यह अगले वित्त वर्ष के दौरान 11.75 लाख करोड़ रुपये होगा। परिणामस्वरूप सरकार वर्ष के दौरान 2,37,818 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करेगी। उन्होंने कहा, '2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.13 और 11.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। दोनों 2023-24 की तुलना में कम होंगे।' उन्होंने कहा कि अब जब निजी निवेश बड़े पैमाने पर हो रहा है तो ऐसे में सरकार के पास निजी क्षेत्र को कर्ज देने के लिए बड़ी पूंजी उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय के कारण इस्पात व सीमेंट क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

2 लाख 37,818 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करेगी सरकार

15 लाख 43 हजार करोड़ के उधार अनुमान से कम है इस वर्ष

एफडीआइ के लिए कई देशों से वार्ता कर रहा भारत

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआइटी) पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) 2005-14 के दौरान आए एफडीआइ की तुलना में 2014-23 के दौरान 596 अरब डालर हो गया। द्विपक्षीय निवेश संधियों के बारे में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि भारत ने 2016 तक अपने 80 से अधिक बीआइटी में से 77 को रद कर दिया है, क्योंकि वे उसके हितों के अनुरूप नहीं थे।

संचार क्षेत्र से 1.20 लाख करोड़ रुपये के गैर कर राजस्व का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए संचार क्षेत्र से 1.20 लाख करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व संग्रह का अनुमान लगाया है। 'सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अन्य संचार सेवाओं से राजस्व अनुमान को 93,541.01 करोड़ कर दिया है। बजट में 89,469.17 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। 2022-23 में सरकार की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां 64,835.17 करोड़ थीं। अन्य संचार सेवाओं से गैर कर राजस्व प्राप्तियां दूरसंचार आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपभोग शुल्क की प्राप्तियों से संबंधित हैं।

****

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण
जीत के लिए जोखिम तो लेना ही पड़ता है

अंतरिम बजट का संदेश

जब यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनावों के चलते मोदी सरकार अंतरिम बजट में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ लोकलुभावन घोषणाएं अवश्य करेगी, तब उसने इससे परहेज किया। इसके जरिये उसने न केवल पुरानी परिपाटी का परित्याग करते हुए रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ संदेश दिया, बल्कि अपने इस आत्मविश्वास का परिचय भी दिया कि वह अपने अब तक के कार्यों के आधार पर ही तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। ऐसे आत्मविश्वास का परिचय वही सरकार दे सकती है, जो इसे लेकर आश्वस्त हो कि आम जनता का भी उसके प्रति यह भरोसा है कि वह अपने राजनीतिक हितों के स्थान पर देश के आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक हितों की रक्षा वित्तीय अनुशासन का परिचय देकर ही की जा सकती है। अंतरिम बजट के जरिये यही करने की कोशिश की गई है। अंतरिम बजट यह रेखांकित कर रहा है कि मोदी सरकार की निगाह विकसित भारत के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर है। अंतरिम बजट में इस लक्ष्य को साधने के प्रयत्न इसलिए किए जाने आवश्यक थे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और वह तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर है।

अंतरिम बजट की अपनी सीमाएं होती है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शोध एवं अनुसंधान के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष का प्रविधान किया। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए शोध एवं अनुसंधान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाना समय की मांग थी, क्योंकि इस क्षेत्र में काम किए बिना कोई भी देश विकसित नहीं बन सका है। अंतरिम बजट का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। सरकार इस कठिन लक्ष्य को इसीलिए सामने रख सकी, क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8 प्रतिशत तक ही रहने का अनुमान है। पहले यह अनुमान 5.9 प्रतिशत था। साफ है कि तमाम चुनौतियों के बाद भी सरकार वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। अंतरिम बजट इसकी भी पुष्टि कर रहा है कि मोदी सरकार देश को विकसित बनाने के लिए राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि राज्यों को 50 वर्ष के लिए 75,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, ताकि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, बिजली, सड़क, पुल समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परियोजनाएं पूरी कर सकें। इससे राज्यों की स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी और वे देश के विकास में सहभागी बन सकेंगे। यह साफ है कि बड़ी घोषणाओं के लिए पूर्ण बजट की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि मोदी सरकार ऐसी घोषणाएं करने के लिए बजट की मोहताज नहीं।

सुनिश्चित हो ऋण वापसी

धन के अभाव में जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए शिक्षा ऋण की व्यवस्था की गई है, लेकिन चिंताजनक यह है कि बड़े पैमाने पर इसकी वापसी नहीं हो पा रही है। नतीजतन कई जरूरतमंद छात्र आवेदन करने के बाद भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वापस नहीं होने के चलते ही बैंक नए छात्रों को ऋण देने में आनाकानी करते हैं। दरअसल कई विद्यार्थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेकर इसका उपयोग पढ़ाई के बदले किसी दूसरे काम में कर लेते हैं और रोजगार नहीं मिलने से ऋण वापस नहीं कर पाते। बिहार में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। अकेले सहरसा जिले में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने 611 विद्यार्थियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने ऋण वापस नहीं किया है। मुजफ्फरपुर और पटना में भी ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं, जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेकर वापस नहीं किया है। कहने की जरूरत नहीं कि सरकार अगर सुविधा प्रदान कर रही है तो छात्रों को भी चाहिए कि वे रोजगार मिलने के बाद ऋण वापस कर दें, ताकि यह अन्य निर्धन विद्यार्थियों को भी आसानी से मिल सके। निश्चित रूप से ऋण देने की प्रक्रिया कठिन नहीं हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था जरूर बनाई जाए जिससे इसकी वापसी संभव हो सके। सरकार को चाहिए कि वह इसके लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करे, जो यह देखे कि छात्र इसका उचित उपयोग कर रहे हैं या नहीं। ऋण वापस होने से ही बैंकों का विश्वास जमेगा और अगले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं को भविष्य संवारने के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए भी ऋण दिए जाते हैं, लेकिन यह सुविधा तभी मिल पाएगी, जब बैंकों को इसकी वापसी का भरोसा होगा। अभिभावकों को भी चाहिए कि वे छात्रों पर नजर रखें और इसे वापस करने के लिए उन्हें प्रेरित करें।

संतुलित एवं व्यावहारिक अंतरिम बजट

धर्मकीर्ति जोशी

चुनावी लोकलुभावनवाद से मुक्त यह अंतरिम बजट महंगाई के दबाव को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला है

अवधेश राजपूत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट को देखकर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि सरकार ने पूर्ण बजट और अंतरिम बजट के बीच की महीन रेखा को मिटाने का प्रयास किया। अंतरिम बजट अपनी प्रकृति के अनुरूप ही रहा। चुनावी साल होने के बावजूद सरकार ने किसी भी प्रकार की बड़ी लोकलुभावन घोषणा या ऐसे कोई भावी संकेत देने से परहेज किया। सरकार ने एक प्रकार से राजनीतिक जोखिम लेते हुए वित्तीय अनुशासन का परिचय दिया। यदि एक पंक्ति में व्याख्या की जाए तो चुनावी लोकलुभावनवाद से मुक्त यह अंतरिम बजट महंगाई के दबाव को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाला है। कुछ वैश्विक एवं घरेलू कारणों से महंगाई का जो दबाव अभी भी बना हुआ है, उसका अंतरिम बजट में ध्यान रखा गया है। साथ ही उत्पादकता को बढ़ाने वाले ऐसे कई प्रविधान किए गए हैं, जो दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को आवश्यक गति प्रदान करने में सक्षम एवं प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर इस समय कायम तमाम चुनौतियों के बावजूद सरकार अपने खजाने की सेहत दुरुस्त रखने में सफल रही है। बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया गया था, जो संशोधित अनुमान में 5.8 प्रतिशत रहा। अगले वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री ने इसे जीडीपी के 5.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य तय किया है, जो दर्शाता है कि सरकार राजकोषीय अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं कर रही। यहां यह और भी सराहनीय पहलू है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय में कटौती किए बिना ही घाटे को घटाने में सफलता हासिल की है और आगे भी पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी का रुझान कायम रखने की प्रतिबद्धता दिखाई है। स्पष्ट है कि सरकार ने एक प्रकार के अनुत्पादक राजस्व व्यय को घटाकर ही घाटे पर अंकुश लगाया है। सरकारी खजाने की बेहतर स्थिति में कर राजस्व में आ रही निरंतर तेजी का भी अहम योगदान रहा। चालू वित्त वर्ष में सरकार को अनुमान से 76,000 करोड़ रुपये का अधिक कर राजस्व मिला है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के लिए नामिनल यानी अनुमानित जीडीपी की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत आंकी गई थी, लेकिन यह 8.9 प्रतिशत रही। यानी नामिनल जीडीपी में संकुचन के बावजूद कर संग्रह ने रफ्तार पकड़ी है तो यह बड़ी उपलब्धि गिनी जाएगी। करों के स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में तो पहले से ही तेजी का रुख बना हुआ है, लेकिन कर राजस्व में बढ़ोतरी में प्रत्यक्ष करों का भी भारी योगदान रहा। जीएसटी के चलते जहां कर व्यवस्था कई मायनों में सुसंगत हुई है तो कर चोरी एवं रिसाव को रोकने के कई रास्ते बंद होने का असर भी कर संग्रह पर स्पष्ट दिख रहा है। डिजिटलीकरण के स्तर पर हो रहे व्यापक प्रयासों ने भी अपना प्रभाव दिखाया है।

वित्तीय रूप से अनुशासित रहते हुए भी सरकार ने कल्याणकारी राज्य की भूमिका के साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती किसी से छिपी नहीं है। उसे मुश्किल से उबारने के लिए सरकार ने सीधे किसी प्रकार की मदद या रेवड़ी देने के बजाय तार्किक रूप से संसाधन आवंटित किए हैं। इस मोर्चे पर किसी प्रकार की सीधी मदद से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिक दबाव उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ता। ऐसे में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा जैसी उन योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया है, जिनसे उत्पादक कार्यों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। इससे ग्रामीण आर्थिकी को बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार शहरी मध्य वर्ग को सीधी राहत भले ही न दी गई हो, लेकिन आवास योजना का दायरा बढ़ाकर शहर में आशियाने के लोगों के सपने को परवान चढ़ाया है। शहरों में बड़ी संख्या में किराये के घर में रहने वाले लोगों के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना है। अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार ने दर्शाया है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वह किस हद तक कमर कसे हुए है। चूंकि भविष्य अब तकनीक आधारित और नवाचार केंद्रित उद्यमों का है तो उस दृष्टिकोण से शोध एवं विकास यानी आरएंडडी के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष की पहल बहुत सराहनीय कदम है। इससे जहां युवाओं की ऊर्जा का अपेक्षित रूप से उपयोग होगा तो उद्यमिता के नए आयाम स्थापित होने की संभावना है।

अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य ने इस समय आर्थिक अनिश्चितताओं को बढ़ाया हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि पश्चिम एशिया में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष का नया मोर्चा खुल गया। अब लाल सागर में तनाव भड़का हुआ है। इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है। अंतरिम बजट के संकेत यही दर्शाते हैं कि सरकार वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने को प्रतिबद्ध है तो आर्थिक मोर्चे पर किसी बड़ी फिसलन की आशंका नहीं दिख रही। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष में हमारा अनुमान है कि जीडीपी 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने में सफल रहेगी। मौजूदा परिदृश्य में यह ठीकठाक वृद्धि कही जाएगी। चूंकि यह अंतरिम बजट ही था तो सरकार ने नीतिगत मोर्चे पर बड़े कदम नहीं उठाए, लेकिन ऐसे कुछ संकेत दिए हैं कि यदि वह फिर से सत्ता में आती है तो जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट की तस्वीर किस तरह की होगी। जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में कुछ ऐसे सुधारों के आकार लेने की संभावना दिख रही है, जो निजी निवेश को गति देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएं।

अंतरिम बजट का समग्रता में आकलन करें तो वित्त मंत्री ने मुश्किल माहौल में प्रभावी संतुलन साधने का काम किया है। चुनावी साल होने के बावजूद मुफ्त रेवड़ियों और लोकलुभावनवाद का मोह नहीं किया। ऐसे कोई कदम नहीं उठाए, जिनसे महंगाई के पहले से कायम दबाव को और ताकत मिले। कुल मिलाकर, वर्तमान परिस्थितियों में यह एक व्यावहारिक अंतरिम बजट है, जिसके लिए वित्त मंत्री सराहना की पात्र हैं।

(लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

विकसित भारत के संकल्प का प्रदर्शन

विवेक देवराय

आदित्य सिन्हा

अंतरिम बजट इसकी तस्वीर पेश करता है कि सरकार किस तरह देश के भविष्य को संवारने में लगी है

पूर्ण बजट की आधारशिला है अंतरिम बजट। प्रेट्र

देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक योजना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी योजनाओं से सतत आर्थिक वृद्धि एवं चहुंमुखी विकास के लिए संसाधनों का रणनीतिक आवंटन सुगम होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में ऐसी ही दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के बजाय दूरगामी एवं व्यापक लाभ को वरीयता दी, जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो आह्वान किया था, उस सिद्धि को प्राप्त करने में अंतरिम बजट के कुछ प्रविधान संकल्प की भूमिका में दिख रहे हैं। इसी कड़ी में पहला कदम पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करने का है। बुनियादी ढांचागत विकास सरकार की प्राथमिकताओं में बना हुआ है। आधारिक संरचना को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र के लिए 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 11.1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके माध्यम से रेलवे नेटवर्क, मेट्रो रेल, विमानन और हरित ऊर्जा पर काम किया जाएगा। बुनियादी ढांचे पर इतने भारी खर्च का अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे जहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा तो आर्थिक वृद्धि की गति और तेज होगी। देश के बहुमुखी विकास के लिए ये दोनों ही आवश्यक पहलू हैं।

भारत तेज आर्थिक वृद्धि की ओर अग्रसर है, लेकिन इस राह में देश का पूर्वी हिस्सा कुछ पीछे रह गया। उसकी भरपाई के लिए सरकार भारत के इस हिस्से पर पूरा ध्यान दे रही है कि वह देश की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ कदमताल करे और उसका लाभ यहां के लोग भी उठा पाएं। इससे जहां क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, वहीं समावेशी वृद्धि को बल मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों के अहम सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए 50 वर्षों के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश भी सराहनीय कही जाएगी। इस कवायद का उद्देश्य राज्यों को विकास-केंद्रित सुधारों के लिए प्रोत्साहित करना है। विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए राज्यों का व्यापक विकास अत्यंत आवश्यक है। भारत की आर्थिक वृद्धि में उसके राज्यों की जटिल कड़ियां भी जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार राज्यों को सुधारों के लिए प्रेरित करने के साथ ही सुधार करने वाले राज्यों को पुरस्कृत भी कर रही है। इससे राज्यों में सुधारों के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में अहम भूमिका निभाएगी।

सरकार विकसित भारत के संकल्प पूर्ति की दिशा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर भी पूरा जोर दे रही है। वह कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता में लगी है। यह दृष्टिकोण भारत के दूरगामी हितों की पूर्ति करने वाला है, क्योंकि इससे निवेश, नवाचार और तकनीकी उन्नयन के लिए अनुकूल परिवेश तैयार होने के साथ ही आर्थिक वृद्धि को नए पंख लगेंगे। विदेशी निवेश को आकर्षित करने से भारत-पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण और विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा, जो देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक अवयव हैं। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए सरकार ने नवाचार को रफ्तार देने का निर्णय किया है। इस दिशा में 50 वर्षों के लिए एक लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने वाले कोष के गठन की पहल एक रणनीतिक कदम है।

जलवायु परिवर्तन समकालीन दौर की एक बड़ी चुनौती है। सरकार इस चुनौती की गंभीरता को समझते हुए उससे निपटने के लिए संकल्पबद्ध है। इसी दिशा में हरित ऊर्जा से जुड़ी कई पहल की गई हैं और ऐसी कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार पवन ऊर्जा से जुड़ी संभावनाओं को व्यापक स्तर पर भुनाने और इस राह में वित्तीय संसाधनों सहित तमाम अन्य बाधाओं को दूर करने की राह तैयार कर रही है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा के समुचित दोहन की योजना बनाई जा रही है। इसके माध्यम से करीब एक करोड़ घरों को छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सक्षम बनाया जाएगा, ताकि हर महीने तकरीबन 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल सके। इस कदम से न केवल ऊर्जा के लिए अक्षय स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि हरेक घर के पैसों की बचत भी होगी और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के स्तर पर भी प्रयासरत है। इसके लिए वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन और द्रवीकरण क्षमता स्थापित करने की योजना है। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनाल और अमोनिया के आयात को घटाने में मदद मिलेगी। ये कदम न केवल विकसित भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, बल्कि वर्ष 2070 तक 'नेट जीरो' के लक्ष्य की पूर्ति में भी सहायक होंगे।

अंतरिम बजट एक प्रकार से जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट की आधारशिला रखने वाला है। इसका विस्तारित खाका तो पूर्ण बजट में ही दिखेगा, फिर भी अंतरिम बजट इसकी झलक अवश्य पेश करने में सफल रहा कि सरकार किस तरह देश के भविष्य को संवारने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम रही है।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सौभाग्य का सूरज

धूप और छांव की तरह जीवन में कभी दुख ज्यादा तो कभी सुख ज्यादा होते हैं। जीवन में जितनी अधिक समस्याएं होती हैं, सफलताएं भी उतनी ही तेजी से कदमों को चूमती हैं। बिना समस्याओं के जीवन के कोई मायने नहीं हैं। समस्याएं क्यों होती हैं? हम समस्याओं को कैसे कम कर सकते हैं? इन प्रश्नों का समाधान आध्यात्मिक परिवेश में ही खोजा जा सकता है। अति चिंतन, अति स्मृति और अति कल्पना-ये तीनों समस्या पैदा करते हैं। शरीर, मन और वाणी-इन सबका उचित उपयोग होना चाहिए। ऐसा न होने पर ये निकम्मे बन जाएंगे। यदि इन्हें बहुत ज्यादा काम में लें तो ये समस्या पैदा करेंगे। इस समस्या का कारण व्यक्ति स्वयं है और वह समाधान खोजता है दवा में या बाहर संसार में। यही समस्या व्यक्ति को अशांत बनाती है। यहां जरूरत है एक संतुलित जीवनशैली की। जीवनशैली के शुभ मुहूर्त पर हमारा मन उगती धूप की तरह ताजगी-भरा होना चाहिए, क्योंकि अनुत्साह, भयाक्रांत, शंकालु और अधमरा मन समस्याओं का जनक होता है। यदि हमारे पास विश्वास, साहस, उमंग और संकल्पित मन है तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती।

बीमारी में दवा समाधान है, परंतु उचित समाधान नहीं। पहला समाधान भीतर खोजना चाहिए। एक व्यक्ति दवा के बल पर स्वस्थ रहता है या अपने मानसिक बल यानी सकारात्मक सोच के बल पर? हमारी सकारात्मकता कई समस्याओं का समाधान है। जितने नकारात्मक भाव हैं, वे हमारी बीमारियों एवं समस्याओं से लड़ने की प्रणाली को कमजोर बनाते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उसे निषेधात्मक भावों से बचना चाहिए। बार-बार क्रोध आना, चिड़चिड़ापन, मूड का बिगड़ते रहना-ये सारे भाव हमारी समस्याओं से लड़ने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। इनसे ग्रस्त व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है।

ललित गर्ग

सही हाथों तक पहुंचते पुरस्कार

डा. मोनिका शर्मा

सामाजिक बदलाव लाने में जुटे चेहरों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना आमजन का मनोबल बढ़ाने वाला है

पद्म पुरस्कारों की सूची में इस बार भी कुछ अनजाने-अनसुने चेहरों के नाम देशवासियों के सामने आए। जनकल्याण, जागरूकता और जिजीविषा के मोर्चे पर हर नागरिक को प्रेरणा देने वाली इन हस्तियों को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना बहुत से सार्थक पहलू सामने रखता है। ज्ञात हो कि हर वर्ष देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार कई क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले विशिष्ट चेहरों को दिए जाते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री-तीन श्रेणियों में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों से समाज सेवा, कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा और खेल आदि क्षेत्रों से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। इस बार पांच पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 हस्तियों को दिए पद्म श्री सम्मानों की सूची में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। बिना शोर-शराबे के सामाजिक बदलाव लाने में जुटे इन चेहरों को सम्मानित किया जाना आमजन का मनोबल बढ़ाने वाला है। छोटी से छोटी मुहिम को मान देने के भाव संग सही हाथों तक पहुंचते पुरस्कार समाज में नए उत्साह का संचार भी करते हैं।

यह पहल चर्चित चेहरों के बजाय गांवों-कस्बों के उन लोगों की कला, प्रतिभा और सरोकारी सोच को पहचान देने वाली है, जो जमीनी बदलाव लाने में जुटे हैं। कम से कम संसाधनों में भी सामाजिक बदलाव की नींव को मजबूत बना रहे हैं। यही वजह है कि देश के आम नागरिक भी पद्म पुरस्कारों से जुड़े इस बदलाव की खूब सराहना कर रहे हैं। अब हर वर्ष सामने आते चेहरे न केवल देशवासियों को सुखद आश्चर्य से भर देते हैं, बल्कि गौरव की भी अनुभूति करवाते हैं। अपने परिवेश तक में अपरिचित बने रहने वाले बहुत से चेहरों का योगदान तो हैरत में डालने वाला होता है। उनकी अनदेखी-उपेक्षित भागीदारी को मान मिलना अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने वाला है। प्रशंसा और प्रेरणा का यह मेल हर किसी को देश की बेहतरी में साझीदार बनने का संदेश देता है।

पद्म पुरस्कारों की पहुंच से जुड़ा यह रेखांकित करने योग्य बदलाव वर्ष 2014 के बाद आया, जिसके बाद सम्मानित किए जाने के लिए चुनी जाने वाली हस्तियों का नाम सुझाने की प्रक्रिया में आम नागरिकों को भी भागीदार बनाया गया। अब पद्म सम्मान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष काम करने वाले लोगों के नाम की अनुशंसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। देश और समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे गुमनाम चेहरों को सामने लाने के लिए वेबसाइट बनाकर आवेदन मांगे गए जिससे दूर-दराज के इलाकों में बसे लोगों को भी प्रोत्साहन मिला। सुखद है कि पुरस्कृत होने वालों में हर वर्ष देश के सुदूर क्षेत्रों के लोगों की संख्या बढ़ रही है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

गणतांत्रिक मूल्य और वर्तमान भारत

'गणतांत्रिक मूल्यों से भटकता भारत' शीर्षक से प्रकाशित कपिल सिब्बल का आलेख केवल पूर्वाग्रहों से ग्रस्त प्रतीत होता है। लेखक देश के नामी वकील हैं, किंतु उनके आलेख में व्यक्त सोच बड़ा नहीं है। उनका यह कहना कि 'एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से हमारे गणतंत्र के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है, इससे एक समावेशी भारत बनाने के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न ध्वस्त हुआ है' निःसंदेह एक व्यक्ति-विरोध का सोच है। ऐतिहासिक 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो भारत की समावेशी संस्कृति के ही दर्शन हुए। जिस व्यक्ति का लेखक विरोध कर रहे हैं उनके साथ उस दिन राम मंदिर परिसर में विभिन्न पंथों के गणमान्य लोग उपस्थित थे। गणतांत्रिक मूल्यों से भटकता भारत तब था जब करोड़ों गणों की आस्था के प्रतीक इस राष्ट्र मंदिर के कार्य को लटकाया और भटकाया जा रहा था। भारत विभिन्न पूजा-पद्धतियों का देश होने के बावजूद सनातन धर्मावलंबी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश के गण लाखों की संख्या में अयोध्याधाम पहुंच रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत अध्यात्म की भूमि है और अपने देश में आध्यात्मिक पर्यटन की अपनी परंपरा है। लेखक को इस बात का संज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि अयोध्या में राष्ट्र मंदिर निर्माण तक और उसके बाद वहां की आर्थिकी का क्या स्वरूप है तथा इसके लाभार्थी कौन हैं। व्यक्ति विरोध में हमें लोगों की आस्था का अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। हालांकि विश्वगुरु भारत का सपना तभी साकार होगा जब सभी गण उदार मन से अपने-अपने कार्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करेंगे। संकुचित सोच से विकास के मार्ग अवरुद्ध होते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के सभी उदात्त प्रयास समस्त गणों को करने ही होंगे।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

जन-भावना का सम्मान

कपिल सिब्बल का 'गणतांत्रिक मूल्यों से भटकता भारत' शीर्षक से युक्त आलेख पढ़ कर उनके मोदी विरोध का एक और नया रूप देखने को मिला। संघर्ष से युक्त एक लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत के बहुसंख्यक जन के आहत मन को मिलने वाला सुख अल्पसंख्यकवाद से ग्रस्त तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को रास नहीं आया। शायद इसीलिए इन सभी ने अयोध्या के दिव्य प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से न केवल समानांतर दूरी बनाए रखी, अपितु राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रेषित स्नेह आमंत्रण को भी ठुकरा दिया। अयोध्या में श्रीराम के बाल विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा एक धार्मिक आयोजन न होकर भारतीय जन-मन की चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूर्ति का भावनात्मक समारोह था, जिसमें सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सामूहिक भावना का आदर किया है। यह काम 1947 में तभी हो जाना चाहिए था जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने विधर्मी आक्रांताओं द्वारा विध्वंसित किए गए सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू को दो कदम आगे बढ़ कर देश के पौराणिक तीर्थ स्थल अयोध्या काशी, मथुरा सहित देश के उन सभी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को भारतीय पराभव के प्रतीक चिह्नों से मुक्त कर दिए जाने की घोषणा कर देनी चाहिए थी जो स्वाधीन भारत के स्वाभिमान को पददलित करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन्हें भारत के स्वाभिमान से अधिक भविष्य में कांग्रेस पार्टी का सुनिश्चित वोट बैंक बनने वाले उस मुस्लिम वर्ग की चिंता थी जिसके लिए उन्होंने कश्मीर को अनुच्छेद-370 की सौगात देकर एक गणतांत्रिक देश में दो विधान की असंवैधानिक व्यवस्था देने में संकोच नहीं किया। रामलला 37 वर्षों तक टेंट में विराजमान रहे। बावजूद इसके देश का बहुसंख्यक हिंदू वर्ग राम जन्मभूमि के लिए धैर्य पूर्वक संघर्ष करता रहा। ऐसे में देश की जन-भावना को समादृत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के सुकृत्य को गणतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन बताया जाना कहां तक उचित है?

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

11.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है अंतरिम बजट में आधारभूत संरचना के निर्माण में, जिसके माध्यम से देश में सड़क, रेल और अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे का व्यापक रूप से निर्माण किया जा सकेगा।

अंतरिम बजट

झलक रहा है सरकार का आत्मविश्वास

मनोहर मनोज
वरिष्ठ पत्रकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट आगामी आम चुनाव में जीत के प्रति मोदी सरकार के आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि अंतरिम बजट प्रस्तुत होने के पूर्व ही प्रधानमंत्री ने इस बात का इशारा कर दिया था कि उनकी सरकार जुलाई में अपना पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी और इस अंतरिम बजट में आगामी बजट के दिशा-निर्देशों का बस उल्लेख भर होगा। कुल मिलाकर इस बजट से केंद्र सरकार का आत्मविश्वास झलक रहा है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट भाषण में नई लोकप्रिय घोषणाओं के बजाय मोदी सरकार के लगभग सभी निवर्तमान योजनाओं के कशीदे काढ़े गए। वैसे पांच साल पूर्व प्रस्तुत अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, आयकर की सीमा बढ़ाने, असंगठित मजदूरों के लिए पेंशन जैसे कई लोकलुभावन कदमों को जो घोषित किया था, उससे उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने में मदद मिली थी और वही योजनाएं मोदी सरकार की मौजूदा संबल भी बनी हुई हैं।

मोदी सरकार पांच साल पूर्व की तुलना में स्वयं को अभी राजनीतिक तौर पर ज्यादा आरामदेह स्थिति में महसूस कर रही है। इसीलिए वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा को देखते हुए अपने बजट भाषण में आय-व्यय में संतुलन साधने को लेकर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी है। वर्ष 2020 के उपरांत जहां कोविड के कारण भारत सरकार को वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत तक ले जाना पड़ा, वह अब अर्थव्यवस्था की बढ़ती विकास दर और सरकार के बढ़ते राजस्व से घटनी शुरू हो गई है। अंतरिम बजट भाषण में वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित वित्तीय घाटा 5.8 प्रतिशत होने तथा आगामी 2024-25 के लिए 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

वित्त मंत्री के अनुसार 2025-26 तक इसे 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अंतरिम बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय और आधारभूत संरचना के निर्माण की प्राथमिकता पर एक बार फिर से अपना बल दिया है। इसे ध्यान में रखकर पूंजीगत व्यय में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 11.1 लाख करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमारे जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। इसमें रेलवे आधारभूत संरचना में विगत के फ्रेट कारिडोर निर्माण के अलावा तीन और ऊर्जा-सीमेंट-इस्पात ढुलाई कारिडोर, बंदरगाह कनेक्टीविटी कारिडोर और हाई डेनसिटी ट्रैफिक कारिडोर विकसित किए जाने की घोषणा महत्वपूर्ण है। ये चारों कारिडोर पीएम गतिशक्ति की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा होंगे। रेलवे को लेकर इस अंतरिम बजट में जो दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा है, वह पैसेंजर ट्रेनों की मौजूदा 40 हजार बोगियों को भी अपग्रेड किया जाएगा।

मोदी सरकार ने इस अंतरिम बजट के जरिये यह दर्शाया है कि देश के विकास में बुनियादी विकास को वह काफी महत्व देती है। इसी के तहत अंतरिम बजट में भारत के हवाई परिवहन का भी एक वृहद रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि भारत में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी बढ़कर अब 149 हो गई है और टीयर टू और थ्री के शहरों में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसके तहत 570 नए हवाई रूट बने हैं। यही वजह है कि भारत में एक हजार नए हवाई जहाज के खरीद आर्डर दिए गए। अंतरिम बजट में पर्यटन उद्योग के विकास का नया प्रारूप प्रस्तुत किया गया है और भारत के भावी विकास की नई संभावनाओं से इसे जोड़ा गया है। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में मोदी सरकार द्वारा तीन तरह की आधारभूत संरचना यानी भौतिक आधारभूत संरचना, डिजिटल आधारभूत संरचना और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास का संकल्प दिखाई पड़ा।

वित्त मंत्री ने यह दर्शाया कि सरकार ने एक दशक में सात नए आइआइटी, 16 नए ट्रिपल आइटी, दो हजार आइटीआइ, 15 एम्स स्थापित करने के साथ 1.84 करोड़ युवाओं का कौशल विकास किया। सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों मसलन रसोई ईंधन, नल जल, बिजली कनेक्शन, पक्के मकान, मुफ्त राशन, बैंक खाता, शौचालय निर्माण के जरिये पिछले एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला। कुल मिलाकर गांवों में करीब तीन करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए गए और करीब दो करोड़ और पक्के मकान बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, स्व-सहायता समूह के विकास का पूरा उल्लेख किया। देशभर में करीब एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने तथा उन घरों में 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की गई। बताया गया है कि इससे 15 हजार करोड़ रुपये के बिजली की बचत होगी। वित्त मंत्री ने तीन राजनीतिक समूहों मसलन किसान, मजदूर और मध्यवर्ग के अलावा महिलाओं व युवाओं को विशेष रूप से साधने का प्रयास किया है। महिला स्व-सहायता समूहों की प्रगति का ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्री ने इनकी 83 लाख की संख्या को बढ़ाकर एक करोड़ करने की घोषणा की। इसमें नौ करोड़ महिलाओं के स्वरोजगार व जीवन आशा जुड़ी हुई है। इनमें दो करोड़ महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं जिनकी संख्या सरकार तीन करोड़ करना चाहती है।

देश में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या पिछले नौ साल में दोगुनी बढ़कर साढ़े सात करोड़ होने, आयकर की सीमा सात लाख सालाना होने, जीएसटी राजस्व में यथोचित बढ़ोतरी के उल्लेख के साथ वित्त मंत्री ने वर्ष 2010 तक के 25 हजार रुपये तक के प्रत्यक्ष कर बकाये के चल रहे सभी मुकदमे वापस लेने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मोदी सरकार के पिछले करीब दस साल के कार्यकाल में शुरूआती तीन साल और अंतिम तीन साल विकास दर के मामले में उल्लेखनीय रहे। नई आर्थिक नीति और कारपोरेट जनित आर्थिक सुधार के मामलों में चैंपियन रहने के बावजूद नोटबंदी, जीएसटी, लाकडाउन और किसान आंदोलन को लेकर किए गए विवादास्पद फैसलों से आर्थिक विकास दर 2017 से लेकर 2021 तक हतोत्साहित रही, पर अब मौजूदा स्थिति ने मोदी सरकार को मुस्कुराने का मौका दिया है और यह मौका ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव आसन्न है। साथ ही भारतीय राजनीति के आकाश में राममंदिर निर्माण के जरिये उसे एक राजनीतिक सूर्य प्राप्त हो गया है जिसकी रोशनी में मोदी सरकार राजनीतिक रूप से आरामदेह दिख रही है, जो इस अंतरिम बजट में भी परिलक्षित हुआ है, जिसमें लोकलुभावन घोषणाओं की बौछार नहीं है। फिर भी ये लोगों को गुदगुदा रही है। (ईआरसी)

अधिक यात्री भार वाले क्षेत्रों में सुगम यातायात के लिए अंतरिम बजट में नए सिरे से प्रावधान किया गया है। फाइल

बैंकिंग समेत कई अन्य क्षेत्रों को मिलेगी मजबूती

सतीश सिंह

गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट को युवा भारत के युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब कहा गया है और इसमें देश के चार स्तंभों गरीब, युवा, महिला और किसान को सशक्त बनाने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बैंकिंग क्षेत्र को सीधे तौर पर मजबूत बनाने वाले प्रविधानों की घोषणा इस अंतरिम बजट में नहीं की गई है, लेकिन बैंक विकास के मानकों को विकसित करने वाले सभी क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम करता है और सरकार भी बहुत सारी बजटीय घोषणाओं को मूर्त रूप बैंकों की मदद से देती है, इसलिए दूसरे क्षेत्रों के लिए किए गए बजटीय प्रविधानों का लाभ तभी उन क्षेत्रों को मिल पाएगा, जब बैंक उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए बजटीय प्रविधानों में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। अंतरिम बजट घोषणा के अनुसार ऊर्जा एवं सीमेंट कारीडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कारीडोर आदि को भी यथाशीघ्र विकसित किया जाएगा। इन कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए पूंजीगत व्यय में 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कोरोना महामारी से सबक लेते हुए अस्पतालों का भी निर्माण करने की घोषणा भी अंतरिम बजट में की गई है, जिससे बैंक के कारोबार में वृद्धि होने की संभावना है।

बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि विगत एक दशक में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं उद्यमियों को दिए गए हैं। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। यह सब संभव हो सका है लोगों की पहुंच बैंक तक सुगम होने की वजह से। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना से लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और पीएम सम्मान निधि की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की मदद से महज कुछ सेकेंड में लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट करना संभव हो पा रहा है। अनुसंधान और नवोन्मेष को विकसित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा, ताकि तकनीक और बैंक की मदद से गरीब, युवा, किसान और महिला आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही स्टार्टअप को दिए जाने वाले कर छूट का विस्तार करने की घोषणा भी बजट में की गई है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को फायदा होना निश्चित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पांच वर्षों में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ घर और बनाए जाएंगे। झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सरकार पक्का मकान बनाएगी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाया जाएगा और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंडरी जैसी नयोजनाओं को शुरू किया जाएगा। सरकार मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। उपरोक्त के आलोक में यह कहना समीचीन होगा कि गरीब, युवा, महिला और किसान को सशक्त बनाने वाले उपायों और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाले प्रविधानों से उधारी व जमा दोनों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे बैंकों की सेहत और भी बेहतर होगी। (लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

खरी-खरी

कवि की मौलिकता

गोविंद भारद्वाज

हमारे शहर के जाने-माने एक कवि हैं- सुंदर लाल 'सुंदर'। जितना उनका नाम सुंदर है उतना वे सुंदर नहीं हैं। हां, अपने घर परिवार में सबसे सुंदर हैं, शायद इसीलिए उनका नाम बड़ा सोच-विचार कर रखा हो। सुंदर जी बचपन में चोर कवि थे, यानी वे इधर-उधर से कविता चुराकर अपने स्कूल की बाल सभा में सुनाते थे। स्कूल के सारे पुरस्कार उन्हीं को मिलते थे। वैसे कविताएं चुराना कोई हंसी-खेल थोड़ी है। यह भी एक कला है। जो अपनी कला में पारंगत हो वही श्रेष्ठ कलाकार होता है।

हमारे सुंदर लाल 'सुंदर' की एक बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठियों में बिना बुलाए चले जाते हैं। उनका कहना है कि इंसान को कभी बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। बुलावे के चक्कर में बैठे रहोगे तो बन लिए बड़े कवि। घुसपैठ करने की उन्हें अच्छी आदत है। बेचारे शहर भर के आयोजक उनकी शक्ल देखकर घबरा जाते हैं।

सुंदर लाल 'सुंदर' की कविताएं तो बहुत सुंदर होती हैं, कारण मैंने बता ही दिया। वह जितना समय अन्य कवियों की कविताएं चुराने में लगाते हैं, उतना ही समय उनमें थोड़ा फेरबदल करने में लगाते हैं। कोई वाह-वाह करे या न करे, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। 'कविताएं मौलिक हो न हो, कवि मौलिक होना चाहिए' यह कथन सुंदर लाल 'सुंदर' का ही है। वैसे देखा जाए तो बात भी बिल्कुल सही है। कवि की मौलिकता का प्रमाण तो मिल सकता है, लेकिन रचना की मौलिकता किसने देखी। मौलिकता से मतलब यहां यह भी है कि कभी-कभी सुंदर लाल 'सुंदर' किसी नवोदित कवियों से कविताएं खरीद भी लेते हैं। सुंदर लाल 'सुंदर' की इस विशेष रुचि से काव्य प्रेमी बहुत खुश हैं। इसका कारण है कि उन्हें एक ही कवि से कई कवियों की कविताएं सुनने को एक ही मंच पर मिल जाती है। यह किसी खास बात से कम थोड़ी है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपके शहर में यदि स्वरुचि कवि सम्मेलन हो और आपके आगमन तक जारी रहे तो उसमें हमारे मित्र सुंदर लाल 'सुंदर' को बुलाना न भूलें। यह कवि आपके दीदार के इंतजार में हमेशा तत्पर हैं।

X पोस्ट

आयकरदाताओं के लिए अंतरिम बजट में इतना ही है कि वह सरकार से तारीफ, आइटीआर भरने की सहूलियत और उनके द्वारा भरे टैक्स का वाजिब इस्तेमाल की गारंटी का झुनझुना लेकर खुश रहे।
विक्रांत@vikrantkumar

सोलर पैनल लगाने वालों को 300 यूनिट बिजली की सब्सिडी उन लोगों और प्रकृति का हित करने वाली एक समझदार योजना है। यही काम दमघोंटू कोयले की बिजली बांटने वाली राज्य सरकारें भी कर सकती थीं। देर से ही सही, पर किसी को तो अक्ल आई कि जलवायु रक्षा केवल भाषणों से नहीं हो सकती। लोगों को लाभ भी दिखना चाहिए। शिव कांत@shivkant

अंतरिम बजट का सार है कि वित्त मंत्री राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर प्रधानमंत्री की विरासत को लेकर संजीदा हैं। कोई चुनावी रेवड़ी नहीं और प्राथमिकता के आधार पर ही आवंटन। चुनाव से पहले लोकलुभावनवाद से परहेज का वित्त मंत्री ने भरपूर साहस दिखाया, जबकि 2014 में संप्रग ने खैरात बांटी थी। पीएम और वित्त मंत्री आश्वस्त हैं कि मतदाता सरकार के दस वर्षों के शासन पर विश्वास जताएंगे।
राहुल शिवशंकर@RShivshankar

जागरण जनमत — कल का परिणाम

हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज कराना इसके दुरुपयोग का उदाहरण है?

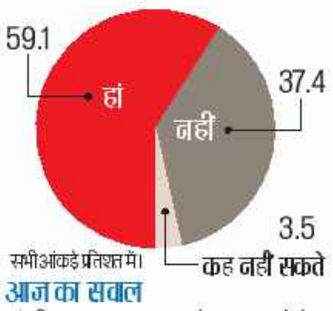

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

अंतरिम बजट सरकार के इस भरोसे का परिचायक है कि वह फिर सत्ता में आने जा रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

नवपीढ़ी इतिहास को जाएगी ही भूल,
अगर बताएं न उन्हें हम विवाद का मूल।
हम विवाद का मूल शूल जो गए चुभाए,
मठ-मंदिर को तोड़ आरती बंद कराए।
उनकी उंगली थाम चढ़े मंदिर की सीढ़ी,
ताकी अपना मूल नहीं भूले नवपीढ़ी।
- ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड डायरी

भ्रष्टाचार का भंवर और साख पर सवाल

झारखंड के हालिया घटनाक्रम ने पहली बार पूरे देश का ध्यान खींचा है। क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के हाथ से सत्ता फिसल गई है।

मुख्यमंत्री रहे मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बुधवार की देर शाम उन्होंने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। वर्ष 2019 के अंतिम माह के अंतिम सप्ताह में भाजपा के हाथों से सत्ता छीनने वाले हेमंत सोरेन चार साल से थोड़ा ज्यादा समय सीएम के पद पर रहे। हेमंत के इस्तीफे के बाद बुधवार रात से गुरुवार आधी रात तक नई सरकार के गठन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को देख ऐसा लगा कि 24 वर्ष पहले बिहार से पृथक हुआ यह राज्य एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। हालांकि देर रात राज्यपाल ने चम्पाई सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। झारखंड में 24 वर्ष में 11 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। हेमंत सोरेन पहले भी 13 महीने सीएम रहे हैं। अर्जुन मुंडा को अलग-अलग अवधि में तीन बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। शिबू सोरेन ने भी दो बार कम समय के लिए कुर्सी संभाली। एक वक्त ऐसा भी आया, जब निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गए। अलग-अलग कारणों से सरकारों का गिरना-बनना इस दरम्यान होता रहा। पांच वर्ष का कार्यकाल सिर्फ रघुवर दास पूरा कर पाए। रघुवर दास अभी ओडिशा के राज्यपाल हैं। इससे इतर झारखंड के साथ देश के मानचित्र पर उभरे दो अन्य राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ा। दरअसल, छोटे राज्य बनाने के पीछे तत्कालीन केंद्र सरकार की सोच थी कि इससे अछूते और सुदूर इलाकों का विकास हो सकेगा, लेकिन झारखंड में यह परिकल्पना धरातल पर नहीं उतरी।

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (दाएं से दूसरे) को अपना इस्तीफा सौंपते हेमंत सोरेन (बाएं से दूसरे)। फाइल

सच्चाई तो यह है कि एक समय यह राज्य दिल्ली में कमीशन-खंड तक कहा जाने लगा था। इसके पीछे वजहें भी है। झारखंड में सत्ता के गलियारे के प्रकरण की अनुगूंज अन्य प्रदेशों तक पहुंची तो यह अनायास या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं था। सत्ता के आसपास प्रभावी भूमिका निभाने वाले चेहरों की एक लंबी सूची यहां हैं, जो अपने पीछे कई कहानियां छोड़ गए हैं। कोड़ा के एक करीबी जमशेदपुर के संजय चौधरी ने तो आरोपों से पिंड छुड़ाकर देश ही छोड़ दिया। अभी तक उसे केंद्रीय एजेंसियां खोज नहीं पाई है। बताया जाता है कि काली कमाई से उसने दुबई में आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है। कोड़ा और उनके कई करीबी अभी भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी को गिरफ्तार करने की नौबत आने तक की पूरी कहानी समझने के लिए इसके पार्श्व में जाना होगा। ऐसे कई लोग अभी ईडी की कार्रवाई की चपेट में आकर जेल की हवा खा रहे हैं जो सत्ता के बाएं-दाएं कहे जाते थे। आरंभ में इनकी कहानियां अधिकारियों-नेताओं तक इनकी पहुंच और प्रभाव के किस्से तक सीमित थे, लेकिन ईडी ने जब यहां कार्रवाई आरंभ की तो इसका अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि इसकी चपेट में सत्ता का शीर्ष पद भी आ जाएगा।

देश में सबसे कम उम्र में भारतीय प्रशासनिक पद के लिए चयनित होने का गौरव जिस पूजा सिंघल नामक अधिकारी के पास था, वह भ्रष्टाचार की 'पूजा' करने वाली निकलीं। इस महिला अधिकारी का पूरा करियर चौपट हो गया। वह सलाखों के पीछे हैं और उनकी ज्यादातर संपत्ति को ईडी अटैच कर चुकी है। युवा आइएएस अधिकारी छवि रंजन ने प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग की 'छवि' को दागदार किया। जिस अधिकारी पर फर्जीवाड़ा पकड़ कर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, वही जमीन के फर्जी कागजात बनाकर हेरफेर करने वाले गिरोह का संरक्षक बन बैठा।

दरअसल प्रभावी नेताओं और लालची अधिकारियों का वरदहस्त प्राप्त कर कुछ ऐसे अवसरवादी तत्वों को मध्यस्थ बनने का मौका मिलता है जो देर-सवेर पूरे तंत्र को हांकने की जुगत में लग जाते हैं। इसका अंजाम आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। इस सिंडिकेट ने इस पिछड़े राज्य को बुरी तरह पीछे धकेला है, जहां कुपोषण, गरीबी दर, कम साक्षरता, राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे संसाधनों की उपलब्धता समेत कई जटिलताएं मुंह फाड़े खड़ी है। ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य की साख पर सवाल उठाया है। इन घटनाओं से सीख नहीं ली गई तो आगे आने वाले दिनों में नाम और चेहरे भले ही बदल जाएं, लेकिन झारखंड की फितरत बदलने में वक्त लगेगा।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस

पर्यावरण संरक्षण की कड़ियां

रमन कांत
अध्यक्ष, भारतीय नदी परिषद

नमभूमियों का पर्यावरण संरक्षण में व्यापक योगदान है। इनके संरक्षण के लिए हमें वैसी हर गतिविधि को रोकना होगा, जिस कारण नमभूमियों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचती हो

आर्द्रभूमियां हमारे वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके कारण पृथ्वी की जैवविविधता सबल बनी हुई है। जैवविविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमियां (वेटलैंड्स) अत्यंत संवेदनशील होती हैं। विशेष प्रकार की वनस्पतियां ही आर्द्रभूमि पर उगने और फलने-फूलने के लिए होती हैं। आर्द्रभूमियां जहां विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए सुरक्षित पनाहगाह होती हैं, वहीं मानव जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वेटलैंड्स अत्यंत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो जलवायु परिवर्तन व मीठे पानी की उपलब्धता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नमभूमियों के प्रति जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष दो फरवरी को इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिन आर्द्रभूमियों (नमभूमियों) की वर्षगांठ का भी प्रतीक है, जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में अपनाया गया था, जो 1975 में प्रभावी हुआ। वर्ष 2024 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस को 'आर्द्रभूमि और मानव भलाई' की थीम दी गई है। यह थीम आर्द्रभूमियों के प्रति मनुष्य के जुड़ाव को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तय की गई है। रामसर समझौते के अनुसार आर्द्रभूमि ऐसा स्थान होता है जहां वर्ष में कम से कम आठ माह तक पानी भरा रहता है। ये सैकड़ों मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। ये आर्द्रभूमियां तीन प्रकार की होती हैं। अंतर्देशीय आर्द्रभूमियों में दलदल, झीलें, नदियां व बाढ़ के मैदान आते हैं। तटीय आर्द्रभूमियों में खारे पानी के क्षेत्र, ज्वारनदमुख, मैंग्रोव व मूंगे की चट्टानें शामिल होती हैं, जबकि मानव निर्मित आर्द्रभूमियों में तालाब प्रमुखता से आते हैं। विश्व में लगभग 2500 रामसर साइट मौजूद हैं, जो विश्व के लगभग 26 करोड़ हेक्टेयर भूमि में मौजूद हैं। विश्व में सर्वाधिक लगभग 1,132 रामसर क्षेत्र यूरोप में हैं। भारत में 75 रामसर क्षेत्र चिह्नित हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग 13.26 लाख हेक्टेयर है। हमारे देश ने इस वर्ष पांच और वेटलैंड्स को रामसर साइटों के रूप में नामित किया है जिससे इनकी संख्या 75 से बढ़ाकर 80 हो गई है।

संकट में नमभूमि : वर्तमान में भारत सहित तमाम विश्व की आर्द्रभूमियां संकट के दौर से गुजर रही हैं। विगत करीब 200 वर्षों में विश्व की लगभग 90 प्रतिशत नमभूमियां आधुनिकता की भेंट चढ़ चुकी हैं। यह सब मानवनिर्मित गतिविधियों के कारण हो रहा है। आर्द्रभूमियों से मनुष्यों को मिलने वाले अनेक लाभों के बावजूद प्रतिदिन आर्द्रभूमियों को मनुष्यों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। आर्द्रभूमियों को बेतरतीब कृषि व्यवस्था से बड़ी क्षति होती है। शहरों के निकट स्थित नमभूमियां सर्वाधिक मानव दखल के कारण प्रदूषित हो रही हैं जिसमें पालीथीन का प्रदूषण प्रमुख है। बेतरतीब बढ़ते कस्बे व शहर तथा उनमें मानव बसावट वहां आर्द्रभूमियों के लिए खतरा है। जैसे-जैसे शहर बढ़ते हैं, वैसे वैसे भूमि की मांग बढ़ती जाती है, ऐसे में आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और ये जंगलों की तुलना में तीन गुना तेजी से गायब हो रही हैं।

नदियों का क्षय : नदियां भी आर्द्रभूमि का हिस्सा हैं। भारत का संपूर्ण नदी तंत्र अर्थात हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीय नदी तंत्र के संग्रहण क्षेत्र में ही देश की अधिकतर नमभूमियां अवस्थित हैं। गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तो उससे पहले वहां बड़े स्तर पर नम भूमि विकसित करती है जिसे ज्वारनदमुख के रूप में भी जाना जाता है। यहीं पर मैंग्रोव वन पनपते हैं, जो भारत को स्वस्थ मानसून प्रदान करते हैं। नदियों के किनारे बाढ़ के कारण बनने वाली नमभूमियों के भी संरक्षण की आवश्यकता है। नदी किनारे की नम भूमियां व नदी एक दूसरे की पूरक होती हैं। इन नम भूमियों से जहां नदी किनारे का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है, वहीं नदी के जलीय जीव अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी इन नमभूमियों का उपयोग करते हैं। ये जलीय जीव एक प्राकृतिक व्यवस्था के तहत नदी में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करते हैं। इन नम भूमियों में प्रवासी पक्षी भी आते हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा इस ओर निरंतर ध्यान खींचा जा रहा है। गांव प्रधानों को अपने गांव में एक तालाब/ सरोवर को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य दिया जाना हो या बड़ी संख्या में अमृत सरोवर बनाने आह्वान करना हो, प्रधानमंत्री के इस संदेश से देश में हजारों की संख्या में तालाब पुनर्जीवित हुए हैं तथा समाज में अपने जल स्रोतों के प्रति नई चेतना आई है। नदियों के संभरण क्षेत्र में अवैध रूप से कृषि कार्य या अतिक्रमण न करके, वहां के जीवों का शिकार न करके, वृक्षों को न काटते हुए तथा जाने-अनजाने किसी भी प्रकार की नमभूमि को प्रदूषित न करके भी हम इनके संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं।

नदियों के बहाव व उनके उत्तम स्वास्थ्य में नदी किनारे की नम भूमियां बहुत उपयोगी होती हैं। फाइल

****

20 एडिशनल डीसीपी को नए आपराधिक कानून अप्रैल से पहले दिल्ली में लागू किए जाने की संभावना के बीच सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी, भोपाल में तीन दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, जो गुरुवार से शुरू हो गई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 फरवरी, 2024

आज का मौसम

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह से मध्यम से घना कोहरा होगा

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
2 फरवरी	20.0	09.0
3 फरवरी	20.0	08.0
नोएडा		
2 फरवरी	20.0	09.0
3 फरवरी	10.0	09.0
गुरुग्राम		
2 फरवरी	18.0	9.0
3 फरवरी	19.0	9.0

डिग्री सेल्सियस में

नमो भारत के दिल्ली-मेरठ कारिडोर को मिलेगी रफ्तार

नई दिल्ली : केंद्रीय अंतरिम बजट में दिल्ली में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास पर फोकस है। इसके लिए किए गए बजटीय आवंटन में यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं तथा कानून-व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता झलकती है। विभिन्न विभागों के लिए इतनी राशि का प्रविधान किया गया है, जिससे कि वे अपनी कार्य कुशलता में सुधार ला सकते हैं।

आरआरटीएस के लिए 3596 करोड़ रुपये का प्रविधान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में नमो भारत अब और रफ्तार पकड़ेगी। इस वर्ष केंद्रीय अंतरिम बजट में रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए अच्छा बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2025 में दिल्ली-मेरठ कारिडोर पूरी तरह शुरू हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली-अलवर और दिल्ली-पानीपत कोरिडोर का कार्य भी गति पकड़ लेगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय अंतरिम बजट में देश के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए 3,596 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में भी इतनी ही राशि आवंटित की गई थी, जबकि वर्ष 2022-23 में 4,710 करोड़ रुपये दिए गए थे। एनसीआर परिवहन निगम ने इस बार भी बजट को कम नहीं बताया है। अधिकारियों के मुताबिक जितने बजट की मांग की गई थी, कमोबेश उसी के अनुरूप आवंटित किया गया है।

केंद्रीय अंतरिम बजट में दिल्ली

आरआरटीएस। फाइल फोटो

यहां यह भी उल्लेखनीय केंद्र सरकार ने आरआरटीएस के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 629 करोड़, 2019-20 में 974 करोड़, 2020-21 में 2487.40 और 2021-22 में 4,472 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था। जानकारी के मुताबिक 82 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ कारिडोर का कार्य लगातार गति पकड़ रहा है। दुहाई से साहिबाबाद के बीच इसके 17 किमी लंबे प्राथमिकता खंड पर ट्रेन का परिचालन गत अक्टूबर से शुरू हो ही चुका है। मार्च 2025 तक पूरे कारिडोर पर परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है। अधिकारी बताते हैं कि आनंद विहार अंडरग्राउंड स्टेशन कारिडोर के एलिवेटेड सेक्शन से जुड़ गया है। न्यू अशोक नगर से आनंद विहार स्टेशन को जोड़ने के लिए खिचड़ीपुर में एक रैम्प बनाया गया है। दूसरी ओर आनंद विहार अंडरग्राउंड स्टेशन को साहिबाबाद स्टेशन से जोड़ने के लिए दूसरा रैम्प बनाया गया है, जो वैशाली में है। जल्द ही इनमें ट्रैक बिछाने और ओएचई इस्टालेशन का कार्य आरंभ होगा। न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक पांच किमी की दूरी बारापूला फ्लाईओवर से यमुना पुल तय करते हुए पूरी होगी। यमुना पर पुल बन चुका है, बारापूला फ्लाईओवर आधा बन गया है तो सराय काले खां स्टेशन के सभी लेवल बन चुके हैं। अगले पांच माह में ट्रैक का काम लगभग पूरा हो जाएगा और उसके बाद ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा।

एम्स को चार चिकित्सा संस्थानों को प्रस्तावित बजट का 50.83 प्रतिशत हिस्सा मिला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राजधानी में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए केंद्रीय अंतरिम बजट में नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक बजट आवंटित करने का प्रविधान किया गया है। खास यह है कि एम्स, सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज (एलएचएमसी) एलोपैथी के चार बड़े चिकित्सा संस्थानों को अंतरिम बजट में जितनी राशि आवंटन का प्रविधान किया गया है, उसका 50.83 प्रतिशत हिस्सा अकेले एम्स को मिला है। इससे एम्स को इलाज की अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। साथ ही एम्स में लंबित मास्टर प्लान की योजना को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एम्स सहित एलोपैथी के इन चार बड़े चिकित्सा संस्थानों को 8897 करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान किया गया है। पिछले बजट में इन चारों चिकित्सा संस्थानों को 8196.87 करोड़ रुपये का

बजट मिला था। एम्स को इस बार 4523 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट मिला है। एम्स के मीडिया डिवीजन की प्रभारी डा. रीमा दादा ने कहा कि इलाज में इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा तकनीक को अपग्रेड किया जाना है।

आरएमएल अस्पताल में करीब 550 बेड का सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक अप्रैल तक शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा एमबीबीएस के छात्रों के लिए मेडिकल कालेज के भवन का निर्माण भी होना है। इस वजह से इस अस्पताल को पहली बार डेढ़ हजार करोड़ से ज्यादा 1610 करोड़ का बजट मिला है। लेडी हार्डिंग मेडिकल और उससे जुड़े कलावती सरण अस्पताल को 930 करोड़ का बजट मिला है।

प्रदूषण से जंग में सीपीसीबी को मिले 113 करोड़, सीएक्यूएम को 116 करोड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय अंतरिम बजट में प्रदूषण से जंग के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 113 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। गत वर्ष 105 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसी तरह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को 116 करोड़ आवंटित हुए हैं, जो वर्ष 113 करोड़ रुपये था। सीपीसीबी के सदस्य डा. अनिल गुप्ता ने केंद्र के बजट में पर्यावरण संरक्षण का ख्याल रखे जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी सरकार की प्रतिबद्धता ही दर्शाता है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीटयूट (टेरी) की महानिदेशक डा. विभा धवन ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से भी पर्यावरण संरक्षण में खासी मदद मिलेगी।

न्यूज गैलरी

अमानतुल्ला के विरुद्ध ईडी समन पर रोक से इन्कार

नई दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में अनियमितताओं से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। गुरुवार को अमानतुल्ला के अधिवक्ता के उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने मामले की सुनवाई दो फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न तो मामले में नोटिस जारी किया गया है और न ही अमानतुल्ला के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया है। (जासं)

संसद सत्र में शामिल होने को संजय सिंह ने मांगी जमानत

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित आप नेता संजय सिंह की अर्जी पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया। संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए चार से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने ईडी को सिंह की अर्जी पर तीन फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी। (जासं)

सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आज उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति

फरीदाबाद : देश-विदेश के हस्तशिल्पियों का महाकुंभ शुक्रवार से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन करेंगी। मेले में लगभग 50 देश भाग ले रहे हैं। मेला 18 फरवरी तक चलेगा। संयुक्त गणराज्य तंजानिया की पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदारी है। थीम राज्य गुजरात है। पूर्वोत्तर के आठ राज्य सांस्कृतिक भागीदारी कर रहे हैं। (जासं)

और भी हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, सुधरेगा यातायात प्रबंधन

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

- अंतरिम बजट में दिल्ली पुलिस को मिले 11397.98 करोड़
- पिछले बजट की तुलना में 535 करोड़ रुपये कम का बजट

2024-2025 के केंद्रीय अंतरिम बजट में इस बार दिल्ली पुलिस को 11397.98 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में करीब 535 करोड़ रुपये कम है। 2023-2024 के बजट में दिल्ली पुलिस को 11932.03 करोड़ रुपये मिला था। जी-20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों को लेकर पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक बजट मिला था ताकि दिल्ली पुलिस अपने ढांचागत सिस्टम को मजबूत कर सके। साथ ही बड़ी संख्या में कैमरे व वाहन भी खरीदने थे। इस बार मिले 11397.98 करोड़ रुपये से भी दिल्ली पुलिस को और हाईटेक बनाने और यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी।

दिल्ली के करीब 13 थाने अभी भी या तो किराए के भवनों में चल रहे हैं या सरकारी भूमि पर टिन के शेड में चल रहे हैं। अब तक सभी पुलिसकर्मियों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पड़ोसी राज्यों से रोज ड्यूटी करने दिल्ली आते-

नया पुलिस मुख्यालय। फाइल फोटो

जाते हैं। लिहाजा बड़ी राशि भवन निर्माण में खर्च की जाएगी।

दिल्ली पुलिस उन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करेगी, जहां कैमरे नहीं लगे हैं। इस बजट में दिल्लीभर में सीसीटीवी सुरक्षा निगरानी प्रणाली की स्थापना, कानून और व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न उन्नत उपकरणों की खरीद, साइबर हाईवे और डिजिटल ट्रैकिंग रेडियो सिस्टम जैसी संचार प्रणाली के उन्नयन के अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किए गए हैं। पुलिस के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन और खरीदे जाएंगे। करोड़ों रुपये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत कार्यालयों के निर्माण, आवासीय भवनों और नए पुलिस मुख्यालय भवन के संचालन और रखरखाव के लिए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है, ऐसे में अधिकारियों के बैठने के लिए कार्यालय भी बनाने होंगे। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उपायों जैसे छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण आदि पर भी राशि खर्च की जाएगी।

निर्भया फंड के लिए इस बार भी बढ़ाकर बजट नहीं दिया गया है। शहर की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने, यातायात प्रबंधन व नियमित खर्चों के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं जैसे यातायात और संचार नेटवर्क का विकास करने, माडल यातायात प्रणाली विकसित करने, प्रशिक्षण को अपग्रेड करने, दैनिक कामकाज में नवीनतम तकनीक को खरीदने और यातायात संकेतों को दुरुस्त करने आदि के लिए भी बजट दिया गया है।

विकास की गति को तेज करने वाला बजट : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को विकास की गति तेज करने वाला बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अंतरिम बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमृत काल विजन को दर्शाता है। यह गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को समर्पित है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में मदद मिलेगी। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ गरीबों को आवास और एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए काम किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया गया है। ई-बस, मेट्रो विस्तार एवं पर्यावरण विकास के प्रविधान का लाभ दिल्ली को भी मिलेगा।

वीरेंद्र सचदेवा

बिधूड़ी बोले, देश के विकास का रोडमैप : दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अंतरिम बजट देश के विकास का रोडमैप है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह विकास के पथ पर अग्रसर है, यह बजट उसकी तस्वीर पेश करता है। लोकसभा चुनाव में विजयी होकर मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसमें विकास को और गति मिलेगी।

केंद्र का अंतरिम बजट बहुत ही निराशाजनक : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केंद्र के अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया है। कहा कि देश के ज्वलंत मुद्दों यानी युवाओं को रोजगार व महंगाई नियंत्रण जैसे विषयों पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। कटाक्ष किया कि भाजपा सरकार के अच्छे दिन किसके लिए आए हैं, यह पूरा देश जानता है।

अरविंदर सिंह लवली

लवली ने कहा कि अंतरिम बजट में नौकरी पेशा, छोटे-बड़े कारोबारियों, महिलाओं, किसानों और गरीबों को भी किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में भी जनता को राहत नहीं देने के बाद भाजपा की मंशा साफ नजर आती है कि उसे जनता की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। 10 वर्षों के कुशासन में भाजपा सरकार ने जनता की उम्मीदों को तोड़ा है।

लवली ने कहा कि भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित बजट से कम राशि खर्च करना असंतोषजनक है।

बजट है जुमला, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार : आतिशी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को जुमला करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महंगाई कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली के साथ केंद्र सरकार हमेशा सौतेला व्यवहार करती है। जितना टैक्स दिल्ली की जनता देती है, उसे देखते हुए केंद्र को दिल्ली को 15,000 करोड़ देना चाहिए था। केंद्र ने सभी स्थानीय निकायों को पैसा दिया है, लेकिन एमसीडी को एक भी रुपया नहीं दिया।

आतिशी

मालीवाल ने कहा, महिला सुरक्षा और उत्थान सिर्फ कागजों पर : आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इस अंतरिम बजट को आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला बताया। मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि इस बार भी आम जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कोई टैक्स रियायत नहीं, पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं, महंगाई कम करने की कोई बात नहीं। महिला सुरक्षा और उत्थान सिर्फ कागज पर।

एलजी ने सभी डीएम से मांगी ग्रामीणों की समस्याओं और समाधान पर रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली ग्रामोदय अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए परियोजनाओं को कम समय में पूरा करने के निर्देश
- फरवरी के मध्य में मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागों के प्रमुख गांवों में करेंगे रात्रि प्रवास

एलजी वीके सक्सेना ने जिलाधिकारियों से दो दिनों में ग्रामीणों की पांच बड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल, एलजी ने सभी डीएम द्वारा गांवों में उनके पिछले दो 'संवाद' दौरों से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य डीडीए के 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत आगे का रास्ता तैयार करना था।

सक्सेना के निर्देश पर सात-आठ और 27-28 जनवरी को चिह्नित गांवों का दौरा करने वाले डीएम ने गांव में रातभर रुकने के अलावा उन गांवों के निवासियों से उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारियों ने डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आइएंडएफसी) आदि सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का दौरा किया था। बैठक के

वीके सक्सेना। फाइल फोटो

दौरान उन्होंने एलजी से अपने अनुभव साझा किए और उन्हें जमीनी हकीकत व वहां से मिली फीडबैक की जानकारी दी।

एलजी ने सलाह दी कि 'दिल्ली ग्रामोदय अभियान' के तहत शुरू की जाने वाली इन परियोजनाओं को कम से कम समयसीमा में लागू किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इनका लाभ तुरंत मिल सके। एलजी ने यह भी निर्देश दिया कि इस माह के मध्य में प्रस्तावित अगले दौरे में मुख्य सचिव के अलावा प्रधान सचिव, सचिव और विभाग प्रमुख स्वयं चिह्नित गांवों का दौरा करेंगे तथा वहां रातभर रुक कर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने जिलाधिकारियों से हर शनिवार को गांवों में नियमित फील्ड विजिट करने को भी कहा।

एलजी को बताया गया कि सभी गांवों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम अग्रिम चरण में है। 69 गांवों में पहले ही गैस उपलब्ध करा दी गई है, 39 गांवों में एक महीने के भीतर काम पूरा होने की उम्मीद है और 142 गांवों में सर्वे किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव के अलावा डिवीजनल कमिश्नर, डीडीए के उपाध्यक्ष, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी), सीईओ (जल बोर्ड), आयुक्त (एमसीडी) और सभी जिलाधिकारियों समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

उद्यान उत्सव 2024...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 'उद्यान उत्सव 2024' का शुभारंभ किया। इस उत्सव के अंतर्गत यह उद्यान दो फरवरी से 31 मार्च तक (सोमवार को छोड़कर) आम लोगों के लिए खुला रहेगा। 15 एकड़ में फैले इस प्रसिद्ध उद्यान में इस बार एक पुष्प घड़ी तथा सेल्फी प्वाइंट के अतिरिक्त फूलों की 85 से अधिक प्रजातियां प्रदर्शित हो रही हैं। आगंतुकों के लिए 18 किस्मों के 42 हजार ट्यूलिप वाला एक थीम गार्डन भी विकसित किया गया है। 225 वर्ष पुराना शीशम का पेड़ एवं बोनसाई उद्यान आगंतुकों के लिए प्रमुख आकर्षणों में से हैं। प्रेट्र

'अंग और ऊतक दान पर दो महीने में केंद्र सरकार तय दिशानिर्देश'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नाबालिगों द्वारा जीवित अंग या ऊतक दान के आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकारी और राज्य सरकारों के संदर्भ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो महीने में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम-2014 के नियम-पांच(तीन)(जी) में कहा गया है कि असाधारण चिकित्सा आधारों के अलावा नाबालिगों द्वारा जीवित अंग या ऊतक दान की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि असाधारण चिकित्सा आधारों की प्रकृति को इंगित करते हुए दिशानिर्देश तय किए जाने चाहिए जिन्हें उपयुक्त प्राधिकारी और राज्य सरकारों द्वारा पूरे देश में अपनाया जा सकता है।

अदालत ने यह आदेश एक 17 वर्षीय लड़की द्वारा उसके बीमार पिता को अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने के लिए आवश्यक अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

आयोजन

केंद्रीय आयुष मंत्री ने किया चार दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन, जागरण समूह के श्री पूरनचन्द्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट व आयुष मंत्रालय ने आयोजित किया है मेला

भारत में आज 900 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप : सोनोवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

केंद्रीय आयुष, जहाजरानी, पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि देश में आयुष इस तेजी से बढ़ रहा है कि आज यहां 900 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप हैं। इनमें एक यूनिकार्न भी है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को देश-दुनिया में पहुंचाने के लिए स्टार्टअप की संख्या बढ़ाई जाएगी।

सोनोवाल गुरुवार को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चार दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन करने के दौरान समारोह को संबोधित कर रहे थे। दैनिक जागरण समूह के श्री पूरनचन्द्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट और आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोनोवाल ने कहा कि आयुष को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों 10 लाख करोड़ रुपये निवेश के 307 एमओयू साइन हुए हैं। भविष्य में इसे 80 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयुष क्षेत्र में विविधता, नवाचार और स्वास्थ्य सुरक्षा

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में दैनिक जागरण समूह के श्री पूरनचन्द्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट और आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेले 2024 को संबोधित करते केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंच पर (बाएं से) मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, डीडीजी आयुष मंत्रालय सत्यजीत पाल और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसरी। जागरण

वितरण की भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। यह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि दुनियाभर में लोग योग दिवस, आयुर्वेद दिवस और आयुष की अन्य विधाओं से संबंधित कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं। मंत्रालय का 'हर दिन हर घर आयुष' अभियान लोगों को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को हर कीमत पर आगे बढ़ाना है।

केंद्रीय मंत्री ने किया स्टाल का निरीक्षण

केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने मेले में लगे विभिन्न स्टाल का निरीक्षण किया। मेले में आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े 72 स्टाल लगाए गए हैं। इस मौके पर डीडीजी आयुष मंत्रालय सत्यजीत पाल, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसरी, दैनिक जागरण के मुख्य महाप्रबंधक नीतेंद्र श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर अनंत विजय और वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) विकास चंद्र भी मौजूद थे।

गुरु दीपक महाराज ने किया कथक डांस

मेले में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इसमें कथक सम्राट बिरजू महाराज के पुत्र गुरु दीपक महाराज ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। दर्शक उनके नृत्य को देखकर भावविभोर हो गए।

अवैध निर्माण से झुग्गी बस्ती बन गया है शहर : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कहा, डीडीए- एमसीडी अधिकारी बंद करें एक-दूसरे पर दोष मढ़ना

राजधानी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शहर एक झुग्गी बस्ती बन गया है। दिल्ली के केंद्र में स्थित संरक्षित स्मारक निजामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की खिंचाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अधिकारियों को एक-दूसरे पर दोष मढ़ना बंद करना चाहिए। बहुत दुखद है कि आपने शहर को इस स्तर पर पहुंचा दिया है।

अदालत ने यह गंभीर टिप्पणियां डीडीए की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए गेस्ट हाउस की ऊपरी मंजिल पर किए गए अवैध निर्माण से जुड़े मामले में की। उस गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया था। कोर्ट ने इमारत के मालिक को पेश होने को कहते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया इस मामले की जांच सीबीआइ से कराने की जरूरत है। सीबीआइ के एक्शन में आने के बाद अधिकारियों का आपस में दोष मढ़ना बंद हो जाएगा। अदालत ने इमारत के मालिक के वकील से यह बताने को भी कहा कि अधिकारियों द्वारा निचली मंजिलों को डी-सील नहीं करने के बावजूद दूसरी और पांचवीं मंजिल के बीच निर्माण कैसे किया गया? अदालत जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।

****

29 हजार से अधिक पद रिक्त हैं पुलिसकर्मियों के गुजरात में। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर यह जानकारी दी है। राज्य में 1,25,350 स्वीकृत पद हैं।

न्यूज गैलरी

पीएम मोदी ने हिमंत को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जन्मदिन की बधाई देते हुए असम की विकास यात्रा को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। मोदी के बधाई के एक्स पोस्ट पर हिमंत ने भी एक्स पोस्ट कर आभार जताया। बता दें कि तीन और चार फरवरी को प्रधानमंत्री असम के दौरे पर हैं। इस दौरान वह 11 हजार करोड़ के कल्याणकारी कार्यों की आधारशिला रखेंगे और लोगों को समर्पित करेंगे। (एएनआइ)

पूर्व राजनयिक संजय वर्मा यूपीएससी सदस्य नियुक्त

नई दिल्ली: पूर्व राजनयिक संजय वर्मा को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का सदस्य नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) अधिकारी वर्मा को गुरुवार को यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वर्मा स्पेन व अंडोरा, इथियोपिया, जिबूती और अफ्रीकी संघ में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। (प्रेट्र)

एआइएमआइएम सांसद जलील पर मुकदमा दर्ज

छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन का नेतृत्व करने के आरोप में आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के सांसद इम्तियाज जलील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दो दिन पहले आयोजित प्रदर्शन में मांग की गई थी कि सरकार आरबीआइ द्वारा लाइसेंस निरस्त की गई आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक व अन्य सात वित्तीय संस्थानों के खाता धारकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाए। (प्रेट्र)

आइएस माड्यूल मामले में आरोपित ने मांगी जमानत

मुंबई: इस्लामिक स्टेट (आइएस) के माड्यूल भंडाफोड़ मामले के आरोपित ने अदालत से बच्चे के जन्म के समय पत्नी के साथ रहने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए छह आरोपितों में से एक जुबैर शेख ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और चार फरवरी को उसका आपरेशन होना है। याचिका में आरोपित ने पत्नी के साथ रहने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है। हालांकि एनआइए ने जमानत देने का विरोध किया। अदालत शुक्रवार को याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। (प्रेट्र)

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, उससे तय होगा एएमयू का भविष्य

एएमयू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में आठ दिनों तक दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनी। सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायाधीश संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पार्डीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, वह एएमयू का भविष्य तय करने वाला होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान माना जाएगा कि

सुप्रीम कोर्ट फाइल

नहीं।

इस मामले में एएमयू ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांच जनवरी 2006 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में एएमयू की अपील सहित कुल आठ अपीलें लंबित हैं। हाई कोर्ट ने उस फैसले में एएमयू में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में मुसलमानों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने को रद कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि एएमयू कभी भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था। इसलिए, पीजी पाठ्यक्रम में मुसलमान छात्रों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने मुस्लिम छात्रों को दिये जाने वाले आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के अजीज बाशा मामले में 1968 में दिए गए फैसले को आधार बनाया था। 1968 के अजीज बाशा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने अजीज बाशा फैसले के बाद एएमयू के कानून में 1981 में संशोधन कर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के प्रविधानों को भी रद कर दिया था।

हाई कोर्ट ने कहा था कि ये संशोधन गलत हैं, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी किया गया है। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिए भेज दिया था। इसके अलावा 1981 में भी अल्पसंख्यक दर्जे का एक मामला सात न्यायाधीशों को भेजा गया था। इसमें अजीज बाशा फैसले का मुद्दा भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ ने नौ जनवरी को मामले पर सुनवाई शुरू की थी और आठ दिन तक दोनों पक्षों की बहस सुनी। बहस के दौरान एएमयू ने अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करते हुए कहा कि एएमयू की स्थापना मुसलमानों ने की थी। एएमयू ने 1968 के अजीज बाशा फैसले पर भी पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। जबकि केंद्र सरकार ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की मांग का विरोध करते हुए दलीलें दी थीं कि न तो एएमयू की स्थापना मुसलमानों द्वारा की गई है और न ही उसका प्रशासन अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित होता है। केंद्र ने कहा था कि एएमयू की स्थापना 1920 में ब्रिटिश कालीन कानून के जरिये हुई थी। उस समय एएमयू ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़कर इंपीरियल कानून के जरिये विश्वविद्यालय बनना स्वीकार किया था।

ईडी की याचिका पर एजेएल और हुड्डा को हाई कोर्ट का नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पीएमएलए के तहत आरोप तय करने की कार्रवाई शुरू करना चाहती है ईडी
- विशेष न्यायाधीश पंचकूला के आदेश को ईडी ने हाई कोर्ट में दी है चुनौती

प्लाट आवंटन मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को ईडी की याचिका पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। ईडी ने इन सभी के खिलाफ आरोप तय करने पर लगी रोक को चुनौती दी है।

इस मामले में 19 अप्रैल, 2022 को पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ईडी ने इस आदेश को विशेष न्यायाधीश, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अदालत में चुनौती दी थी, पर अदालत ने 30 अगस्त, 2023 को उसकी याचिका खारिज कर दी। अब ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी पीएमएलए 2002 के तहत आरोप तय करने की कार्रवाई फिर से शुरू करना चाहती है। सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अरविंद मौदगिल ने तर्क दिया कि मनी लांड्रिंग अलग अपराध है, इसलिए कि इस विषय पर सीबीआइ जांच की कार्रवाई पर रोक है। ऐसे में पीएमएलए मुकदमे में कार्रवाई को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है। सीबीआइ व ईडी की जांच अलग है। चाहे मामला एक विषय पर ही क्यों न हो। हाई कोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर नौ अप्रैल तक इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। ईडी की विशेष अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने की कार्रवाई पर इस आधार पर रोक लगा दी थी कि वर्तमान मामले में जांच अभी भी प्रगति पर है और अपराध की आय का निर्धारण अभी भी लंबित है।

एजेएल को पंचकूला में भूखंड आवंटन से संबंधित मामला 22 दिसंबर, 2016 को सीबीआइ को स्थानांतरित कर दिया गया था और सीबीआइ ने पांच अप्रैल, 2017 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के तत्कालीन अध्यक्ष और वित्तीय आयुक्त टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, मैसर्स एजेएल, तत्कालीन मुख्य प्रशासक हुडा के खिलाफ आइपीसी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआइ ने जांच के बाद एजेएल, कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें मोतीलाल वोरा का निधन हो चुका है।

गुना में मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग उखाड़ कर फेंका

नईदुनिया, गुना

मध्य प्रदेश में गुना जिले के बमोरी तहसील मुख्यालय पर बुधवार देर रात मुक्तिधाम के समीप स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात लोगों ने न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि शिवलिंग को उखाड़कर फेंक दिया। गुरुवार सुबह इस घटना की जानकारी लगने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार बंद कर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों अनवर, बफाती, रिहान, जीशान व रहीश पर शांतिभंग का केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है, पर ग्रामीण मामले में संलग्न सभी आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े रहे।

- ग्रामीणों ने बाजार बंद कर किया चक्का जाम, पुलिस ने पांच आरोपितों को हिरासत में लिया

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम को शयन आरती तक मंदिर में हालात सामान्य थे, लेकिन गुरुवार सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो तोड़फोड़ की जा चुकी थी। मंदिर की स्थिति देखकर आक्रोश की स्थिति बन गई। कुछ ही देर में मंदिर में तोड़फोड़ की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और ग्रामीण मुख्य मार्ग पर एकत्रित हो गए। इसके बाद न केवल बाजार बंद किया गया, बल्कि चक्काजाम भी कर दिया गया। कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल भी बमोरी पहुंचे और ग्रामीणों के साथ धरना-प्रदर्शन में शामिल हो गए। चक्का जाम कर रहे ग्रामीणों और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों की बातचीत के बाद दोपहर करीब तीन बजे ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर मार्ग खोला। उन्होंने प्रशासन को पांच दिनों की मोहलत के साथ चेतावनी दी है कि उक्त अवधि में कार्रवाई नहीं हुई तो जिलेभर में आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने सात दिन का समय मांगा है। ग्रामीणों का कहना था कि वर्ष 2013 में भी मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद जीर्णोद्धार कर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उस समय भी पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।

शिवलिंग उखाड़कर फेंके जाने के विरोध में चक्का जाम करते लोग। नईदुनिया

विशेषज्ञ समिति धामी को आज सौंपेगी समान नागरिक संहिता का मसौदा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराओं का उल्लेख, 2.30 लाख से अधिक सुझाव भी मिले

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में समिति सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंपेगी। इसे शनिवार तीन फरवरी को कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इस ड्राफ्ट को पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ड्राफ्ट में कानूनों को सख्त करने पर जोर दिया गया है। ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराओं का उल्लेख है।

सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। 20 माह में समिति अब इस कार्य को पूरा कर चुकी है। इस अवधि में समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों व समुदायों के साथ 60 से अधिक बैठकों व आनलाइन माध्यम से सुझाव लिए। समिति को 2.30 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। अब समिति समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी भाषा में तैयार कर चुकी है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने के साथ ही 18 से 21 वर्ष के युवाओं के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य की जा सकती है। इसके अलावा सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार, बहु विवाह पर रोक, तलाक, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, स्थानीय व जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों का अनुपालन व निजी स्वतंत्रता संबंधी बिंदुओं को प्रारूप में शामिल करते हुए कानून को सख्त करने पर जोर दिया गया है।

प्रतीकात्मक

मदरसों में रामायण पाठ के समर्थन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने कहा है कि मदरसों में रामायण पाठ व श्रीराम के सम्पूर्ण जीवन के बारे में जानकारी देना अच्छा कदम है। शिक्षित होने के लिए हर जानकारी लेना जरूरी है। कहा, मुशायरों व कवि सम्मेलनों में भी तो हिंदू समाज के बुद्धिजीवी उर्दू व अरबी में शायरी पढ़ते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के अधीन मदरसों में भगवान श्रीराम के बारे में बताया जाएगा। इसी सत्र से मदरसों के पाठ्यक्रम में यह बदलाव किया जाएगा। इस आदेश का कुछ लोगों ने दबी जुबान में विरोध किया। वहीं, मजहर ने कहा, मदरसों में रामायण पाठ पढ़ाने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर किसी को रामायण को समझना चाहिए। देश में कई आचार्य ऐसे भी हैं, जिन्हें कुरान पाक की आयतों की पूरी जानकारी है। इसलिए मैं समझता हूं कि मदरसों में रामायण पढ़ाने में किसी तरह का ऐतराज करना गलत है।

परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है सेना : जनरल पांडे

- पुणे में वांवे सैपर्स वार मेमोरियल सैंटिनरी के कार्यक्रम में हुए शामिल
- वोले-अग्निवीरों को सेना में शामिल किए जाने पर किया जा रहा विचार

पुणे, प्रेट्र : थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि सेना परिवर्तनकारी दौर से गुजर रही है। सेना ने परिचालन तैयारियों को मजबूत करने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है। हमने बदलाव की दिशा में अच्छी प्रगति की है। इस बदलाव के तहत सेना इंजीनियरों की कोर में आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकी समावेशन पर जोर दे रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में इन प्रयासों से परिचालन तैयारियों में वृद्धि होगी और हम युद्ध की चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम होंगे।

वह महाराष्ट्र के पुणे में बांबे सैपर्स वार मेमोरियल सैंटिनरी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बांबे सैपर्स का इतिहास शौर्य, बलिदान और साहस से भरा है। इसने युद्ध क्षेत्र, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में अपनी कार्य कुशलता, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के माध्यम से नाम कमाया है। राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में बांबे सैपर्स की भूमिका अहम है और मुझे विश्वास है कि यह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करता रहेगा और भारतीय सेना का नाम ऊंचा रखेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्निपथ योजना महत्वपूर्ण कदम है। अग्निवीरों को सेना की रेजीमेंटों व अन्य इकाइयों में शामिल करने का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनका चयन स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वचालित प्रणाली के तहत किया जा रहा है।

मनोज पांडे। फाइल फोटो

उचित हिस्सा नहीं मिला तो अलग देश की मांग करेंगे दक्षिण के राज्य : डीके सुरेश

- कांग्रेस सांसद ने कहा, राज्यों को करों का उचित हिस्सा नहीं दे रहा केंद्र
- भाजपा ने कहा, कांग्रेस उत्तर व दक्षिण को विभाजित करना चाहती है

नई दिल्ली, एएनआइ : अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद ने विवादित बयान दिया है। बेंगलुरु ग्रामीण से लोकसभा सांसद डीके सुरेश ने गुरुवार को कहा कि अगर केंद्र ने उनके लिए धन जारी नहीं करने की प्रवृत्ति जारी रखी, तो देश के दक्षिणी राज्य एक अलग देश की मांग उठाएंगे। कांग्रेस सांसद अंतरिम बजट जारी होने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने केंद्र पर दक्षिण भारतीय राज्यों को फंड जारी नहीं करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि केंद्र दक्षिण भारतीय राज्यों को जीएसटी और प्रत्यक्ष करों का उचित हिस्सा नहीं दे रहा है। दक्षिण भारतीय राज्यों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी राज्यों से एकत्र किया गया पैसा उत्तर भारतीय राज्यों को दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एक अलग देश की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डीके सुरेश ने कहा कि केंद्र हमसे चार लाख करोड़ रुपये से अधिक ले रहा है और बदले में हमें जो मिल रहा है वह नगण्य है। हमें इस पर सवाल उठाना होगा।

डीके सुरेश। फाइल फोटो

इस पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि अलग देश की मांग कांग्रेस पार्टी की नीति नहीं रही है। वहीं, डीके सुरेश के भाई और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सांसद दक्षिण भारत का दर्द बयां कर रहे थे। एक संतुलन होना चाहिए। पूरा देश एक है। आप केवल हिंदी बेल्ट को नहीं देख सकते। इस बजट में वित्त का कोई समान वितरण नहीं है। कर्नाटक केंद्र को बहुत अधिक राजस्व दे रहा है। पूरे दक्षिण भारत के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। हमें निराश किया गया है। लेकिन पूरा देश एक है। हम भारतीय हैं। भारत को एकजुट होना चाहिए। क्षेत्रवार कुछ भी मांगने का सवाल ही नहीं उठता।

वहीं, भाजपा नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने डीके सुरेश पर देश को विभाजित करने के लिए चाल चलने का आरोप लगाया। सूर्या ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास फूट डालो और राज करो का रहा है। पार्टी के सांसद अब फिर से चाल चल रहे हैं। वे उत्तर और दक्षिण को विभाजित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ उनके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ों यात्रा निकालते हैं, वहीं दूसरी ओर डीके सुरेश देश को तोड़ने पर तुले हैं। कन्नड़वासी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का एजेंडा लोगों को बांटना है।

कर्नाटक में हनुमान ध्वज हटाने के मामले ने पकड़ा तूल

- कई स्थानों पर हरे झंडे लगाए गए, लोगों ने की इसे हटाने की मांग
- बजरंग दल आज से शुरू कर सकता है हनुमान ध्वज अभियान

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच हनुमान ध्वज हटाने का विवाद अब तूल पकड़ चुका है। इसका असर अब पूरे राज्य में हो रहा है। मांड्या जिले में एक सार्वजनिक स्थान से हनुमान ध्वज हटाए जाने के बाद कई सार्वजनिक स्थानों पर हरे झंडे लगा दिए गए हैं। इस बीच, बजरंग दल ने कहा है कि शुक्रवार से हनुमान ध्वज अभियान शुरू किया जाएगा। इससे पहले विहिप ने घोषणा की थी कि पूरे राज्य में भगवा झंडा अभियान चलाकर सभी घरों पर झंडे फहराए जाएंगे। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मांड्या जिले के केरागोडु गांव में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यह विवाद यहीं से शुरू हुआ था।

भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने भी अधिकारियों से मैसूरु शहर से हरा झंडा हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या आपको मैसूरु शहर के कैलासपुरम में आंबेडकर पार्क के पास हरा झंडा नहीं दिख रहा। आपने एक झंडा हटाकर दूसरे झंडे को यहां क्यों रहने दिया। विवाद बढ़ने के बाद अधिकारियों ने बेंगलुरु में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शिवाजीनगर के चांदनी चौक पर हरा झंडा हटा दिया था और राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। चिक्कबल्लापुर शहर के स्थानीय लोगों ने गुरुवार को लगाए गए हरे झंडे को हटाने की मांग की। उन्होंने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों ने मौके का दौरा कर झंडा हटाने का निर्देश दिया। भाजपा नेताओं ने कोलार शहर के प्रसिद्ध घंटाघर पर स्थापित आधे चांद और सितारे वाली संरचना को हटाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल का कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं विपक्षी दल भाजपा का कहना है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।

तैयारी

एनसीपीसीआर ने शुरू किया परीक्षा पर्व का छठा संस्करण, छठी से 12वीं तक के विद्यार्थी अपलोड कर सकेंगे आडियो-वीडियो

बोर्ड परीक्षार्थियों का तनाव दूर करेगा परीक्षा पर्व

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) पीएम के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रेरित होकर बोर्ड के परीक्षार्थियों का तनाव दूर करने के लिए परीक्षा पर्व आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा से संबंधित तनाव पर काबू पाने में सहायता करना और अभिभावकों व शिक्षकों के दृष्टिकोण को बदलना और परीक्षा परिणाम से पहले उनकी चिंता दूर करना है। इस बार एनसीपीसीआर परीक्षा पर्व का छठा संस्करण मना रहा है।

अभियान में एनसीपीसीआर के इंटरनेट मीडिया अकाउंट और दूरदर्शन के जरिये विशेषज्ञों, मनोविज्ञानियों, प्रेरक वक्ताओं के साथ फेसबुक, एक्स व यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों तक पहुंच के लिए रेडियो स्पाट भी अभियान भी शामिल है।

आयोग की योजना इस कार्यक्रम में अधिकतर विद्यार्थियों को शामिल करने की है, ताकि उनमें सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। एग्जाम वारियर्स विषय पर छात्रों से आडियो-वीडियो संदेश एनसीपीसीआर की वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। वीडियो अपलोड करने का लिंक छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक से 20 फरवरी तक लाइव रहेगा, जो 60 सेकंड के आडियो-वीडियो संदेश अपलोड करेंगे। शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि वीडियो माता-पिता की सहमति से अपलोड किए जाएं। संदेश में विद्यार्थी परीक्षा के दौरान अपने अनुभव व दिनचर्या के बारे में बात कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक

एनसीपीसीआर के अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थी वीडियो की शुरुआत अपना परिचय देते हुए करें, जिसमें वे अपनी उम्र, स्तर व स्कूल का विवरण बताएं। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को ई-प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और चयनित वीडियो को एनसीपीसीआर के इंटरनेट मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। विद्यार्थियों के माता-पिता भी इस विषय पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं।

एनसीपीसीआर ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वे इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। आयोग ने परीक्षा अवधि के दौरान बच्चों द्वारा महसूस किए गए तनाव, चिंता, भय और अन्य सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए टेली काउंसलिंग संवेदना (180012128301) के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक सहायता देने के लिए योग्य और प्रशिक्षित विशेषज्ञ परामर्शदाताओं का नेटवर्क भी बनाया है।

****

भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर व पत्नी को धोखाधड़ी मामले में नहीं मिली राहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भारतपे के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी व संचालन प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर ने उनके विरुद्ध जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, मामले की जांच शुरुआती चरण में है और इस स्तर पर अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालत ने सुनवाई आठ मई तक के लिए स्थगित कर दी।

फिनटेक फर्म भारतपे ने अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन पर 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के कहने पर ग्रोवर दंपती के खिलाफ एलओसी जारी की गई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पुलिस को जांच में कुछ समय लगेगा।

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

दैनिक जागरण
इंग्लिश चुनौती
शुक्रवार 2 फरवरी, 2024 www.jagran.com

मैंने हमेशा जो रूट से कहा कि बतौर कप्तान उन्होंने कम गेंदबाजी की और मैं उन्हें एक गेंदबाज बनाऊंगा और मैंने ऐसा कर भी दिया। रूट की गेंदबाजी का यहां फायदा मिलना निश्चित रूप से बड़ी चीज है। वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।

– बेन स्टोक्स, कप्तान, इंग्लैंड

अंग्रेजों की रणनीति अपना सकती है भारतीय टीम

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज से जडेजा की जगह कुलदीप को मिलेगा मौका, मेहमान टीम में दो बदलाव

नई दिल्ली, जेएनएन : पहला टेस्ट गंवाने के बाद भारत को शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड की बेखौफ 'बैजबाल' शैली का सामना करने के लिए बेहतर रणनीति के साथ उतरना होगा क्योंकि उसके प्रमुख खिलाड़ी इस मैच से बाहर हैं। विशाखापत्तनम में अगर स्पिन की मददगार पिच मिलती है तो भारतीय टीम अंग्रेजों की रणनीति अपना सकती है। चोट के कारण बाहर रवींद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में कुलदीप यादव खेल सकते हैं। अगर भारत जसप्रीत बुमराह के रूप में सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ उतरता है तो वाशिंगटन सुंदर टीम के चौथे स्पिनर हो सकते हैं। वाशिंगटन अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, जिससे बल्लेबाजी को गहराई मिलती है। इंग्लैंड ने पहले मैच में भी चार स्पिनर और एक तेज गेंदबाज के साथ उतरने की रणनीति अपनाई थी और दूसरे मैच में भी उसकी यही रणनीति है।

भारतीय बल्लेबाजों को भी पहले टेस्ट में नए स्पिनर टाम हार्टले ने परेशान किया। दूसरी पारी में सिर्फ रोहित शर्मा आत्मविश्वास से भरे दिखे जबकि शुभमन गिल समेत युवा ब्रिगेड ने निराश किया। गिल को रक्षात्मक खेल का नुकसान उठाना पड़ा। तीसरे टेस्ट में विराट कोहली की वापसी होगा जिससे गिल और श्रेयस अय्यर पर अच्छे प्रदर्शन का काफी दबाव होगा। अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल की जगह रजत पाटीदार इस मैच में खेल सकते हैं। घरेलू क्रिकेट में काफी रन बनाने के बाद आखिरकार सरफराज खान को चयनकर्ताओं ने मौका दिया है और वह पदार्पण को बेताब होंगे।

अपनी धरती पर मजबूत भारत को हैदराबाद में पहले टेस्ट में पराजय झेलनी पड़ी। तीन साल पहले भी भारतीय टीम को इन्हीं हालात से दो चार होना पड़ा था जब चेन्नई में पहले टेस्ट में उसे इंग्लैंड ने हराया था लेकिन वापसी करके भारत ने सीरीज अपने नाम की थी। जो रूट की कप्तानी वाली वह टीम अलग थी और इस बार भारत को वापसी करने के लिए इंग्लैंड की ऐसी टीम को हराना होगा जिसने टेस्ट क्रिकेट खेलने के मानदंड ही बदल दिए हैं। हैदराबाद में पहली पारी में 190 रन से पिछड़ने के बाद उसने आक्रामक खेल की अपनी 'बैजबाल' से वापसी करके 28 रन से मैच जीता। ओली पोप ने स्वीप और रिवर्स स्वीप को ढाल बनाकर भारतीय फिरकी आक्रमण को बखूबी झेला। पोप के आगे भारत का विख्यात स्पिन आक्रमण बौना साबित हो गया। दूसरे टेस्ट में भारत के पास जडेजा नहीं होंगे और 500 टेस्ट विकेट से चार विकेट दूर रविचंद्रन अश्विन को बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

अभ्यास के दौरान राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ● प्रेट्र

लीच बाहर, एंडरसन और बशीर अंतिम एकादश में

इस बीच, इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए गुरुवार को अंतिम एकादश की घोषणा कर दी। जैक लीच की जगह युवा स्पिनर शोएब बशीर खेलेंगे, जो वीजा विवाद के कारण देर से टीम से जुड़ पाए थे। इस दौरे पर टाम हार्टले के बाद शोएब इंग्लैंड की ओर से पदार्पण करेंगे। वहीं सबसे अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन की भी वापसी हुई है। उन्हें मार्क वुड की जगह टीम में सम्मिलित किया गया है।

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), गिल, यशस्वी, श्रेयस अय्यर, केएस भरत, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, रजत पाटीदार, सरफराज खान, वाशिंगटन सुंदर, सौरभ कुमार।

इंग्लैंड एकादश : जैक क्रावले, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जानी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), बेन फोक्स, रेहान अहमद, टाम हार्टले, शोएब बशीर, जेम्स एंडरसन।

4 विकेट लेने के साथ ही अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे कर लेंगे। ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय जबकि नौवें गेंदबाज होंगे

इंग्लैंड से निपटने के लिए स्वीप शाट पर काम किया: भरत

विकेटकीपर केएस भरत ने कहा कि भारतीय खेमे में कोई हड़बड़ाहट नहीं है और टीम ने इंग्लैंड के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए नई योजना बनाई है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर स्वीप शाट लगाना भी शामिल है। भारत ने कहा, भारत में हम इस तरह के ट्रैक पर काफी क्रिकेट खेले हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्वीप, रिवर्स स्वीप या पेडल शाट खेलना नहीं जानते, लेकिन टीम की हालात को देखते हुए उस विशेष दिन हम बल्लेबाज फैसला करते हैं।

रवींद्र जडेजा का तीसरे टेस्ट में खेलना भी संदिग्ध

नई दिल्ली, जेएनएन : हैमस्ट्रिंग के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर भारतीय आलराउंडर रवींद्र जडेजा का तीसरे टेस्ट में खेलना भी संदिग्ध है। सूत्रों की मानें तो जडेजा की चोट को ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। आमतौर पर हैमस्ट्रिंग की चोट चार से आठ सप्ताह में ठीक हो जाती है। ऐसे में अगर वह 23 से 27 फरवरी तक रांची में होने वाले चौथे टेस्ट तक भी ठीक हो जाते हैं तो यह बड़ी बात होगी। हालांकि बीसीसीआइ की ओर से जडेजा के केवल दूसरे टेस्ट से बाहर होने की जानकारी दी गई है।

कोहली से सीखकर बल्लेबाजी की कोशिश करता हूं: रजत

विशाखापत्तनम, प्रेट्र : इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत के लिए पदार्पण की दहलीज पर खड़े मध्यक्रम के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने कहा है कि वह विराट कोहली को देखकर अपनी बल्लेबाजी में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। पाटीदार ने बीसीसीआइ टीवी से कहा कि मैं नेट्स पर कोहली की बल्लेबाजी देखता रहता हूं, विशेषकर उनका फुटवर्क और मूवमेंट। मैं उनसे सीखकर इन चीजों को अपनी बल्लेबाजी में लाने की कोशिश करता हूं। पाटीदार ने कहा कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से उन्हें काफी फायदा हुआ है।

हादसे के बाद पैर गंवाने का डर था: रिषभ पंत

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत ने कहा है कि 13 महीने पहले हुए भयावह कार हादसे के बाद उन्हें अपना दाहिना पैर गंवाने का डर था। पंत ने कहा कि अगर हड्डी के अलावा किसी नस को नुकसान पहुंचा होता तो यह भी संभव था कि वे मेरा पैर शरीर से अलग करना पड़ता। पंत दिसंबर 2022 में दिल्ली से अपने परिवार से मिलने रुड़की जा रहे थे, जब उनकी कार सड़क के बीच डिवाइडर से टकरा गई थी।

पंत ने एक कार्यक्रम में कहा, अगर कोई नस क्षतिग्रस्त होती तो पैर गंवाने का डर था। मैं उस समय डर गया था। मेरा दाहिना घुटना खिसक गया था और मैं काफी दर्द में था। मेरा घुटना 180 डिग्री तक घूम गया था। वहां आसपास कोई था तो मैंने पूछा कि क्या कोई घुटने को वापस जगह पर लाने में मदद कर सकता है। दुर्घटना के बाद रजत और निशु कुमार नामक दो व्यक्तियों ने पंत को कार से बाहर निकालने में सहायता की था। पंत ने कहा कि पहली बार मुझे लगा कि मेरा समय खत्म हो चुका है। क्योंकि मुझे बाहर निकालते ही कार में आग लग गई थी। मैं भाग्यशाली रहा। मैंने एसयूवी ली थी लेकिन दुर्घटना के बाद सेडान लग रही थी। मैं रजत और निशु की वजह से जीवित हूं और मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा।

एक नजर में

भारतीय अंडर-19 टीम की नजरें सेमीफाइनल पर

ब्लोमफोंटेन: शानदार फार्म में चल रही भारतीय टीम शुक्रवार को अंडर-19 विश्व कप के ग्रुप वन के अंतिम सुपर सिक्स मैच में उतरेगी तो नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरने का लक्ष्य होगा। सुपर सिक्स से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। पाक और भारत के छह अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट बेहतर होने से भारत शीर्ष पर है। उदय सहारन की कप्तानी वाली भारतीय टीम अभी तक हारी नहीं है और नेपाल से किसी उलटफेर की उम्मीद भी नहीं है। (प्रेट्र)

डेविस कप मैच को लेकर पाक में उत्साह नहीं

इस्लामाबाद: भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच यहां डेविस कप मैच होना है, लेकिन इस्लामाबाद को देखकर जरा भी अहसास नहीं होता कि यह शहर इस ऐतिहासिक मुकाबले की मेजबानी कर रहा है। यहां एक भी पोस्टर नहीं लगा है जिससे पता चले कि भारतीय टीम 60 साल बाद यहां डेविस कप मुकाबला खेलने आई है। इस्लामाबाद खेल परिसर में भी कोई हलचल नहीं है जहां यह मैच होना है। वहीं, भारतीय उच्चायोग ने भारतीय टीम की अगवानी की। (प्रेट्र)

अवनि संयुक्त चौथे स्थान पर

पटाया: भारत की अवनि प्रशांत पहले दौर में चार अंडर 68 के साथ महिलाओं के एमेच्योर एशिया पैसिफिक गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर चल रही हैं। अवनि ने पहले दौर में छह बर्डी की लेकिन वह दो बोगी भी कर गईं जिससे उनका स्कोर चार अंडर रहा। थाइलैंड की इला गेलिटस्काई और नोवापोर्न सूनत्रीयापास पांच अंडर 67 के स्कोर से शीर्ष पर चल रहे हैं। (प्रेट्र)

पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है बिहार की टीम

रणजी ट्राफी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : दो रणजी टीम उतारने को लेकर उपजे विवाद के बाद बिहार की टीम अब पटरी पर लौटती नजर आ रही है। मौजूदा रणजी सत्र के पहले मैच में मुंबई ने बिहार को पारी और 51 रनों से करारी शिकस्त दी थी। इसी मैच में बिहार की दो टीमें उतर गई थीं और बिहार क्रिकेट संघ (बीसीए) में चल रहा विवाद सामने आया था लेकिन इसके बाद राज्य संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने अपनी टीम को पटरी पर वापस दौड़ाने की भरपूर कोशिश की जिसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है।

उस मैच के बाद बिहार ने छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और केरल से मैच खेले। टीम भले ही अब तक एक भी जीत नहीं दर्ज कर सकी हो, लेकिन बिहार मजबूत टीमों के विरुद्ध तीनों मैच ड्रा कराने में सफल रही। बिहार को अब शुक्रवार से घरेलू मैदान पर आंध्र प्रदेश का सामना करना है। बीसीए में लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन हाल ही में दैनिक जागरण से बात करते हुए राकेश तिवारी ने राज्य संघ में किसी भी विवाद से इन्कार किया था। बिहार टीम के 2023-24 सत्र के घरेलू प्रदर्शन को देखें तो यह साफ नजर आता है कि बीसीए में विवाद का असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा था। सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्राफी में बिहार की टीम ग्रुप बी में थी उसने सात मैच में से सिर्फ एक में जीत दर्ज की थी। विजय हजारे ट्राफी में सात में से टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी थी और ग्रुप सी की तालिका में सबसे नीचे रही थी।

बिहार की रणजी टीम विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। रणजी ट्राफी के पहले मैच में मुंबई से मिली करारी हार के बाद टीम ने अगले तीन मैच ड्रा खेले। हम भविष्य की टीम बनाने की कोशिश में जुटे हैं।

राकेश तिवारी, अध्यक्ष, बिहार क्रिकेट संघ

धर्मशाला स्टेडियम में बर्फ से ढके मैदान की यह तस्वीर वेंकटेश अय्यर ने साझा की। यहां शुक्रवार से हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच रणजी मैच खेला जाना है ●

अपराजेय रहना चाहेगा उप्र

नई दिल्ली, जेएनएन : नीतीश राणा की कप्तानी वाली उत्तर प्रदेश की टीम को भले ही रणजी ट्राफी के मौजूदा सत्र में चार मैचों में एक जीत मिली है, लेकिन टीम टूर्नामेंट में अबतक अजेय रही है क्योंकि उसने केरल, बंगाल और बिहार के विरुद्ध ड्रा खेला है। उत्तर प्रदेश का सामना शुक्रवार से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में असम से होगा और टीम की नजरें अविजित लय को बरकरार रखने पर टिकी रहेंगी।

घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी दिल्ली: उत्तराखंड के विरुद्ध रोमांचक मैच में जीत दर्ज करने वाली दिल्ली का सामना अब शुक्रवार से बड़ौदा के साथ होगा। दिल्ली को घरेलू मैदान पर अपने पिछले मैच में पुडुचेरी ने हराया था और टीम इस कड़वी याद को भुलाकर जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी।

ओलिंपिक वर्ष में खेल मंत्रालय की राशि में 45 करोड़ की बढ़ोतरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : खेल मंत्रालय को गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में 3442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जिसमें पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया। पिछले बजट में 3396.96 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे।

इस 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान देश का मुख्य ध्यान पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले ओलिंपिक खेलों पर लगा होगा। खेलों इंडिया को पिछले बजट की तुलना में 20 करोड़ रुपये का इजाफा कर 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। राष्ट्रीय शिविर आयोजित करने वाले, खिलाड़ियों को बुनियादी ढांचा और उपकरण मुहैया कराने वाले और कोचों की नियुक्ति के अलावा अन्य काम करने वाले साई के बजट में पिछले साल की तुलना में 26.83 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई जिससे अब यह 795.77 करोड़ रुपये का होगा।

एनएसएफ के 2023-24 के 325 करोड़ रुपये के बजट में इस बार 15 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। नाडा को इस अंतरिम बजट में 22.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए जो 2023-24 वित्तीय वर्ष में 21.73 करोड़ रुपये का था।

अंतिम गेंद पर जीती कैपिटल्स

आइएलटी-20

नई दिल्ली, जेएनएन : दुबई कैपिटल्स ने गुरुवार को रोमांचक मुकाबले में डेजर्ट वाइपर्स को चार विकेट से हराकर आइएलटी-20 में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। दुबई को अंतिम ओवर में केवल चार रन बनाने थे और अंतिम गेंद पर जेसन होल्डर ने टीम को जीत दिला दी। वाइपर्स ने दुबई के सामने 170 रन का लक्ष्य रखा था। दुबई के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज (4) और कप्तान डेविड वार्नर फिर (4) विफल रहे। लेकिन बेन डंक (59) और रोवमैन पावेल (40) ने अच्छी बल्लेबाजी की। इससे पहले रोहन मुस्तफा (50) और एलेक्स हेल्स (49) की आरंभिक जोड़ी के बाद एडम होस (35) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर डेजर्ट वाइपर्स ने 169 रन बनाए थे।

जी फाइव व एंड पिक्चर्स पर प्रसारित मुकाबले में दुबई ने टास जीतकर वाइपर्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। मुस्तफा और हेल्स ने वाइपर्स को तेज शुरुआत दिलाई और पावरप्ले के छह ओवर में 64 रन जोड़ डाले थे।

टीम को पहला झटका अकीफ रजा ने दिया, जिन्होंने मुस्तफा को अर्धशतक पूरा करने के बाद ही पवेलियन भेज दिया। हेल्स भी कुछ देर बाद जेसन होल्डर का शिकार बने। इसके बाद वाइपर्स की पारी लड़खड़ा गई और उसने नौ रन के भीतर तीन विकेट गंवा दिए। अंत में होस ने केवल 17 गेंदों में 35 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में तीन छक्के और दो चौके जड़े।

त्रीसा-गायत्री की जोड़ी थाइलैंड मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में

बैंकाक, प्रेट्र : त्रीशा जाली और गायत्री गोपीचंद की छठी वरीय भारतीय जोड़ी ने गुरुवार को यहां थाइलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत अपने से कम रैंकिंग वाले हमवतन मिथुन मंजूनाथ के विरुद्ध हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए। महिला सिंगल्स में अस्मिता चालिहा भी अंतिम आठ में जगह बनाने में सफल रहीं।

त्रीशा और गायत्री ने प्री क्वार्टर फाइनल में तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की हमवतन भारतीय जोड़ी को सीधे गेम में 21-15, 24-22 से हराया।

मेसी का सामना नहीं कर सकेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो

खेल डायरी

रियाद, एपी : क्रिस्टियानो रोनाल्डो चोट के कारण लियोन मेसी के विरुद्ध बहुचर्चित प्रदर्शनी फुटबाल मैच नहीं खेल सकेंगे। रोनाल्डो के क्लब अल नस्र और लियोन मेसी के इंटर मियामी के बीच यहां मुकाबला होना है।

अल नासर के कोच लुईस कास्ट्रो ने कहा, 'रोनाल्डो अभी पूरी तरह से फिट नहीं है। उम्मीद है कि वह अगले कुछ दिन में फिट हो जाएंगे। वह इंटर मियामी के विरुद्ध नहीं खेल सकेंगे।' मेसी और रोनाल्डो की प्रतिद्वंद्विता स्पेन में बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड के लिए खेलने के दिनों से चली आ रही है। दोनों मिलकर पिछले 15 में से 13 बैलोन डिओर पुरस्कार जीत चुके हैं।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ● फाइल फोटो, एपी

लियोन मेसी ● फाइल फोटो, एपी

घरेलू मैचों में भारतीय हाकी टीम की कप्तानी करेंगे हरमनप्रीत

नई दिल्ली, प्रेट्र : अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाले एफआइएच प्रो लीग के मैचों में भारतीय पुरुष हाकी टीम के कप्तान होंगे। मिडफील्डर हार्दिक सिंह उपकप्तान होंगे। हाकी इंडिया ने दोहरे चरण के मुकाबलों के लिए गुरुवार को 24 सदस्यीय टीम का एलान किया। भुवनेश्वर चरण 10 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक चलेगा, जबकि राउरकेला चरण 19 से 25 फरवरी तक होगा। भारतीय टीम आयरलैंड, नीदरलैंड्स, स्पेन और आस्ट्रेलिया से दो-दो बार खेलेगी। पहला मैच 10 फरवरी को स्पेन से होगा। भारतीय टीम में स्ट्राइकर बाबी धामी और गोलकीपर पवन नहीं हैं जो द. अफ्रीका दौरे पर टीम में शामिल थे।

भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे सुमित नागल

चेन्नई, प्रेट्र : हाल में ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में वरीय खिलाड़ी को पराजित करने वाले पहले भारतीय बने सुमित नागल रविवार से शुरू होने वाले चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 100 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। नागल ने पिछले महीने आस्ट्रेलियन ओपन में कजाखस्तान के 31वें वरीय और विश्व रैंकिंग में 27वें स्थान पर काबिज एलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। अभी उनकी विश्व रैंकिंग 121 है। रामकुमार रामनाथन और मुकुंद शशिकुमार पुरुष सिंगल्स में अन्य भारतीय खिलाड़ी होंगे जिन्हें मुख्य ड्रा में वाइल्डकार्ड दिया गया है।

राष्ट्रीय फलक

केन-बेतवा परियोजना का जून तक शुरू हो सकेगा काम

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- मप्र, उप्र व केंद्र सरकार के अफसरों ने परियोजना में आ रही बाधाओं पर की चर्चा, अगले माह होगा टेंडर
- टेंडर की शर्तों को लेकर 11 कंपनियों ने दिए सुझाव, अब केंद्र सरकार करेगी विचार

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम अब जून तक ही शुरू हो सकेगा। परियोजना से संबंधित भोपाल स्थित कार्यालय में गुरुवार को हुई बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने परियोजना शुरू करने में आ रही बाधाओं को लेकर चर्चा की। इच्छुक 11 कंपनियों द्वारा दिए गए सुझावों और आपत्तियों को भी सुना गया। इनके समाधान के लिए एक बार फिर भोपाल में ही अधिकारी बैठक करेंगे।

कंपनियों की प्रमुख आपत्ति यह है कि टेंडर की शर्तों में निर्माण कार्य के लिए हाईवे शब्द का उपयोग किया गया है। उनकी चिंता यह है कि ऐसे में क्या छोटी सड़कें मान्य होंगी या नहीं। इसके अलावा निर्माण सामग्री की रायल्टी या जीएसटी लागत बढ़ती है तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी या नहीं। वहीं, वन विभाग को भूमि हस्तांतरित नहीं होने के कारण भी परियोजना प्रभावित हो रही है। इन सभी आपत्तियों को अब जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर समाधान निकाला जाएगा। बैठक में तय किया गया है कि दौधन बांध निर्माण के लिए पांच मार्च तक टेंडर डाले जा सकेंगे। इसके बाद टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को प्री-क्वालिफाई किया जाएगा। कंपनियों का कार्य अनुभव और समस्त दस्तावेज के परीक्षण के बाद टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जून तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें, अब तक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड, दिलीप बिल्डकान, एसटीएन सहित 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

इसी माह शिलान्यास की तैयारी: केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करना चाहती है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी कह चुके है कि परियोजना का भूमिपूजन फरवरी में किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों हो सकता है।

ये जिले होंगे लाभान्वित

- **मध्य प्रदेश:** छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन।
- **उत्तर प्रदेश:** महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर।

केन बेतवा परियोजना। फाइल

परियोजना एक नजर में

लागत: 44,605 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार देगी: 90 प्रतिशत राशि

राज्य सरकारें देंगी: 5-5 प्रतिशत राशि

केन-बेसिन से उत्तर प्रदेश में सिंचाई: 2.27 लाख हेक्टेयर

केन-बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई: 4.47 लाख हेक्टेयर

बेतवा बेसिन से मध्य प्रदेश में सिंचाई: 2.06 लाख हेक्टेयर

मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगी: बिजली

कर्नाटक में एक व्यक्ति ने पत्नी को 12 साल तक रखा नजरबंद

बेंगलुरु, आइएएनएस : कर्नाटक में मैसूर जिले के हिरेगे गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके चरित्र के संदेह में 12 साल तक घर में नजरबंद रखा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार रात घर पर छापा मारा और पीड़िता सुमा को बचाया। आरोपित सन्नालैया को गिरफ्तार कर लिया। सुमा आरोपित की तीसरी पत्नी है। शादी के दिन से ही वह उस पर शक कर रहा था।

शादी के पहले सप्ताह में ही उसने पत्नी को घर के एक कमरे में बंद कर दिया। उसे घर के बाहर स्थित शौचालय का उपयोग करने से भी मना किया था। आरोपित ने इसके लिए कमरे के अंदर बाल्टी रखी थी और उसे खुद ही डिस्पोज करता था। इससे आहत पीड़िता के एक रिश्तेदार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। आरोपी से पीड़िता के दो बच्चे हैं, जिन्हें अब उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया है। सुमा ने बताया कि वह अकारण ही मुझे थप्पड़ मारता था। देर रात घर आने तक वह बच्चों को मेरे साथ नहीं रहने देता था। मुझे उन्हें छोटी खिड़की से खाना देना पड़ता था। पुलिस ने कहा, मामले की जांच चल रही है।

महिला पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में विधायक को गिरफ्तारी से राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए उससे मारपीट करने के मामले में ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष जयनारायण मिश्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है।

जस्टिस ऋषिकेश राय व जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने ओडिशा सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि इस दौरान याचिकाकर्ता को उपरोक्त मामले के संबंध में गिरफ्तारी से राहत दी जाती है। मिश्रा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक हैं और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उन्होंने पिछले लगभग एक साल के दौरान अपने सामान्य कर्तव्यों का पालन किया है और पिछले साल 15 फरवरी की घटना के संबंध में पुलिस को कभी भी उन्हें समन करने का कोई मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, उड़ीसा हाई कोर्ट को याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जमानत पर विचार करना चाहिए था क्योंकि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी।

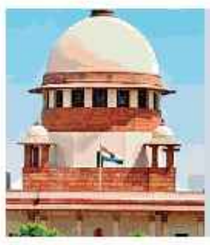

शीर्ष न्यायालय ने ओडिशा सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब

- **महिला अधिकारी ने कहा, विधायक ने घूस का आरोप लगाते हुए धक्का दिया**

सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट के 23 नवंबर 2023 के आदेश के खिलाफ मिश्रा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मामले में अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

भाजपा विधायक ने आरोप को खारिज करते हुए दावा किया था कि धनुपाली की थाना प्रभारी निरीक्षक अनीता प्रधान ने उन्हें धक्का दिया था। वहीं, महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि विधायक ने मुझ पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया और मुझे डकैत कहा। जब मैंने पूछा कि वह ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया।

****

4,666 सूचीबद्ध स्वदेशी उपकरणों में से 2,920 का निर्माण हो चुका है। रक्षा उत्पादन में हर साल जारी किए जाते हैं 40 से 50 लाइसेंस। फिक्की द्वारा आयोजित रक्षा सम्मेलन में रक्षा उत्पादन विभाग के निदेशक अमित सतीजा ने दी जानकारी।

न्यूज गैलरी

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू, गुलजार-जडेजा ने रखे विचार

जयपुर : साहित्य का महाकुंभ पांच दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) गुरुवार से शुरू हो गया। पहले दिन की शुरुआत शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली के कार्यक्रम राग भैरवी से हुई। इसके बाद मीरा और कबीर के भजन ने माहौल भक्तिमय बना दिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद जाने-माने गीतकार गुलजार ने "बाल-ओ-पार : द बीटिंग हार्ट आफ पोएट्री" सत्र में पवन के. वर्मा और रक्षंदा जलील से बातचीत की। इस दौरान गुलजार की नई किताब "बाल ओ पार" पर चर्चा हुई। गुलजार ने कहा कि मेरी यह किताब पढ़ने के अलावा व्यायाम करने के भी काम आएगी, क्योंकि इसका वजन काफी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजय जडेजा व आरबीआइ के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी विचार रखे। (जासं)

गुलजार। प्रेट्र

गुरु मां आशुतोषाम्बरी का शव सुरक्षित रखने के लिए याचिका

लखनऊ : सीतापुर रोड छठा मील में आनंद आश्रम की मुख्य संस्थापिका व गुरु मां आशुतोषाम्बरी ने 28 जनवरी की सुबह समाधि ले ली। आश्रम ने उनके शव को सुरक्षित रखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की है। आश्रम के प्रवक्ता बाबा महादेव का दावा है कि गुरु मां की समाधि लेने का मुख्य उद्देश्य पंजाब के लुधियाना में करीब दस वर्ष पहले समाधि लेने वाले आशुतोष महाराज को उठाना और विश्व में शांति व कल्याण की स्थापना है। सभी को बताया था कि समाधि में जाने के बाद उनके शरीर का ख्याल कैसे रखना है। (जासं)

डीआरडीओ ने कक्षा में लांच किया ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम

नई दिल्ली : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पीएसएलवी सी-58 राकेट से लांच किए गए पेलोड पर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम को कक्षा में सफलतापूर्वक लांच किया है। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना के तहत इसे बेंगलुरु के स्टार्ट-अप बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। इस नवोन्मेषी तकनीक के तहत कक्षा के लिए पर्यावरण-अनुकूल प्रोपल्शन सिस्टम तैयार की गई है। जबकि पारंपरिक राकेट ईंधन (प्रोपल्शन सिस्टम) अत्यधिक जहरीला और कैंसरजन्य रसायन होता है। इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आइएसटीआरएसी), बेंगलुरु में पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपेरिमेंटल माड्यूल (पीओईएम) से टेलीमेट्री डाटा को वैलिडेट किया गया है। (आइएएनएस)

अधिकारियों ने भाग लिया। (प्रेट्र)

फेमा के तहत इंडिया सीमेंट्स के कार्यालयों पर ईडी की छापेमारी

चेन्नई : ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रविधानों के उल्लंघन की जांच के तहत सीमेंट बनाने वाली कंपनी इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के कार्यालयों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि चेन्नई में कंपनी के दो कार्यालय परिसर और दिल्ली में एक परिसर में बुधवार को छापेमारी शुरू की। कंपनी ने कहा कि वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, जांच इंडियन सीमेंट्स की सहयोगी कंपनी इंडिया सीमेंट्स कैपिटल लिमिटेड (आइसीसीएल) के मामलों और लगभग 550 करोड़ रुपये विदेश भेजे जाने से संबंधित है। (प्रेट्र)

पौने चार करोड़ रुपये के नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार

महासमुंद : छत्तीसगढ़ में सरायपाली पुलिस ने नकली नोटों की बड़े खेप पकड़ी है। साड़ी परिवहन की आड़ में पिकअप वाहन में ले जा रहे तीन करोड़, 80 लाख रुपये के नकली नोटों को पुलिस ने जब्त किया है। वाहन में कुल 760 बंडल में 500-500 रुपये के नकली नोट मिले। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजेश कुकरेजा ने बताया कि आरोपित वाहन चालक अरुण सिदार को सारंगढ़ से एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके साड़ियों को रायपुर ले जाने के लिए कहा था। उक्त अज्ञात व्यक्ति ने उससे यह कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे-पीछे मोटर साइकिल से चलूंगा। पुलिस का मानना है कि उक्त अज्ञात व्यक्ति ही नकली नोटों का सूत्रधार हो सकता है। (नईदुनिया)

सीजेआइ ने सुप्रीम कोर्ट में पुस्तकालय का किया उद्घाटन

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर में सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीजेआइ के अतिरिक्त शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। अधिकारी ने बताया कि पुस्तकालय में पुस्तकों को जारी करने और लौटाने के लिए अत्याधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक से जोड़ा जाएगा। (प्रेट्र)

बारिश ने दी राहत तो ओलावृष्टि ने फसलों को पहुंचाया नुकसान

जागरण टीम, नई दिल्ली

- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में दूसरे दिन भी वर्षा
- पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ हुई बर्फबारी
- उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आज और कल बारिश होने का अनुमान, ठिठुरन बढ़ी

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में ताजे हिमपात के बाद बर्फ की सफेद मोटी चादर बिछ गई है। इस दौरान हिमाच्छादित ट्रैक से गुरुवार को गुजरती एक ट्रेन। एएनआइ

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार दूसरे दिन भी वर्षा हुई। इससे सर्दी का सितम तो बढ़ा, लेकिन गेहूं की फसल के लिए वर्षा का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली है। अलबत्ता, पंजाब और हरियाणा में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान हुआ है। पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी हुई। इससे जनजीवन तो प्रभावित हुआ, मगर पर्यटन को अब पंख लगेंगे। बर्फबारी से सेब उत्पादक खुश हैं। वर्षा से हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कुछ राज्यों में शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश हो सकती है।

दिल्ली में 24 घंटे की वर्षा में दो माह की भरपाई : दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे की वर्षा ने दिसंबर-जनवरी महीनों का 'सूखा' खत्म कर दिया है। बुधवार से लेकर गुरुवार शाम साढ़े पांच बजे तक 27.1 मिमी वर्षा हुई है। दिसंबर की सामान्य वर्षा 8.1 मिमी, जबकि जनवरी की 19.5 मिमी है, लेकिन इस बार दोनों माह सूखे रहे थे। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार सुबह घना कोहरा होगा। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

उत्तराखंड में पर्यटकों, किसानों व बागवानों के चेहरे खिले : उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी व वर्षा होने से पर्यटकों, किसानों, बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। पूरे शीतकाल में पहली बार इस तरह बर्फबारी व वर्षा हुई है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चायना पीक में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। मसूरी में सुबह ओलावृष्टि और दोपहर बाद हल्का हिमपात हुआ। बर्फबारी से चार धाम समेत हिमालय की चोटियां चांदी की तरह चमक उठीं। केदारनाथ धाम में दो फीट से अधिक बर्फ पड़ी। बर्फबारी से बदरीनाथ राजमार्ग हनुमानचट्टी के पास बाधित हो गया है, जबकि उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग गंगनानी से आगे अवरुद्ध हो गया। उधर, लुधियाना के जिला कृषि अधिकारी नरिंदर सिंह बेनीपाल का कहना है बर्षा गेहूं की फसल के लिए अच्छी है लेकिन ओले से नुकसान है। सरसों और आलू की फसल प्रभावित हो सकती है।

सड़क मार्ग बंद लेकिन बर्फ से ढकी वादियों में रेल परिचालन जारी

भारी बर्फबारी व भूस्खलन से इस समय कश्मीर को जोड़ने वाले तीनों सड़क संपर्क मार्ग जम्मू-श्रीनगर हाईवे, मुगल रोड व सिंथनटाप मार्ग बंद हैं। बावजूद इसके कश्मीर में रेल परिचालन जारी है। कश्मीर के बारामुला से ट्रेन निरंतर यात्रियों को लेकर श्रीनगर व बड़गाम होते हुए जम्मू संभाग के बनिहाल तल चल रही है। इस बीच, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि भारी बर्फबारी के बावजूद रेलवे ने अपना परिचालन जारी रखा है, जो रेल मंत्रालय के समर्पण को दर्शाता है।

देश का कश्मीर से सड़क संपर्क कटा

जम्मू-कश्मीर में पहाड़ों के साथ श्रीनगर, कटड़ा में माता वैष्णो देवी के भवन, भैरो घाटी व पत्नीटाप समेत कई हिस्सों में इस मौसम का पहला हिमपात हुआ। इससे लोगों के चेहरे खिल गए, पर यह मौसम परेशानी का भी सबब बना। रामबन जिले में भूस्खलन व बनिहाल में बर्फबारी से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। इससे देश का कश्मीर से सड़क संपर्क कट गया। जम्मू से श्रीनगर तक हाईवे पर जगह-जगह वाहनों को रोके जाने से लंबी कतारें लग गईं। जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी देते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले तीन दिन तक बर्फबारी का क्रम बना रह सकता है।

'बेनामी संपत्ति हड़पना चाहते थे हेमंत'

ईडी ने कोर्ट को दी जानकारी, एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

ईडी ने मांगी 10 दिनों की रिमांड, आज अदालत करेगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची

ईडी द्वारा गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को रांची में कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। प्रेट्र

जमीन घोटाला मामले में बुधवार को गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गुरुवार को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। ईडी ने कोर्ट में रिमांड आवेदन देकर हेमंत से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड देने का आग्रह किया। अदालत ने फिलहाल हेमंत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिमांड आवेदन पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत रिमांड आवेदन में बताया है कि रांची के बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के जरिये हेमंत बेनामी संपत्ति हड़पने की कोशिश में थे। इसके लिए वह जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी करवा रहे थे। जमीन घोटाले में भानु प्रताप के ठिकाने से बरामद दस्तावेजों के जांच के क्रम में इसकी पुष्टि हुई है। जमीन हस्तांतरण मामले में ईडी ने 14 अप्रैल 2023 को भानु को छह अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने जालसाजी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला और मुख्य सचिव को अवगत कराया। इसी के बाद सदर थाने में एक जून 2023 को भानु के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

मोबाइल से मिले सुबूत : ईडी ने कोर्ट को बताया है कि राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध तरीके से जमीन अधिग्रहण व कब्जे में सक्रिय था। उनमें हेमंत भी शामिल थे, इसकी जानकारी भानु के मोबाइल से बरामद दस्तावेज में मिली। उक्त मोबाइल से नकदी लेन-देन से संबंधित अधिकतर चैट व सूचनाओं में जमीन का जिक्र था। इसके अतिरिक्त हेमंत के माध्यम से अवैध तरीके से हासिल की गई जमीन की सूची से संबंधित एक फोटो भी मिला। उक्त जमीन 8.5 एकड़ है। छापेमारी में भानु ने सीएमओ के निर्देश पर अंचलाधिकारी के आदेश के बाद उक्त जमीन का भौतिक सत्यापन भी किया था। ईडी ने भानु के आवास में छापेमारी में बरामद 17 सेल डीड के बारे में भी बताया। इनमें ज्यादातर में फर्जीवाड़ा किया गया था। यह सभी हेमंत से संबंधित है।

हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज : सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन कर दिया है।

जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की पीठ शुक्रवार सुबह 10.30 बजे सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में झामुमो नेता को गिरफ्तार किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार रात गिरफ्तार किए गए सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सबसे पहले हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि बाद में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सोरेन की गिरफ्तारी पर भाजपा ने कसा तंज, कांग्रेस बोली- संघवाद पर आघात

नई दिल्ली, प्रेट्र : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए भाजपा ने बुधवार को इसे विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के भ्रष्टाचार में जुड़ी एक और महान उपलब्धि बताया। वहीं, कांग्रेस ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल करके सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना संघवाद पर आघात है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'झारखंड से विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए में भ्रष्टाचार की एक और महान उपलब्धि जुड़ गई है।' पूनावाला ने कहा, 'एक वक्त था जब केजरीवाल लालू, सोरेन, सोनिया को गिरफ्तार करने की मांग करते थे। इन दिनों वह इनका बचाव करते हैं क्योंकि वह खुद भी शराब घोटाले के साजिशकर्ता हैं।'

पानी की टंकी में मिले शिवलिंग का आधार तलगृह में होने का दावा

- एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिला था शिवलिंग
- पानी की टंकी के नीचे तलगृह को बंद किया गया है दीवारों से

जागरण संवाददाता, वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर की पानी टंकी में मिले शिवलिंग का आधार तलगृह (तहखाना) में होने का दावा मंदिर पक्ष करता है। उस क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) सर्वे नहीं हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है। इसके नीचे तलगृह में मौजूद हिस्से को भी दीवारों से बंद किया गया है। पानी की टंकी के सर्वे को लेकर मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की वादी राखी सिंह ने हाई कोर्ट ने अपील दाखिल की है। वहीं, शिवलिंग की वैज्ञानिक विधि से जांच के लिए वादी महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है।

मंदिर पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी व सुभाष नंदन चतुर्वेदी के अनुसार, श्रीकाशी विश्वनाथ धाम स्थित नंदी के ठीक सामने लोहे की बैरिकेडिंग के अंदर 33 गुणे 33 फीट की पानी की टंकी है। इसकी दूरी नंदी जी से 83 फीट है। सभी कोनों से साढ़े सात फीट की दूरी पर कुएं की जगतनुमा आकृति है। एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान इसके ही बीच में शिवलिंग मिला था। ऊंचाई ढाई फीट व बेस पर चार फीट व्यास की गोलाकार काले पत्थर की आकृति है। इसके नीचे जमीन तक पहुंचना संभव नहीं है। तलगृहों के ऊपर फर्श की सतह पर मौजूद पानी की टंकी तक नीचे से जाना संभव नहीं है। नीचे से उस हिस्से को दीवारों से घेर दिया गया है। पूरी संभावना है कि पानी की टंकी में नजर आने वाले शिवलिंग का आधार नीचे ही मौजूद है, जिसे दीवारों से घेर दिया गया है। एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान इस दीवार से पानी टपकता नजर आया था। ज्ञानवापी के तलगृह के ऊपरी सतह पर मौजूद पानी की टंकी में मिला शिवलिंग काफी विशाल रहा होगा। इसका आधार तलगृह में ही मौजूद है जिसे दीवारों से घेरा गया है।

ज्ञानवापी परिसर। फाइल

ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने की सलाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष से वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा, जिसमें व्यासजी के तहखाने में हिंदू पुजारी द्वारा नियमित पूजा-अर्चना की अनुमति दी गई है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा है। अपने आवेदन में वकील निजाम पाशा और फुजैल अहमद अय्यूबी ने कहा कि अदालत के आदेश की आड़ में स्थानीय प्रशासन ने "जल्दबाजी" में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और अब वह मस्जिद के दक्षिणी हिस्से पर स्थित ग्रिलों को काटने की प्रक्रिया में है। मस्जिद पक्ष ने अपने आवेदन में कहा कि प्रशासन के पास रात के अंधेरे में इस कार्य को जल्दबाजी में करने का कोई कारण नहीं है।

मस्जिद पक्ष ने तलगृह में पूजा-अर्चना के आदेश पर रोक की मांग की

विधि संवाददाता, वाराणसी : ज्ञानवापी तलगृह (तहखाना) में पूजा-अर्चना कराने के जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। अदालत ने इस पर मंदिर पक्ष से आपत्ति मांगी है और सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तारीख तय की है। गुरुवार को ही मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर जिला जज के आदेश को चुनौती दी है। दूसरी ओर, मंदिर पक्ष से शैलेंद्र पाठक ने भी हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल किया और याचिका पर सुनवाई का अवसर देने की मांग की। मस्जिद पक्ष के वकील रईस अहमद ने प्रभारी जिला जज के यहां प्रार्थना देते हुए दलील दी है कि जिला जज के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की जानी है। जिला जज के आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने और पुनरीक्षण याचिका तैयार करने में समय लगेगा। ऐसी स्थिति में जिला जज आदेश के क्रियान्वयन को 15 दिन तक स्थगित किया जाना आवश्यक है। इस पर अदालत ने मुकदमे में वादी शैलेंद्र पाठक से आपत्ति मांगी है। बता दें कि बुधवार को ही ज्ञानवापी परिसर के गर्भगृह में व्यास परिवार को पूजा-अर्चना करने की अनुमति मिली है। इस पर लंबे समय से मामला चल रहा था।

शिष्या से दुष्कर्म के मुकदमे में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद बरी

जासं, शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को शिष्या से दुष्कर्म के मुकदमे में दोषमुक्त कर दिया गया है। गुरुवार को एमपी-एमएलए न्यायालय ने उन्हें आरोप से बरी करने का निर्णय सुनाया। विदित हो कि चिन्मयानंद के विरुद्ध 30 नवंबर, 2011 को चौक कोतवाली में प्राथमिकी हुई थी। इसमें उनकी शिष्या ने आरोप लगाया था कि मुमुक्ष आश्रम में बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म किया गया। चिन्मयानंद के अधिवक्ता फिरोज खां ने बताया कि प्रकरण में छह गवाह प्रस्तुत किए गए। षड्यंत्र के तहत शिष्या ने झूठे आरोप लगाए थे। अपर सत्र न्यायाधीश एहसान हुसैन ने उन्हें दोषमुक्त कर आरोप से बरी कर दिया है। इस प्रकरण में पूर्व में प्रदेश सरकार की ओर से भी मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने आपत्ति जताते हुए अर्जी दी थी, जिसके बाद एमपी-एमएलए न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था।

जिला जज का फैसला, अब्दुल्ला आजम का एक जनवरी, 1993 को हुआ जन्म

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज ने की सुनवाई, भेजी रिपोर्ट
- छजलैट प्रकरण में सजा होने पर अब्दुल्ला ने दाखिल की है अपील

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

अदालत ने सपा महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि का निर्धारण कर दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनका जन्म एक जनवरी, 1993 को हुआ था। हालांकि, इस फैसले से उनके जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 होने के दावे को भी सही नहीं माना गया है। अब्दुल्ला ने छजलैट प्रकरण में दो साल की सजा होने पर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने खुद को नाबालिग बताकर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

आजम खां और अब्दुल्ला समेत अन्य सपा नेताओं ने दो जनवरी, 2008 को छजलैट क्षेत्र में पुलिस के रोकने पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में 13 फरवरी, 2023 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के आधार पर अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने घटना के समय स्वयं को नाबालिग बताते हुए आदेश को गलत बताया था। उनका कहना था कि इस मामले में अवर न्यायालय को सजा देने का अधिकार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुरादाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अजय कुमार द्वितीय को अब्दुल्ला आजम की उम्र का निर्धारण कर रिपोर्ट तलब की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी, 1993 मानी है। अब्दुल्ला की ओर से कोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 होने का भी दावा किया गया था।

झारखंड में शिक्षक ने अपने बदले किराये पर रखा टीचर

मिथिलेश पाठक, टाटीझरिया (हजारीबाग) : अब तक बिहार के सरकारी स्कूलों से अजब-गजब किस्से सामने आते रहे हैं। मगर इस बार झारखंड से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक शिक्षक की कारगुजारी से क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर धब्बा लगा है। यह मामला टाटीझरिया प्रखंड में नव प्राथमिक विद्यालय सिमराढाब का है। यहां एक शिक्षक खुद गैरहाजिर रहता था और अपने बदले में किराये पर एक शिक्षिका को रख लिया था। विद्यालय के प्रभारी शिक्षक मोहन प्रसाद ने बताया कि यहां के शिक्षक राजकुमार राम शराब पीने के आदी हैं। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के नाम पर उन्होंने एक शिक्षिका रेखा कुमारी को किराये पर रख लिया है। अपना वेतन पूरा लेने वाला यह शिक्षक उसके बदले में पढ़ाने वाली शिक्षिका को प्रति माह 3500 रुपये भुगतान कर रहा था। शिक्षा अधीक्षक संतोष गुप्ता ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है।

कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने पीएम को दिया शिलान्यास समारोह का निमंत्रण

- प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण के लिए जताया आभार
- 19 फरवरी को होना है श्री कल्कि धाम का शिलान्यास

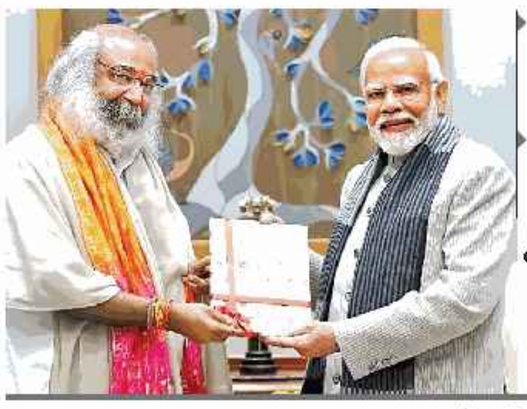
पीएम नरेन्द्र मोदी से मिलकर शिलान्यास का निमंत्रण पत्र सौंपते कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। सौजन्य : स्वयं

जागरण संवाददाता, संभल

अपने ही पार्टी के नेताओं को नसीहत देने वाले कल्कि पीठाधीश्वर व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर उन्हें श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण पत्र सौंपा। शिलान्यास 19 फरवरी को होना है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पीएम से मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि 19 फरवरी को आयोजित समारोह में पीएम मोदी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए आभार।

ईडी के सामने पेश हुए राकांपा विधायक रोहित पवार

राज्य ब्यूरो, मुंबई : राकांपा संस्थापक शरद पवार के पोते रोहित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले की मनी लांड्रिंग जांच के मामले में गुरुवार को ईडी के सामने पेश हुए। इससे पहले 24 जनवरी को भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी।

38 वर्षीय विधायक रोहित पवार गुरुवार को दोपहर एक बजे दक्षिण मुंबई के बेलार्ड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। उनके परिवार के सदस्य ईडी कार्यालय तक उनके साथ गए। पिछली बार जब रोहित ईडी कार्यालय गए थे तो राकांपा सांसद एवं उनकी बुआ सुप्रिया सुले उनके साथ ईडी कार्यालय तक गई थीं। इस समय शरद पवार एवं सुप्रिया सुले संसद सत्र के लिए दिल्ली में हैं। लेकिन, गुरुवार को ईडी कार्यालय से कुछ ही दूर स्थित राकांपा कार्यालय में शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार मौजूद थीं। रोहित पवार उनका आशीर्वाद लेकर ही ईडी कार्यालय गए। राज्यभर से आए सैकड़ों राकांपा कार्यकर्ता भी राकांपा कार्यालय के अलावा ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद थे। वे रोहित के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे।

बंगाल में महिला बीड़ी श्रमिकों से मिले राहुल गांधी

- माकपा नेता भी राहुल की यात्रा में हुए शामिल

मुर्शिदाबाद जिले में गुरुवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला बीड़ी श्रमिकों से भेंट की। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची। यहां कांग्रेस समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल को देखने के लिए कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। राहुल ने शमशेरगंज के धुलियान इलाके में महिला बीड़ी श्रमिकों से जाकर मुलाकात की। राहुल ने बीड़ी बनाने वाली महिलाओं के साथ बैठकर काफी देर तक बातचीत की और उनका हाल जाना। यहां पर राहुल ने यह भी वादा किया कि अगर लोकसभा चुनाव में आइएनडीआइए गठबंधन की सरकार बनती है तो बीड़ी श्रमिकों की पीड़ा को कम करने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से पहल करेंगे। जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र से गुजरने के बाद न्याय यात्रा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के संसदीय क्षेत्र बहरमपुर में पहुंची। वहां भी भीड़ उमड़ी। मुर्शिदाबाद में राहुल की न्याय यात्रा में माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम, केंद्रीय समिति के सदस्य सुजन चक्रवर्ती सहित अन्य वामपंथी नेता भी शामिल हुए।

ममता ने कहा-अकेले लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस को अभी भी गठबंधन की आस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा-'2024 के लोकसभा चुनाव का सर्वोपरि उद्देश्य केंद्र से भाजपा की सरकार को हटाना है। गठबंधन में देने-लेने की प्रवृत्ति होती है। हम बंगाल में संयुक्त सीट-बंटवारे पर आम सहमति तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आइएनडीआइए ब्लाक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हम उनके इस रुख का स्वागत करते हैं।' यह बातें उन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कही। ममता के कांग्रेस पर माकपा के साथ मिलकर भाजपा के हाथ मजबूत करने के लगाए गए आरोप पर रमेश ने कहा-'मैंने उनका बयान सुना है, लेकिन यह उनकी राय को दर्शाता है, गठबंधन की सहमति को नहीं। तृणमूल और कांग्रेस, दोनों का भाजपा को हराने का साझा लक्ष्य है।'

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 2 फरवरी, 2024
आजकल
12
www.jagran.com

अमेरिका में आपराधिक जांच के लिए किया गया पालीग्राफ टेस्ट

1935 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार आपराधिक जांच में सहायता के लिए पालीग्राफ टेस्ट किया गया था। इसका आविष्कारक लियोनार्डो कीलर ने किया था। जिन दो संदिग्धों का परीक्षण किया गया, उन्हें बाद में पालीग्राफ टेस्ट के सबूतों के आधार पर दोषी घोषित कर दिया गया।

पहली बार एडविन एच लैंड ने किया तत्काल फोटोग्राफी का प्रदर्शन

1947 में आज ही के दिन एडविन एच लैंड ने आप्टिकल सोसाइटी आफ अमेरिका की एक बैठक में अपने आविष्कार पोलेराइड लैंड कैमरा से तत्काल फोटोग्राफी का पहला प्रदर्शन किया। इसे एक तस्वीर बनाने में लगभग एक मिनट का समय लगता था। कैमरे की कीमत 89 डालर थी।

आरएसएस और विहिप के आधार स्तंभ थे दादासाहब आप्टे

पत्रकार व हिंदू धर्म के समर्थक शिवराम शंकर (दादासाहब) आप्टे का जन्म 1905 में आज ही बड़ोदरा में हुआ था। पेशेवर जीवन की शुरुआत मुंबई हाई कोर्ट में वकालत से की। बाद में पत्रकारिता से जुड़ गए। 1964 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पहले महासचिव बने। उन्होंने विश्व भ्रमण कर हिंदू धर्म को दुनिया भर में फैलाने और वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रयास किया। कानून के जानकार होने के नाते संघ तथा विहिप का संविधान बनाने में भी अहम योगदान दिया। 10 अक्टूबर, 1985 को उनका निधन हो गया।

विज्ञानियों ने तैयार किया बंदर का क्लोन

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : चीन के विज्ञानियों ने दावा किया है कि उन्होंने रीसस मंकी का क्लोन तैयार कर लिया है। दो साल के इस बंदर का नाम 'रेट्रो' है। रेट्रो को तैयार करने के लिए उस तकनीक में बदलाव किया गया, जिससे डाली नाम की भेड़ का क्लोन बनाया गया था। विज्ञानियों को उम्मीद है कि इस तकनीक के सफल होने से उन्हें शोध में बंदरों के इस्तेमाल में लाभ मिलेगा। बंदरों को क्लोन करना बहुत मुश्किल माना जाता है, इसलिए विज्ञानियों की इस उपलब्धि को काफी बड़ा माना जा रहा है। शोध नेचर कम्यूनिकेशंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

- जिस तकनीक से डाली का क्लोन बनाया गया था, उसमें किया गया बदलाव
- शोध में बंदरों के उपयोग में मिलेगा लाभ

लंबे समय तक मिली विफलता के बाद बंदर की क्लोनिंग में मिली है सफलता। इंटरनेट मीडिया

भ्रूण को क्लोन की गई कोशिकाओं से बदला

विज्ञानियों को बरसों तक मिली विफलताओं के बाद यह सफलता मिली है। उन्होंने भ्रूण को क्लोन की गई कोशिकाओं से बदल दिया। विज्ञानियों को उम्मीद है कि नई तकनीक से वे एकदम समरूप रीसस मंकी बना पाएंगे। हालांकि दुनिया के अन्य विज्ञानियों का कहना है कि इस नए तरीके की सफलता की दर बहुत कम है। साथ ही विज्ञानियों के कुछ वर्ग ने नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। दुनिया में एक बड़ा वर्ग है, जो क्लोनिंग के विरोध में हैं और इसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ मानते हैं।

अब तक बनाए हैं 20 से ज्यादा जानवरों के क्लोन

अब तक 20 से ज्यादा जानवरों के क्लोन बनाए जा चुके हैं। 1996 में विज्ञानियों ने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नाम की तकनीक से डाली का क्लोन बनाया था। तब से अब तक कुत्ते, बिल्ली, सूअर और गाय समेत 20 से ज्यादा जानवरों के क्लोन बनाए जा चुके हैं। भारत में 2009 में एक भैंस का क्लोन बनाया गया था, लेकिन बंदर का क्लोन बनाने में विज्ञानियों को अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई थी।

क्लोन से तैयार डाली। फाइल

35 भ्रूणों में से एक बंदर का हुआ था जन्म, एक दिन बाद ही हो गई थी मौत

मुख्य शोधकर्ता कियांग सन ने शोध दल के साथ इस बात का गहन अध्ययन किया कि रीसस मंकी की क्लोनिंग में सफलता क्यों नहीं मिल रही? एक बार पहले भी इस बंदर के क्लोन का जन्म हुआ था। 35 भ्रूणों में से एक अकेला बंदर जन्मा था, लेकिन उसकी एक ही दिन में मौत हो गई थी। कियांग बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह थी कि क्लोन किए गए भ्रूण के प्लेसेंटा में गड़बड़ियां दिख रही थीं।

प्लेसेंटा बनाने वाली कोशिकाओं को ही बदल दिया

शोधकर्ताओं ने उन कोशिकाओं को ही बदल दिया जो बाद में प्लेसेंटा बनती हैं। ट्रोफोब्लास्ट नाम की ये कोशिकाएं एक स्वस्थ बंदर से ली गईं। ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्व सप्लाई करती हैं। ये पोषक तत्व ही भ्रूण को आक्सीजन और जरूरी तत्व उपलब्ध कराते हैं।

113 भ्रूणों में से सिर्फ एक ही बचा

स्पेनिश नेशनल सेंटर फार बायोटेक्नोलाजी के लुइस मोंटोलियू कहते हैं कि 113 भ्रूणों में से सिर्फ एक बचा है, यानी सफलता की दर एक प्रतिशत से भी कम है। इंसान का क्लोन बनाने के लिए बंदरों की अन्य प्राजियों के क्लोन बनाने होंगे।

इंसान की क्लोनिंग की जरूरत पर उठाया सवाल

मोंटोलियू का मानना है कि इन क्लोनिंग की कोशिशों में सफलता की कम दर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इंसान की क्लोनिंग ना सिर्फ गैरजरूरी, बल्कि विवादित भी है। अगर इसकी कोशिश भी की गई तो यह बेहद कठिन होगा। बंदर का क्लोनिंग करने वाले विज्ञानी कियांग खुद भी इंसान की क्लोनिंग के समर्थक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह अस्वीकार्य है।

इधर-उधर की

1,780 डालर में नीलाम हुआ 285 साल पुराना नींबू

नींबू पर लिखे संदेश से हुई तिथि की पहचान ● इंटरनेट मीडिया

लंदन, एजेंसी: इंग्लैंड में एक पुरानी अलमारी के दराज के पीछे मिला 285 साल पुराना नींबू 1,780 डालर यानी लगभग डेढ़ लाख रुपये में नीलाम हुआ। ब्रेटेल्स नीलामीकर्ताओं ने कहा कि एक परिवार द्वारा एक पुरानी अलमारी को नीलाम करने के लिए नीलामी घर में लाया गया था। परिवार के अनुसार अलमारी उनके मृत चाचा की थी। सारी प्रक्रिया सामान्य नीलामी की तरह ही था। जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीलामी से पहले एक विशेषज्ञ बिक्री के लिए रखी गई अलमारी की तस्वीर खींच रहा था, तभी दराज के पीछे एक नींबू दिखा। इसपर लिखा हुआ था, 'पी लू फ्रैंचिनी द्वारा चार नवंबर, 1739 को मिस ई बैक्सटर को दिया गया'। इसे देखकर नीलामी घर ने नींबू को भी बेचने का फैसला किया। जब इसकी 1,780 डालर की ऊंची बोली लगी तो अधिकारी भी हैरान रह गए। इस बीच अलमारी केवल 40 डालर में बिकी।

रूट कैनाल करने का तरीका बदला, न उपकरण टूटेंगे, न संक्रमण होगा

एक बार में ही हो पाएगा दांतों का संपूर्ण इलाज, खर्च भी 33 प्रतिशत तक होगा कम

आठ साल शोध के बाद विकसित की तकनीक, भारत सरकार ने दी मान्यता

अमित तिवारी, जमशेदपुर

दांतों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी और राहतभरी खबर है। अब रूट कैनाल कराते समय न तो फाइल (उपकरण) टूटने का डर होगा और न ही संक्रमण होने का खतरा। इतना ही नहीं, इलाज पर भी 33 प्रतिशत कम खर्च आएगा। इसे लेकर जमशेदपुर के दंत रोग विशेषज्ञ (माइक्रो-एंडोडोंटिस्ट) डा. सौरभ बनर्जी ने एक नई तकनीक खोजी है, जिसे भारत सरकार ने भी मान्यता दे दी है।

सीएचएफ (कन्सेप्चुअल हाइब्रिड फ्लेयर) नामक इस तकनीक को विकसित करने में आठ वर्ष लग गए। उनका दावा है कि देश में इस तरह की यह पहली तकनीक है। सीएचएफ तकनीक के कई फायदे हैं। इससे दांतों की उम्र बढ़ने के साथ-साथ रूट कैनाल की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आएगा।

सीएचएफ तकनीक में उपयोग होने वाला उपकरण। स्वयं

10% मरीजों के दांतों की नली में टूट जाते उपकरण

पारंपरिक पद्धति से रूट कैनाल करने के दौरान लगभग 10 प्रतिशत मरीजों के दांतों की नली में उपकरण टूट जाते हैं। इससे मरीज का समुचित इलाज नहीं हो पाता है और संक्रमण हो जाता है। इससे मरीज को सर्जरी के बाद दोबारा दर्द सहित अन्य परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन नई तकनीक में उपकरण टूटने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इलाज भी बेहतर होगा और दांतों की उम्र भी बढ़ेगी। चूंकि, इंफेक्शन अधिक होने की वजह से कई बार दांतों को निकालने की भी नौबत आ जाती है, लेकिन नई तकनीक से इलाज पूर्ण होने से इंफेक्शन होने का खतरा ही नहीं रहेगा। ऐसे में दांतों को निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

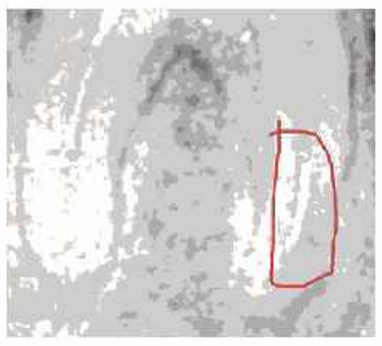

दांतों की नली में इस तरह टूट कर रह जाता है उपकरण या पिन। स्वयं

यह है सीएचएफ तकनीक

इस तकनीक में उपयोग होने वाला उपकरण स्टेनलेस स्टील व निकेल टाइटेनियम के मिश्रण से बना है। डा. सौरभ बनर्जी कहते हैं कि इस तकनीक के माध्यम से रूट कैनाल करने के तरीके को बदला गया है। पुरानी विधि में एक ही फाइल का उपयोग किया जाता है, जो दांतों की नली के अंतिम क्षोर तक जाता है, जिससे उपकरण टूट कर नली में फंसने का खतरा बना रहता है। नई तकनीक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें दांतों की घुमावदार नली को चिन्हित कर उसके अनुसार उसे अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। कई हिस्सों में बंटने से घुमावदार भाग छोटे हो जाते हैं, जिससे उपकरण टूटने की संभावना शून्य हो जाती है। सीएचएफ तकनीक में 10 स्टेप बनाए गए हैं, जिसका पालन करना होता है।

काफी शोध के बाद सीएचएफ तकनीक विकसित किया गया है। इसकी मान्यता के लिए भारत सरकार के कापीराइट कार्यालय को आवेदन किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस तकनीक से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा।

– डा. सौरभ बनर्जी, माइक्रो एंडोडोंटिस्ट

लाइट और संगीत का संगम

लंदन के सेंट मार्टिन इन फील्डस चर्च में ब्रिटिश स्थापना कलाकार पीटर वाकर द्वारा इमर्सिव लाइट्स और साउंड के समन्वय से इंस्टालेशन आर्ट 'ओपनिंग नाइट आफ लाइट' प्रदर्शित की गई। इमर्सिव लाइट समकालीन कला है, जो व्यक्तिपरक अहसास दिलाती है और अधिक प्राकृतिक लगती है। एएफपी

फेसबुक और इंस्टा से 2.6 करोड़ से अधिक कंटेंट हटाए गए

नई दिल्ली, आइएएनएस : मेटा ने कहा कि उसने दिसंबर 2023 में भारत में फेसबुक से 19.8 मिलियन से अधिक और इंस्टाग्राम से 6.2 मिलियन से अधिक कंटेंट हटा दिए हैं। एक से लेकर 31 दिसंबर के बीच फेसबुक को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 44,332 रिपोर्टें प्राप्त हुईं। मेटा ने कहा कि 33,072 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल प्रदान किए गए। विशेष समीक्षा कर 11,260 में से 6,578 रिपोर्टों पर कार्रवाई की गई। वहीं, 4,682 रिपोर्टों पर समीक्षा के बाद कार्रवाई नहीं की गई। इंस्टाग्राम पर कंपनी को 19,750 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 9,555 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल प्रदान किए गए। अन्य 10,195 रिपोर्टों में से 6,028 रिपोर्टों पर कार्रवाई की गई। शेष पर कार्रवाई न की गई। नए आइटी नियम 2021 के तहत पचास लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय

न्यूज गैलरी

कनाडा में गिरफ्तार भारतवंशी अमेरिका प्रत्यर्पित होंगे

टोरंटो : कनाडा में गिरफ्तार तीन भारतवंशियों 25 वर्षीय आयुष शर्मा और 60 वर्षीय गुरअमृत सिद्धू और कैलगरी से 29 वर्षीय सुभम कुमार को मेक्सिको और उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच ड्रग्स की तस्करी करने वाले नेटवर्क से कथित संबंधों के लिए अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जाएगा। एफबीआइ और रायल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के बीच संयुक्त अभियान ने संगठित अपराध गिरोह में कथित भूमिका के लिए 19 लोगों को आरोपित किया है। (आइएएनएस)

विधानमंडल पर हुए हमले में अभिनेता ग्रेगरी सहित चार दोषी

हांगकांग : हांगकांग की एक अदालत ने वर्ष 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान विधान परिषद की इमारत पर हुए हमले में गुरुवार को अभिनेता ग्रेगरी वोंग सहित चार लोगों को दोषी ठहराया। इस दौरान हुई क्षति की मरम्मत पर लगभग 4.6 मिलियन डालर खर्च हुए थे। अभिनेता ग्रेगरी वोंग और दो पत्रकारों वोंग का-हो और मा काई-चुंग सहित छह प्रतिवादियों ने पिछले साल दंगों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। छह प्रतिवादियों में से चार को दंगे का दोषी पाया। (एपी)

ईरान में मारे गए नौ नागरिकों के शव एयरलिफ्ट किए गए

इस्लामाबाद : ईरान में गोलीबारी में मारे गए नौ नागरिकों के शव को एयरलिफ्ट कर पाकिस्तान लाया गया। इन सभी श्रमिकों को 27 जनवरी को पाकिस्तानी सीमा के पास ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। (प्रेट्र)

अमेरिका में युवक ने पिता का सिर काटा, वीडियो प्रसारित

वाशिंगटन : अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक युवक ने अपने पिता माइकल एफ. मोहन का सिर काट दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित ने सिर को हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित किया। नेशनल गार्ड की महिला प्रवक्ता ने बताया कि हत्या के कुछ घंटे बाद ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। 14 मिनट के प्रसारित वीडियो में पिता को गद्दार बताया। (प्रेट्र)

अमरिका ने एच-1बी, ईबी-5 व एल-1 वीजा शुल्क में की भारी बढ़ोतरी

- ये गैर-आप्रवासी वीजा श्रेणियां भारतीयों में हैं काफी लोकप्रिय
- संघीय अधिसूचना के अनुसार, एक अप्रैल से प्रभावी होगी वृद्धि

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिकी ने गैर-आप्रवासी वीजा की विभिन्न श्रेणियों में भारी शुल्क वृद्धि की घोषणा की है। इसमें भारतीयों में लोकप्रिय एच-1बी, ईबी-5 और एल-1 वीजा शामिल हैं। फीस बढ़ोतरी आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी।

बुधवार को जारी संघीय अधिसूचना के अनुसार, एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क के लिए अब 460 डालर की जगह 780 डालर का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार एच-1बी पंजीकरण शुल्क 10 डालर से बढ़ाकर 215 डालर कर दिया गया है, लेकिन यह अगले वर्ष से लागू होगा। इसी तरह एल-1 वीजा शुल्क 460 डालर से बढ़ाकर 1,385 डालर कर दिया गया है। इसके साथ ही निवेशकों के वीजा के रूप में जाना जाने वाला ईबी-5 के लिए शुल्क 3,675 डालर से बढ़ाकर 11,160 डालर कर दिया गया है। 2016 के बाद शुल्क वृद्धि पहली बार एक अप्रैल से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को तकनीकी रूप से

प्रशिक्षित विदेशी पेशेवरों को नियुक्ति की अनुमति देता है। इसी तरह एल-1 वीजा जो इंट्राकंपनी डिजाइन किया गया है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनके विदेशी कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है। वहीं, ईबी-5 प्रोगाम को अमेरिका ने 1990 में लांच किया था, जिसमें अमेरिकी बिजनेस में पांच लाख डालर का निवेश कर आवेदक अमेरिकी वीजा प्राप्त कर सकता है।

यूक्रेन को 50 अरब यूरो का नया सहायता पैकेज देगा ईयू

ब्रसेल्स, एपी: यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल 27 देशों के नेताओं ने हंगरी की धमकी के बावजूद गुरुवार को यूक्रेन को 50 अरब यूरो (54 अरब डालर) का नया सहायता पैकेज देने के समझौते पर मुहर लगा दी। सहायता पैकेज देने पर आपत्ति जताते हुए हंगरी ने वीटो का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। ब्रसेल्स में नेताओं के शिखर सम्मेलन के एक घंटे बाद ही यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने एक्स पर समझौते को लेकर जानकारी दी।

रूस ने किया अमेरिकी मिसाइल से सैन्य विमान गिराने का दावा

मास्को, रायटर: रूस ने गुरुवार को दावा किया कि यूक्रेन ने गत सप्ताह रूसी सैन्य विमान (Il-76) को जमीन से हवा में मार करने वाली अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों से गिराया था। गत 24 जनवरी को रूस का सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसमें सवार 65 युद्धबंदियों समेत 74 लोगों की मौत हो गई थी।

भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचेगा अमेरिका

- रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बिक्री को मंजूरी देने की घोषणा की
- मानवरहित निगरानी और टोही गश्त सक्षम बनाने में मदद करेगा

अमेरिका के जनरल एटामिक्स एयरोनाटिकल सिस्टम्स इंक. (जीए-एएसआइ) का एमक्यू-9बी ड्रोन। प्रेट्र

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका ने गुरुवार को भारत को 3.99 अरब डालर की अनुमानित लागत वाली 31 एमक्यू-9बी प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। एक अमेरिकी रक्षा एजेंसी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। प्रस्तावित मेगा ड्रोन सौदे की घोषणा जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी।

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि विदेश विभाग ने एमक्यू-9बी रिमोटली पायलटेड विमान और संबंधित उपकरणों की भारत सरकार को संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा कि उसने गुरुवार को कांग्रेस को इस संभावित बिक्री के बारे में सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणीकरण दे दिया है। यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका-भारत के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षा भागीदार की सुरक्षा में सुधार करने में मदद कर अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी। जो हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत है।

सौदे के तहत भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लांग एंड्योरेंस यूएवी मिलेंगे, जिनमें से नौसेना को 15 सीगार्जियन, जबकि सेना और वायु सेना को आठ-आठ स्काईगार्जियन वाले वर्जन उपलब्ध कराए जाएंगे।

मालदीव के महाभियोजक पर हमले के सिलसिले में दो गिरफ्तार

माले, प्रेट्र : मालदीव के महाभियोजक पर हमले में गुरुवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में उनके हाथों में फ्रैक्चर आ गया था। इसे सुनियोजित हमला बताया गया है। इस घटना के बाद से सरकार और विपक्षी दलों के बीच टकराव शुरू हो गया है। महाभियोजक हुसैन शमीम पर बुधवार सुबह उस समय हमला किया गया जब वह जागिंग करने गए थे। दो बाइक सवारों ने उनपर हमला बोला था। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह एक सुनियोजित हमला था। हमलावरों ने अपना चेहरा ढंक रखा था, जिससे उनकी पहचान न हो सके। हालांकि, उन्होंने उनके संबंध में अतिरिक्त जानकारियां देने से मना कर दिया है। पुलिस का मानना है कि इस हमले में अन्य लोगों की भागीदारी हो सकती है। अस्पताल में इलाज के बाद शमीम ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट की। पोस्ट में कहा कि काम पर मजबूती से वापस लौटूंगा।

फलस्तीन की मदद करना जारी रखेगा भारत : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, एएनआइ: गत सात अक्टूबर को हमास के हमले में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के कर्मचारियों के शामिल होने के इजरायल के आरोप के बाद विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत फलस्तीन की द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र दोनों माध्यमों से मदद जारी रखेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति देश की जीरो टोलरेंस की नीति है। इजरायल ने आरोप लगाया था कि यूएनआरडब्ल्यूए के कर्मचारी बंधकों का अपहरण करने और आपरेशन रूम तैयार करने जैसी गतिविधियों में भी शामिल थे। साप्ताहिक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आतंकी हमले में यूएनआरडब्ल्यूए के कर्मचारियों के शामिल होने के इजरायल के आरोपों पर चिंता जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत फलस्तीन के लिए महत्वपूर्ण विकास भागीदार है।

गाजा को लेकर पेरिस समझौता प्रस्ताव पर असमंजस में हमास

- कहा, सभी बिंदुओं पर कर रहे विचार, जल्द देंगे प्रतिक्रिया
- फलस्तीनी अधिकारी ने कहा, प्रस्ताव खारिज नहीं करेगा हमास

गाजा पट्टी के खान यूनिस से बड़ी संख्या में फलस्तीनी पलायन कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। एएफपी

यरुशलम, रायटर: गाजा में स्थायी संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। एक फलस्तीनी अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि इस सप्ताह मिले पेरिस समझौता प्रस्तावों को हमास द्वारा अस्वीकार किए जाने की आशंका नहीं है। लेकिन इजरायली बलों की गाजा से वापसी के आश्वासन के बिना इसपर उसके हस्ताक्षर की संभावना भी नहीं है। हमास ने कहा है वह सभी बिंदुओं पर विचार कर रहा है, जल्द ही प्रतिक्रिया देगा।

कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने इस सप्ताह हमास को गाजा में युद्ध रोकने को लेकर पहला ठोस समझौता प्रस्ताव दिया था। इस पर पिछले सप्ताह पेरिस में अमेरिका और इजरायल ने सहमति जताई थी। पेरिस प्रस्ताव के तहत पहले चरण की 40 दिनों में पूरा होने की परिकल्पना है। इस दौरान युद्ध विराम रहेगा और हमास को शेष बचे 100 से अधिक बंधकों में से नागरिकों को रिहा करना होगा। इसके बाद अगले चरण में इजरायली सैनिकों की रिहाई और मृत बंधकों के शव सौंपने होंगे।

फलस्तीनी अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, उम्मीद है कि हमास प्रस्ताव को खारिज नहीं करेगा, लेकिन यह हो सकता है कि कोई निर्णायक सहमति भी न दे।

अदन की खाड़ी में हाउती हमले को अमेरिका ने किया नाकाम

वाशिंगटन, रायटर: ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में बुधवार को पोत रोधी तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिसे अमेरिकी नौसेना के मिसाइल विध्वंसक यूएसएस कार्नी ने सफलतापूर्वक मार गिराया। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि इसके साथ ही यमन में ईरान समर्थित हाउती यूएवी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर अमेरिका ने हमले किए। यहां 10 हाउती वन-वे यूएवी हमले की तैयारी कर रहे थे। कहा, उसने यह हमला आत्मरक्षा के लिए किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि 31 जनवरी को स्थानीय समय सुबह लगभग साढ़े आठ बजे ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों ने यमन के हाउती-नियंत्रित क्षेत्रों से अदन की खाड़ी की ओर एक पोत-रोधी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे अमेरिका ने मार गिराया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरानी सैनिकों और सुविधा समेत कई लक्ष्यों पर बहुदिवसीय हमलों की योजना को अनुमति दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने वापस की इमरान की याचिका, कहा-दूर करें कमियां

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की उस याचिका को वापस कर दिया है, जिसमें उन्होंने पंजाब की दो नेशनल असेंबली सीट से अपने नामांकन को खारिज करने को चुनौती दी थी। गुरुवार को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान में आम चुनाव आठ फरवरी को होने हैं। जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के संस्थापक इमरान खान का नामांकन पत्र पिछले महीने खारिज कर दिया गया था। उन्होंने पंजाब के लाहौर और मियांवाली जिले के दो निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किया था, जिसे तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने और नैतिक आधार पर निरस्त कर दिया गया था। क्रिकेटर से राजनेता बने पूर्व पीएम ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें दोनों निर्वाचल क्षेत्रों से लड़ने की अनुमति

पूर्व पीएम ने नामांकन खारिज होने को दी थी चुनौती

देने का अनुरोध किया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों ने उसी दिन वापस करते हुए कहा कि वह एक पखवाड़े के भीतर कमियों को दूर कर पुनः याचिका दाखिल करें।

पीटीआइ के केंद्रीय कार्यालय पर पुलिस का कब्जा : गुरुवार को डान अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि बिना वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने पार्टी के इस्लामाबाद स्थित केंद्रीय कार्यालय पर नियंत्रण कर लिया और पार्टी सदस्यों का इसमें प्रवेश बंद कर दिया। इसके बाद आम चुनाव को लेकर होने वाली बैठक वर्चुअल आयोजित की गई। दूसरी ओर, पीटीआइ ने घोषणा की कि वह पार्टी के अंदर चुनाव पांच फरवरी को आयोजित करेगी।

****